

In Pursuit of Truth

वर्ष: 21 | अंक: 08
16 से 31 जनवरी 2023
पृष्ठ: 48
मूल्य: 25 रु.

आक्स

पाक्षिक



देश का हॉट स्पॉट बना मध्य प्रदेश

प्रवासी, ग्लोबल समिट और खेलो
इंडिया ने बढ़ाई मप्र की साख

चुनावी साल में भाजपा के लिए संजीवनी
बनेंगे ये बड़े आयोजन



नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री



शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

अद्भुत मध्यप्रदेश



श्री महाकाल महालोक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा
भव्य-दिव्य लोकार्पण

चीतों की वापसी

70 साल बाद कूनो अभयारण्य में
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा चीतों का पुनर्स्थापन

पेसा नियम

जनजातीय समुदाय को जल, जंगल, ज़मीन, मजदूरों,
महिलाओं व संस्कृति संरक्षण के अधिकार

रोज़गार

एक लाख शासकीय पदों पर भर्तियां जारी, युवाओं को
प्रतिमाह 2 लाख से अधिक स्व-रोज़गार के अवसर

माफिया पर कार्रवाई

23 हजार एकड़ ज़मीन मुक्त कराई,
बनेंगे गरीबों के घर

मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान

83 लाख से अधिक हितग्राही
विभिन्न योजनाओं से जुड़े

स्वच्छ भारत मिशन

शहरी और ग्रामीण स्वच्छता में अग्रणी,
इंदौर लगातार 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर

नववर्ष में प्रवासी भारतीय दिवस, ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट,
खेलो इंडिया यूथ गेम्स और जी-20 बैठकों का आयोजन

— आइये, विकास के नये अध्याय जोड़ें —

● इस अंक में

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

वल्लभागाथा

9 | 14 हजार में कुर्सी भी नहीं मिली...!

प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में संपन्न 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में विदेश से आए हजारों प्रवासी भारतीयों ने 14 हजार रुपए में रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें सिर्फ लंच और डिनर शामिल था, बाकी लाखों...

राजपथ

10-11 | कमजोर विधायकों...

2023 में मप्र सहित 9 राज्यों में चुनाव होना है। राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। मप्र में विधानसभा चुनाव होने में अब एक साल से भी कम का समय रह गया है। ऐसे में प्रदेश का राजनीतिक माहौल गर्म होने...

भरशाही

13 | हाईकोर्ट के आदेश नहीं...

मप्र में एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुशासन की बातें करते थकते नहीं हैं, वहीं दूसरी तरफ स्थिति यह है कि सरकारी अफसर आम आदमी तो छोड़िए हाईकोर्ट तक की नहीं सुनते हैं। इसका अंदाजा अवमानना के मामलों के...

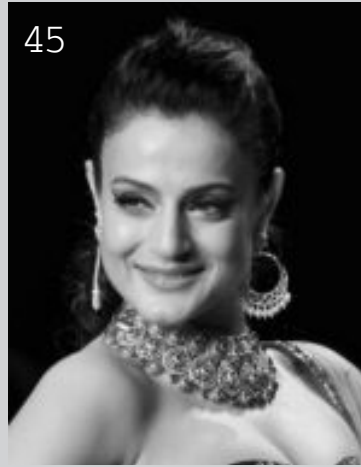
विडंबना

15 | सीमेंट कंपनियों को बेची जा...

मप्र पावर जनरेटिंग कंपनी के ताप विद्युत गृह में कोयले की राखड़ का निष्पादन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार फ्लाई ऐश का उपयोग सड़कों और भवनों के निर्माण में किया जाना चाहिए, लेकिन ताप विद्युत गृहों से निकलने वाली राख सीमेंट कंपनियों को बेची जा...



संघ की प्रयोगशाला के बहुतेरे प्रयोगों के हिसाब से मप्र भाजपा के लिए सबसे ज्यादा मुफीद रहा है। इस कारण किसी न किसी बहाने यहां संघ, विहिप से लेकर प्रमुख अनुषांगिक संगठनों के बड़े आयोजन सरकारी और गैरसरकारी माध्यमों से होते रहते हैं। इनका अपरोक्ष फायदा सरकार को मिलता है। वहीं चुनावी साल में मप्र में प्रवासी भारतीय सम्मेलन, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जी-20 देशों के सम्मेलन का आयोजन मप्र में किया जा रहा है।



राजनीति

30-31

2024 के लिए...

राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो पदयात्रा के जरिए और कुछ किया हो या न किया हो, दो काम तो सफलतापूर्वक कर दिए हैं। पहला यह कि वह पप्पू वाली छवि से बाहर निकल आए हैं और खुद को पूर्णकालिक राजनीतिज्ञ के तौर पर स्थापित किया है। दूसरा काम यह किया है कि उन्होंने...

महाराष्ट्र

35 | महाराष्ट्र और कर्नाटक...

महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच रात ठनी हुई है। दोनों सरकारों के मुखिया, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई और महाराष्ट्र के असली मुख्यमंत्री, वैसे उपमुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस सार्वजनिक रूप से एक दूजे को ललकार रहे हैं। बात पुलिस तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र भाजपा...

बिहार

38 | क्या गुल खिलाएंगे...

प्रशांत किशोर अब तक पूरे देश में एक जाना पहचाना नाम बन चुके हैं। एक अंग्रेजी अखबार के ऑनलाइन साक्षात्कार में पत्रकार ने उन्हें बताया कि उनको सुनने और पढ़ने वालों में सिर्फ हिंदी पट्टी के लोग ही नहीं हैं। उनके साक्षात्कारों को दक्षिण भारत में भी खूब...

6-7 अंदर की बात

39 पड़ोस

41 विदेश

42 महिला जगत

44 खेल

45 फिल्म

46 व्यंग्य



अच्छी शिक्षा के लिए भी कभी तो कोई आंदोलन करता?

शिक्षक का हमारी जिंदगी में क्या महत्व है, इस पर किसी ने क्या खूब लिख है...

गुरु की करके वंदना, बदल भाग्य के लेख।

बिना आंख के सूर ने, कृष्ण लिए थे देख।।

लेकिन विडंबना यह है कि वर्तमान में शिक्षक केवल स्वार्थी बनकर रह गए हैं। शिक्षक बनकर वे शिक्षा के उत्थान के लिए बड़ी-बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि शिक्षण से उनका असरोकार धीरे-धीरे कम होता जाता है। मद्र में तो शिक्षक का नाम सामने आते ही धरना, प्रदर्शन, आंदोलन आदि की याद आने लगती है। दरअसल, मद्र में शिक्षक निरंतर आंदोलनरत रहते हैं। कभी वेतन, कभी सुविधा, कभी पदोन्नति, तो कभी अन्य कारणों से। इसका अक्सर यह हो रहा है कि सरकार के लापरवाही के बाद भी प्रदेश में शिक्षा का स्तर निम्न स्तर पर ही है। दरअसल, इस देश में सरकारें शुरू से शिक्षा के साथ खिलवाड़ करती आई हैं। शिक्षामित्रों के साथ हमें सहानुभूति है। उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए, वेतन मिलना चाहिए। वे नौकरी और वेतन के लिए ही सड़क पर उतरे हैं, शिक्षा के लिए नहीं। शिक्षा के लिए कोई सड़क पर नहीं उतरता। शिक्षक न सरकार, स्कूल न अभिभावक। सब उसके साथ खिलवाड़ करते हैं। सरकारी स्कूल खिलवाड़ हैं। मुफ्त की कॉपी-किताबें-बस्ता-ड्रेस-मध्याह्न भोजन आदि खिलवाड़ के अलावा और क्या हैं। इन सबसे बच्चे कैसी शिक्षा पा रहे हैं। कक्षा पांच का बच्चा कक्षा दो का खाल हल नहीं कर पाता। स्कूल में दिन में खाना मिलेगा, इसलिए स्कूल जाओ। शिक्षा मिलेगी, इसलिए नहीं। भोजन के बहाने बच्चों को स्कूल बुलाना एक तरीका हो सकता है, लेकिन उसमें पेट की भूख बड़ी हो जाती है, शिक्षा की भूख गायब। मध्याह्न भोजन के कीड़े अक्सर खबरों में दिखते हैं। शिक्षा में पड़े कीड़े किसी को दिखते नहीं। कोई शायद ही उन्हें देखना चाहता हो। महंगे, पंचतारा निजी स्कूल और भी बड़ा खिलवाड़ हैं। वे वंचित बच्चों के लिए सबसे बड़ी ईर्ष्या हैं। उनके मुंह पर तमाचा हैं। सरकारी स्कूलों और पंचतारा निजी स्कूलों के बीच स्कूलों की विविध श्रेणियां हैं। वहां अभिभावकों की सामाजिक-आर्थिक औकात का भौंडा प्रदर्शन होता है। रिजल्ट में डिवीजन और नंबरों के प्रतिशत की प्रतियोगिता होती है। ज्यादातर बच्चों के हिस्से कुंठा आती है। इन स्कूलों से निकले बच्चे कैसे पढ़े-लिखे नागरिक बनते हैं, हम सब उसके गवाह हैं। इस देश की संसद ने सबको शिक्षा का अधिकार भी दे ही दिया है। शिक्षा पाना हर बच्चे का अधिकार बन गया है। यह अपने आप में कम बड़ा मजाक नहीं। संविधान ने बहुत सारी चीजें हमें बतौर नागरिक दे रखी हैं, लेकिन किससे पूछें कि वे मिलती क्यों नहीं और मिलती हैं तो कितनी और किस रूप में। शिक्षा के अधिकार के तहत हर निजी स्कूल को कुछ सीटों पर गरीब बच्चों को दाखिलना देना जरूरी है। शिक्षा के लिए गरीब और अमीर बच्चों का भेद क्यों होना चाहिए, हमें तो यही समझ में नहीं आता। चलिए, होता है तो महंगे निजी स्कूल गरीब बच्चों को दाखिलना देने से ही इनकार कर देते हैं। प्रशासन का डंडा चलने पर दाखिलना दे देते हैं, लेकिन उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार करते हैं। उन्हें अमीर बच्चों के साथ नहीं बैठाते। उनके लिए अलग समय पर अलग कक्षा चलाते हैं। शिक्षक-शिक्षिका भी उनके लिए स्तरीय नहीं होते। उन्हें किसी तरह पढ़ते हुए दिखाना होता है। औपचारिकता पूरी करनी होती है। ये बच्चे कैसी शिक्षा पा रहे होंगे, कैसी कुंठा उनके मन में भर रही होगी। अवैधानिक अधिकार के नाम पर इन बच्चों के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है।

- राजेन्द्र आगाल

आक्षर

वर्ष 21, अंक 8, पृष्ठ-48, 16 से 31 जनवरी, 2023

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :

प्लॉट नम्बर 150, जेन-1 मनोरमा कॉम्प्लेक्स,

एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर

भोपाल- 462011 (म.प्र.),

फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788

email : akshmagazine@gmail.com

Website : www.akshnews.com

RNI NO. HIN/2002/8718

MPHPL/642/2021-23

ब्यूरो

कोलकाता:- इंद्रकुमार, छत्तीसगढ़:- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी,

जयपुर:- आर.के. बिनानी, लखनऊ :- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संपादकता

094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे

098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया

094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार

098934 77156, (गंजबासौदा) ज्योत्सना अनूप यादव

089823 27267, (रतलाम) सुभाष सोमानी

075666 71111, (विदिशा) मोहित बंसल

क्षेत्रीय कार्यालय

नई दिल्ली : ईसी 294 माया इन्क्लेव मायापुत्री

फोन : 9811017939

जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान)

मोबाइल-09829 010331

रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर,

फोन : 0771 2282517

भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर,

भिलाई, मोबाइल 094241 08015

इंदौर : नवीन खुशवंशी, खुशवंशी कॉलोनी, इंदौर,

मो.-9827227000

देवास : जय सिंह, देवास

मो.-7000526104, 9907353976

स्वातंत्र्याधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 150, जेन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा कॉम्प्लेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।



आगे आएँ युवा

प्रदेश सहित देशभर की राजनीतिक पार्टियों को युवाओं को आगे लाना चाहिए। उनके जुनून को राजनीति में इस्तेमाल करना चाहिए। युवाओं को भी राजनीति में इंटरैक्ट लेना चाहिए। और अनुभवी नेताओं से सीखकर देश के विकास में योगदान देना चाहिए।

● अनिल शर्मा, भोपाल (म.प्र.)

चुनावी माहौल

इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियाँ मजबूती से तैयारी में जुटी हुई हैं। पार्टियों को गरीबी, बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों पर काम करना चाहिए। किसानों के लिए भी राजनीतिक पार्टियों को आगे आना चाहिए।

● जाकिर खान, ग्वालियर (म.प्र.)

सख्त हो सरकार

प्रदेश में सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त है लेकिन अभी भी कई सरकारी विभागों में अधिकारी-कर्मचारी रिश्वत लेकर काम कर रहे हैं। सरकार को ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। ताकि आम आदमी को अधिक परेशान न होना पड़े।

● प्रद्युम्न मिश्रा, राजगढ़ (म.प्र.)



कोरोना के साथ आर्थिक हालातों के लिए बनें मजबूत

देश की अर्थव्यवस्था पर मंदी के साथ-साथ कोविड की लहर ने एक बार फिर हमला बोल दिया है। यदि हमें फिर पाबंदियाँ लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता है तो इससे एक बार फिर देश के आम लोगों को परेशानी हो सकती है। इसलिए हमें कोरोना के साथ-साथ आर्थिक हालातों से भी लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। पिछली सदी के आठवें दशक की मंदी के समय कंपनियों के शेयरों के दाम उनकी आमदनी के औसतन आठ गुना थे। आज उनके दाम आमदनी के बीस गुना के पास हैं। इसका बरतार यह है कि महंगाई और मंदी की आहट सुनते ही शेयर बाजारों में हड़कंप मच सकता है और दाम आधे तक हो सकते हैं।

● दीक्षा वर्मा, जबलपुर (म.प्र.)

बिजली का भार

म.प्र. में उपभोक्ताओं को महंगी बिजली मिल रही है। इस महंगाई के दौर में बिजली की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। नए साल में गैर जरूरी करार का भार प्रदेश के उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। इससे उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ रहा है। सरकार को आम आदमी की समस्याओं को देखते हुए बिजली के क्षेत्र में कुछ आवश्यक कदम उठाने चाहिए। जिससे उस पर भार न पड़ सके।

● मिहिर खोलकी, रायसेन (म.प्र.)



शिक्षा का स्तर ऊंचा हो

म.प्र. की शिवराज सरकार को प्रदेश के बच्चों की शिक्षा को और अधिक आधुनिक करने का प्रयास करना चाहिए। इससे बच्चों में इंटरैक्ट भी जगेगा। प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई की स्थिति क्या है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अकेले भोपाल में वर्षभर के भीतर 12 से अधिक कार्यक्रम हुए हैं, जिनमें विद्यार्थी और बच्चों को शामिल होना पड़ा है। बाकी के अधिकतर शिक्षक बीएलओ इयूटी कर रहे हैं और पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

● शालिनी खोनी, इंदौर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल



आचार्य ने बढ़ाया पारा

राजस्थान कांग्रेस में सियासी बयानबाजी और नेतृत्व बदलने की चर्चाएं भले ही शांत हो गई हों लेकिन इशारों-इशारों में निशाना साधने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस नेता और सचिन पायलट के करीबी कहे जाने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम् के एक ट्वीट ने फिर सियासी गलियारों में अटकलों को हवा दे दी है। आचार्य ने हाल में ट्वीट किया कि राजतिलक की तैयारी है, पर अभी जंग जारी है। प्रियंका गांधी के सलाहकार आचार्य प्रमोद के ट्वीट के बाद सूबे में एक बार फिर चेहरा बदलने की चर्चाओं को बल मिला और कयास लगाए जाने लगे हैं कि राज्य में जल्द ही कोई बड़ा फैसला हो सकता है। दरअसल, आचार्य प्रमोद कृष्णम् का जन्मदिन था। इस मौके पर भरतपुर से मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध सिंह ने उन्हें ट्वीट कर बधाई दी थी जिसको स्वीकार करते हुए आचार्य ने लिखा कि मुराद पूरी होने का समय आ गया है अनिरुद्ध, खुश रहो। वहीं आचार्य प्रमोद ने अपने जन्मदिन पर सचिन पायलट की बधाई देने के जवाब में कहा कि राजतिलक की तैयारी है, पर जंग अभी भी जारी है, बहुत-बहुत साधुवाद। आचार्य के इन दोनों ही ट्वीट के बाद राजनीतिक हलकों में कई तरह के मायने निकाले जाने लगे हैं। गौरतलब है कि आचार्य सचिन पायलट समर्थक माने जाते हैं और वह कई मौकों पर पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी कर चुके हैं।

उपजातियों के विभाजन की चिंता

अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां इसकी तैयारी में अभी से जुट गई हैं। इसके लिए जहां कांग्रेस की 'भारत जोड़ो यात्रा' जारी है, वहीं भाजपा के दिग्गज नेता राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इस बीच केंद्र से मंजूरी नहीं मिलने के बाद बिहार में राज्य सरकार ने अपने बजट से जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला लिया है। इसमें जातियों के साथ-साथ आर्थिक स्थिति का भी पता लगाया जाएगा। जाति आधारित जनगणना शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सिर्फ जातियों की गिनती होगी, उपजातियों को नहीं गिना जाएगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि जिस तरह से भाजपा को हिंदू समाज के भीतर जातियों के विभाजन की वजह से जातिगत जनगणना कराने से दिक्कत है, वैसे ही नीतीश कुमार को उपजातियों के विभाजन की चिंता है। बिहार में अब जाति की राजनीति निचले स्तर तक चली गई है। हर क्षेत्र में एक ही जाति के कई उम्मीदवार खड़े होते हैं और फिर उपजातियों के आधार पर वोट मांगने जाते हैं, अगर उपजातियों की गिनती होती है तो सत्ता या पार्टियों की शीर्ष पर बैठे कई नेता कम आबादी वाली उपजाति के प्रतिनिधि निकलेंगे और तब दूसरी उपजातियों से उनके खिलाफ आवाज उठ सकती है।



रार नई ठांंगा

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ फिर सुर्खियों में हैं। उपराष्ट्रपति बनने के बाद से धनखड़ ने न्यायपालिका के खिलाफ हल्ला बोल रखा है। खासकर सुप्रीम कोर्ट को लेकर वे लगातार मुखर हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे तो सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उनके रिश्ते लगातार कटुता भरे ही बने रहे। तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें केंद्र सरकार और भाजपा का एजेंट बताते हुए राज्यपाल पद से हटाने की मांग तक कर डाली थी। अफसरों को राजभवन में तलब करने का भी उन्होंने नया प्रयोग शुरू किया था। कई बार ममता समर्थकों ने यहां तक भी आरोप लगाए थे कि राज्यपाल खराब कानून व्यवस्था बताकर सूबे की निर्वाचित सरकार को बर्खास्त कराने की जुगत में हैं। बहरहाल, उनके उपराष्ट्रपति बन जाने और उनकी जगह सीवी आनंद बोस के पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बन जाने के बाद ममता बनर्जी ने राहत की सांस ली है। उपराष्ट्रपति का पद वैसे तो संवैधानिक है और इस नाते अतीत में किसी उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट की ऐसी आलोचना नहीं की जैसी धनखड़ लगातार कर रहे हैं। इससे पहले कानून मंत्री किरण रिजजू थे इसी राह पर। पर उन्हें तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके पद का वास्ता देकर नसीहत दे डाली थी। वे तो संभल गए पर धनखड़ लगातार आक्रामक हैं।

राहुल का चल-चित्र

राहुल गांधी को भी भरोसा नहीं रहा होगा कि भारत जोड़ो यात्रा को अपार जनसमर्थन मिलेगा। यात्रा ने राहुल गांधी की गंभीर नेता की छवि बना दी है। कांग्रेस के नेता कह भी रहे हैं कि भाजपा ने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर राहुल की जो छवि बिगाड़ी थी, कड़ाके की ठंड में केवल एक टी-शर्ट में अपनी अब तक की तीन हजार किलोमीटर से ज्यादा की पदयात्रा से उसे एक झटके में धो दिया। यात्रा को उग्र में महज तीन दिन तक ही सीमित रखने पर भी खूब नुक्ता चीनी सुनाई पड़ी। पर, कांग्रेसियों का कहना है कि एक चक्र में सारे देश की पदयात्रा संभव नहीं। यह कन्याकुमारी से कश्मीर यानी दक्षिण से उत्तर की यात्रा है। इसके बाद संसद का बजट सत्र भी है। लिहाजा यात्रा को जनवरी में खत्म करना मजबूरी थी। जयराम रमेश ने फरमाया है कि हो सकता है कि अगली यात्रा पूरब से पश्चिम की निकालें। राजनीतिक यात्राओं के इतिहास में राहुल गांधी इतनी लंबी दूरी की पैदल यात्रा करने वाले पहले नेता बन गए हैं।

मुश्किल डगर

भाजपा ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। दक्षिण के इसी एक राज्य में सत्ता का सुख मिला है इस पार्टी को। यहां भाजपा पहली बार 2008 में सत्ता में आई थी। 224 सदस्यीय विधानसभा में उसे 110 सीटें ही मिली थी। विरोधी कांग्रेस 80 और एचडी देवगौड़ा का जनता दल 28 सीटों पर ही सिमट गए थे। दोनों मिलकर भी भाजपा से पीछे थे। भाजपा ने निर्दलियों के समर्थन से चलाई थी सरकार। इसी दौरान बीएस येदियुरप्पा भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरने के कारण इस्तीफा देने को भी मजबूर हुए थे। अगले चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा का डिब्बा गोल कर दिया। भाजपा को महज 40 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। कांग्रेस ने 122 सीटों के साथ पूरे पांच साल चलाई थी सरकार। लेकिन, 2018 में फिर भाजपा 104 सीट लेकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। बहुमत के लिए जोड़तोड़ कर पाती उससे पहले ही कांग्रेस के अस्सी और जनता दल के 37 विधायकों ने साझा सरकार का दावा पेश कर दिया।

कितने कप चाय पीना है...

उपरोक्त शीर्षक किसी की आवभगत का प्रतीक नहीं है, बल्कि मप्र की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में यह लेनदेन का कोडवर्ड है। दरअसल, सभ्य और सुशिक्षित लोग इसी तरह के कोडवर्ड का उपयोग कर लक्ष्मीजी की कृपा बटोरती हैं। उपरोक्त कोडवर्ड प्रदेश की राजधानी और व्यावसायिक राजधानी के बीच में पड़ने वाले एक जिले के एक पुलिस अधिकारी का है। सूत्रों का कहना है साहब इसी कोडवर्ड से लेनदेन करते हैं। जब भी कोई उनके पास अपने काम या फंसे मामले के लिए आता है तो साहब उनसे पूछ लेते हैं कि कितने कप चाय पीना है। यानी कितना देकर इस मामले को सुलटाना है। बताया जाता है कि पगड़ीधारी ये साहब राजनीति से संरक्षित हैं। यानी इनका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। इसका प्रमाण यह है कि साहब की अभद्रता से परेशान कुछ महिलाओं ने उनकी शिकायत पुलिस महकमे के मुखिया से की। साहब ने पहले तो उन महिलाओं से पूछा कि इसका कोई ऑडियो-वीडियो है, तो महिलाओं ने कहा- नहीं। फिर भी बड़े साहब ने जिले के जिम्मेदार इस अधिकारी की रिपोर्ट बनाकर ऊपर पहुंचा दी। बताया जाता है कि राजनीति से संरक्षित इस साहब की रिपोर्ट ऊपर तक पहुंचने के बाद भी उनका अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सूत्रों का कहना है कि राजनीतिक कृपा से साहब के खिलाफ जो रिपोर्ट गई है, उसे यह कहकर दबा दिया गया है कि कोई ऑडियो-वीडियो नहीं है।

कितनी जल्दी में सरकार

यह साल चुनाव का है। सरकार की कोशिश है कि इस साल ज्यादा से ज्यादा विकास की छूटी लोगों को पिलाई जाए। इसके लिए आने वाले दिनों में भूमिपूजन और लोकार्पण की भरमार होने वाली है। खुद सरकार के मुखिया ने मंत्रियों और विधायकों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को गति दें। इसी कड़ी में विन्ध्य के एक जिले में तो भूमिपूजन की ऐसी रूपरेखा तैयार की गई है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। दरअसल, ऊर्जाधानी के रूप में ख्यात उक्त जिले में एक ओवरब्रिज बनाया जाना है। अभी तक उक्त ओवरब्रिज को बनाने के लिए एजेंसी तय नहीं हो पाई है। लेकिन विकास के रथ पर सवार स्थानीय नेताओं और अधिकारियों ने उक्त ओवरब्रिज के भूमिपूजन की तैयारी शुरू कर दी है। वे लोग उक्त ओवरब्रिज का भूमिपूजन मुख्यमंत्री से कराने का तानाबाना बुनने लगे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या जल्दी है, जो बिना एजेंसी तय हुए ही ओवरब्रिज का भूमिपूजन कराए जाने की तैयारी हो रही है। दरअसल, यह इस बात का उदाहरण है कि किस तरह बिना तैयारी के विकास कार्यों का घोड़ा दौड़ाया जा रहा है।



जहां से कमाई वहीं पहुंच आई

विगत वर्ष सरकार ने जब तबादलों पर से रोक हटाई थी तो हर विभाग में अधिकारियों-कर्मचारियों ने कमाई या सुविधा वाली जगहों पर तबादला कराने के लिए लाइन लगा दी। इनमें से कुछ मालदार विभागों के अधिकारियों ने तो मंत्रियों के यहां मुंहमांगी रकम जमा कर मुंहमांगी पोस्टिंग की मांग कर डाली। लेकिन कईयों की मंशा पूरी नहीं हो पाई। ऐसे ही एक निर्माण कार्य करने वाले विभाग के एई इस घनचक्कर में फंस गए हैं। तबादला नहीं होने के बाद इन सभी अधिकारियों ने लामबंद होकर मंत्रीजी के यहां धावा बोला। सबने मंत्रीजी से गुहार लगाई कि हम चढ़ावा चढ़ा चके हैं, उसके बाद भी हमारा काम नहीं हुआ है। कई उत्साही इंजीनियरों ने तो यहां तक कह डाला कि आपके स्टाफ ने जितनी रकम मांगी हम लोगों ने उतनी दी है, फिर भी हमारा तबादला नहीं हुआ है। मंत्रीजी सबकी गुहार और पुकार सुनते रहे और मंद-मंद मुस्कराते रहे। एक इंजीनियर ने तो यहां तक कह दिया कि हमारा काम नहीं हो पाया, इसलिए हमारी रकम लौटा दी जाए। सूत्रों का कहना है कि सभी इंजीनियरों की गुहार सुनने के बाद मंत्रीजी ने कहा कि आप लोग इतने उतावले क्यों हो रहे हो। आप लोगों ने कोई एहसान नहीं किया है। आपने विभाग से जो कमाया है, वह फिर विभाग में आ गया है। बताया जाता है कि मंत्रीजी की ऐसी दो टूक सुनने के बाद सभी के पांवों तले जमीन खिसक गई। बेचारे मुंह मसोसकर वहां से चले आए और अब पछता रहे हैं।

मंत्रीजी की शिव आराधना

अक्सर कहा जाता है कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करने से बरकत होती है। वहीं यह भी कहा जाता है कि काली कमाई का कुछ हिस्सा पूजा-पाठ में लगाने से पाप नहीं पड़ता है। शायद यही वजह है कि एक मालदार विभाग में जमकर माल कूटने वाले एक मंत्रीजी शिव-आराधना पर जोर दे रहे हैं। वैसे तो इन दिनों मंत्रीजी के ग्रह नक्षत्र कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। जानकारों का कहना है कि इसी कारण मंत्रीजी के काले कारनामे परत दर परत सामने आ रहे हैं। मंत्रीजी के घपले-घोटालों से उनकी साख के साथ ही पार्टी की साख भी गिर रही है। शायद यही वजह हो सकती है कि मंत्रीजी भगवान भोले की पूजा-पाठ कर रहे हैं। यही नहीं मंत्रीजी ने गत दिनों महाकाल के मंदिर पहुंचकर 15 किलो की चांदी का छत्र भी चढ़ाया है। मंत्रीजी को करीब से जानने वाले लोगों का कहना है कि मंत्रीजी ने यह छत्र अपने गृह नक्षत्र सुधारने के लिए चढ़ाया है, लेकिन इसके लिए भी उन्होंने तरीका गलत अपनाया है। यानी अपनी कमाई की जगह यह छत्र भी किसी से उपहार में मंगवा लिया है। अब देखना यह है मंत्रीजी की दिन-दशा बदलती है या नहीं।

बाथरूम पड़ गया छोट

विगत दिनों राजधानी में वाटर विजन 2047 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में देशभर के जलमंत्री शामिल हुए थे। इन्हीं में एक थे देवभूमि के मंत्री। बताया जाता है कि मंत्रीजी आयोजन स्थल पर जब पहुंचे तो उनके आभा मंडल के सामने सभी हीन नजर आ रहे थे। कुछ माननीय तो मंत्रीजी की कद-काठी देखकर मन ही मन ऐसी कद-काठी की कामना कर रहे थे। लेकिन आयोजन स्थल पर मंत्रीजी के साथ जो कुछ घटा उसे देखकर हर कोई अपनी कद-काठी से संतुष्ट हो गया। दरअसल, आयोजन स्थल पर मंत्रीजी के लिए जो कक्ष आरक्षित था, मंत्रीजी जब उसके बाथरूम में गए तो वे जैसे-तैसे तो अंदर चले गए, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहे थे। बड़ी मेहनत से उन्हें बाहर निकाला गया। वहां उपस्थित अफसरों ने इसके लिए उनसे माफी भी मांगी। दरअसल, मंत्रीजी काया, नाम, काम और विभाग में भी भारी भरकम हैं। यानी मंत्रीजी के पास देवभूमि की सरकार में कई बड़े विभाग हैं। मंत्रीजी की कद-काठी भी लंबी-चौड़ी है। लेकिन आयोजकों को इसकी आशंका नहीं थी कि वे बाथरूम में फंस जाएंगे।

बारबरी को हिस्सेदार बनाकर फंसी गैमन इंडिया



दीपमाला को सभी ने लूटा

राजधानी भोपाल के हॉटस्पॉट यानी न्यू मार्केट में गैमन इंडिया को मिले प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी जिस दीपमाला कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिली थी, उसे सभी ने जमकर लूटा। चाहे नेता हो या अधिकारी उन्होंने अपनी मनमर्जी से इस कंस्ट्रक्शन कंपनी से कमाई की। कंपनी ने हर स्टेज पर पैसा पानी की तरह बांटा। इसका असर यह हुआ कि अफसरों और नेताओं के कारण कंपनी बर्बाद हो गई। वहीं एक अच्छा प्रोजेक्ट भर्शाही की भेंट चढ़ गया। जानकारी के अनुसार गैमन इंडिया प्रोजेक्ट के लिए जमीन फ्री होल्ड चाहता था, लेकिन सरकार द्वारा उसे 100 साल की लीज दी गई। उल्लेखनीय है कि यह प्रोजेक्ट गैमन इंडिया की सहयोगी दीपमाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड पूरा कर रही थी। 2008 में भोपाल के इस सबसे महंगे 330 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ था। 50 फीसदी बुकिंग हो चुकी थी। प्रोजेक्ट पर काम नहीं होने के विभिन्न कोर्ट में मामले दर्ज हुए। फिलहाल प्रोजेक्ट साइट वीरान पड़ी है। रेरा अधिनियम की धारा-8 में प्रावधान है कि ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें आगे कोई कार्य होने की संभावना न हो, उसे किसी सरकारी एजेंसी द्वारा पूरा कराने की एडवाइजरी रेरा जारी कर सकती है। सरकार इस पर विचार कर सकती है। आने वाले समय में गुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होगी। इसमें आगे की रणनीति पर विचार होगा।

बोर्ड से पूरा करवाया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट को हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से पूरा कराने की बात भी हुई, लेकिन इसकी कोई प्रक्रिया ही शुरू नहीं की। यदि हाउसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट शुरू करता तो उसे काम पूरा करने शासन को बड़ी रकम देना पड़ती।

मप्र भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने दीपमाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. (गैमन) के सृष्टि सीबीडी प्रोजेक्ट का पंजीयन निरस्त कर दिया है। अब इसका अधूरा काम दूसरी सरकारी एजेंसी पूरा करेगी। रेरा ने शासन को सुझाव दिया है कि हाउसिंग बोर्ड द्वारा अधूरे काम को पूरा किया जाए। इस संबंध में निर्णय शासन को लेना है। यह प्रोजेक्ट जिस भूमि पर प्रस्तावित है, वह सरकार की है और शासन की ओर से जमीन कंपनी को लीज पर दी गई थी। टीएंडसीपी की ओर से विकास अनुज्ञा मप्र गृह निर्माण मंडल को दी गई है। प्रोजेक्ट के लिए हाउसिंग बोर्ड नोडल व प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी है। बता दें कि रेरा प्राधिकरण द्वारा परियोजना पंजीकरण के आदेश में शर्तों का पालन न करने पर प्रोजेक्ट का पंजीयन मई 2019 में निलंबित किया गया था। कंपनी ने निलंबन के बाद भी शर्तों को पूरा नहीं किया। इसके चलते अब इसका पंजीयन निरस्त कर दिया है। रेरा ने अधिनियम की धारा-8 के तहत यह सुझाव दिया है कि राज्य शासन से इस संबंध में परामर्श किया जाए कि वर्तमान प्रोजेक्ट के शेष कार्यों को पूर्ण करने के लिए मप्र हाउसिंग और अंधोसंरचना विकास बोर्ड को दायित्व सौंपा जाए। अब देखना यह है कि प्रोजेक्ट का क्या होता है।

● सिद्धार्थ पांडे

भो पाल के टीटी नगर में गैमन इंडिया द्वारा बनाया गया बहुप्रतिष्ठित प्रोजेक्ट सालों बाद भी अधर में लटका हुआ है। दरअसल, अधिकारियों की मनमानी के कारण प्रदेश का यह बड़ा प्रोजेक्ट सरकार के साथ ही गैमन इंडिया के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। दरअसल वर्ष 2008 में यह प्रोजेक्ट बड़े लक्ष्य के साथ शुरू हुआ था। लेकिन जैसे-जैसे यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ता गया इसमें सरकारी व्यवधान आते गए और प्रोजेक्ट लटकता गया। अब यह प्रोजेक्ट सरकार के अधिकारियों के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसकी वजह यह है कि गैमन इंडिया ने दीपमाला कंस्ट्रक्शन कंपनी की बजाय बारबरी कंपनी को हिस्सेदार बना दिया है। सरकार का कहना है कि हमसे बिना पूछे बारबरी को बराबर का हिस्सेदार कैसे बना दिया गया।

दरअसल, 17 अप्रैल 2008 में कंपनी के अनुबंध में तय किया था कि दीपमाला इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी मालिक नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट डेवलपर है। मई 2017 को शर्तों के अनुसार हाउसिंग बोर्ड को प्रोजेक्ट सौंपना था। खरीदारों के मुताबिक कंपनी के पूर्व डायरेक्टर रमेश शाह ने तत्कालीन कलेक्टर निकुंज श्रीवास्तव के फर्जी हस्ताक्षर व सील बनवाकर 500 करोड़ रुपए की टीटी नगर स्थित जमीन की लीज ली थी। कंपनी पर आरोप था कि दिवालिया होने की कगार पर कंपनी ने सोनीमोनी इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पर एक हजार करोड़ रुपए कीमत की संपत्ति को चुपचाप तरीके से गिरवी रख दिया है। दीपमाला इंफ्रास्ट्रक्चर और मुंबई की सोनीमोनी इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ही रमेश शाह की कंपनी हैं। विवादित प्रोजेक्ट में सोनीमोनी इलेक्ट्रॉनिक्स की साझेदारी है।

गौरतलब है कि गैमन इंडिया द्वारा जिस प्रोजेक्ट पर काम किया गया उसके तहत 5 एकड़ में 22 मंजिल के पांच रेसीडेंशियल टॉवर, 66 विला का एक प्रीमियम टॉवर, 20 पेंट हाउस, 288 फ्लैट्स, 18 मंजिल के दो ऑफिस टॉवर, 488 ऑफिस स्पेस, जी प्लस फोर पार्किंग, स्वीमिंग पूल, स्पोर्ट कोर्ट, इनडोर गेम जोन, चिल्ड्रेंस प्ले जोन, जॉर्गिंग व साइकिल ट्रेक बनाना था। लेकिन बार-बार के व्यवधान के कारण यह प्रोजेक्ट लेट होता गया। दरअसल टीटी नगर की ये जमीन शासन ने लीज पर कमर्शियल कम रेसीडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए गैमन को दी थी। करीब 40 अरब रुपए इस प्रोजेक्ट से कमाई का अनुमान था। प्रोजेक्ट में भुगतान वसूली के बाद प्रोजेक्ट का काम बंद कर दिया। तय समय में मकान नहीं दिए गए। मामला रेरा में भी गया था और यहां से राज्य सरकार को सुझाव दिया गया था कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आम्रपाली गुप के प्रोजेक्ट को दूसरी सरकारी एजेंसी बना रही हैं, उसी तरह गैमन के इस प्रोजेक्ट को मप्र हाउसिंग

प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में संपन्न 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में विदेश से आए हजारों प्रवासी भारतीयों ने 14 हजार रुपए में रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें सिर्फ लंच और डिनर शामिल था, बाकी लाखों रुपए उन्हें अलग से खर्च करने पड़े। लेकिन बार-बार के बुलावे और लाखों रुपए खर्च कर सम्मेलन में शिरकत करने आए मेहमानों को ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में अंदर तक नहीं घुसने दिया गया। यानी उन्हें कुर्सी भी नहीं मिली। नाराज मेहमानों ने अपना गुस्सा जताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि हम यहां अपनी बेइज्जती कराने थोड़े आए हैं। उन्होंने कहा कि हम जब गुजरात जाते हैं, तो वहां हमारे कुर्सी पर हमारे नाम की चिट लगी होती है। यहां तो अंदर भी नहीं जाने दिया गया। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर माफी भी मांगी, लेकिन प्रदेश की छवि पर लगे दाग को धोने के लिए यह शायद काफी नहीं है। गुस्साए प्रवासी भारतीयों का कहना था कि

14 हजार में कुर्सी भी नहीं मिली...!

हम यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने आए हैं न कि शिवराज सिंह चौहान को। दरअसल, सरकार ने बड़े वादों के साथ उन्हें बुलाया था, लेकिन उन्हें होटल या कार्यक्रम स्थल पर आने-जाने के लिए वाहनों की व्यवस्था अपने खर्च पर करनी पड़ी। अब पहले प्रवासी भारतीय सम्मेलन और बाद में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान अतिथियों के अपमान और विवाद पर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में आयोजनों से जुड़े कुछ अधिकारियों

पर गाज गिर सकती है।

करणी सेना के आंदोलन के पीछे कौन

वहीं सूत्रों का कहना है कि राजधानी में करणी सेना के आंदोलन के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, उसके पीछे किसी बड़े व्यक्ति का हाथ हो सकता है। मुख्यमंत्री ने भले ही अपशब्द कहने वालों को माफ कर दिया है, लेकिन इंटेलेजेंस यह पता लगा रही है कि आखिरकार करणी सेना के आंदोलन के पीछे किसका हाथ है। आने वाले दिनों में इंटेलेजेंस अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा, उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी।

● कुमार राजेन्द्र

मंत्रियों की क्लास 18 को

चुनावी वर्ष में भाजपा की सक्रियता और बढ़ने वाली है। अब सरकार पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों की बैठक बुलाई है। बैठक मुख्यमंत्री निवास पर 18 जनवरी सुबह 10.30 बजे आयोजित होगी।



इसमें विकास यात्रा समेत आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा होने की बात कही जा रही है। इसमें सभी मंत्रियों को शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। इस साल मंत्रियों में चुनाव है।

मुख्यमंत्री लगातार मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने 2 जनवरी को मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इसमें मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और अधिकारियों को काम से जनता की जिंदगी बदल देने का मंत्र दिया था। बता दें सरकार 1 फरवरी से प्रदेश में विकास यात्राएं आयोजित कर रही है। इन यात्राओं में प्रदेशभर में लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को यात्रा से जोड़ा जाएगा। साथ ही योजनाओं और कामों को जनता को बताया जाएगा। इसको लेकर हाल ही में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जिला कलेक्टर को आदेश जारी किए हैं। यात्राओं की रूपरेखा जिले के प्रभारी मंत्री से चर्चा कर कलेक्टर तैयार करेंगे।

हनीट्रैप: एसआईटी स्टेटस रिपोर्ट पेश नहीं कर सकी

मप्र में बहुचर्चित हनीट्रैप मामले में एसआईटी ने अब तक स्टेटस रिपोर्ट पेश नहीं की है। मामले में एसआईटी के वकील ने कोर्ट से और समय दिए जाने की मांग रखी है। कोर्ट ने एसआईटी को 3 फरवरी तक का समय दिया और जवाब मांगा है। एसआईटी कांग्रेस नेता कमलनाथ से कथित सीडी-पेन ड्राइव अब तक हासिल नहीं कर सकी है। एसआईटी को खुद मामले की जांच कर और सबूत जुटाकर कोर्ट को जवाब देना था। बता दें कि हाल ही में अपने पेन ड्राइव को लेकर दिए गए बयान से पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीसीसी चीफ कमलनाथ पलट गए थे। अगली पेशी में आवश्यक रूप से जवाब पेश करने और स्टेटस रिपोर्ट देने की बात कही गई है। इस हाईप्रोफाइल मामले में कई नेताओं और अफसरों का नाम शामिल है।

30 किमी लंबा बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर

राजधानी में कंदाला-वाराणसी की तर्ज पर एनएचआई 30 किमी लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाएगा। इस प्रोजेक्ट पर 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भोपाल के मिसरोद से लेकर भानपुरा खंती तक यह एलिवेटेड कॉरिडोर हवा में रहेगा, जिसकी लंबाई 25 किमी की होगी। उसके बाद 5 किमी यह कॉरिडोर जमीन पर रहेगा। दरअसल, राजधानी में ट्रैफिक के बढ़ते बोझ को देखते हुए यह कॉरिडोर बनाया जाएगा। हवा में बनने वाला 25 किमी लंबा कॉरिडोर 7 लेन का होगा। जबकि जमीन पर बनने वाला कॉरिडोर 10 लेन का होगा। इस लेन से भोपाल रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और राजाभोज विमानतल को भी जोड़ा जाएगा, ताकि यहां आसानी से पहुंचा जा सके। वहीं इस कॉरिडोर को शहर के बाहरी अन्य मार्गों से जोड़ा जाएगा।

अब कलेक्टर-कमिश्नर की बैठक 30 से

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 31 जनवरी और 1 फरवरी को कमिश्नर, कलेक्टर कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक शामिल होंगे। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री प्रदेश में कानून व्यवस्था और सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों से कॉन्फ्रेंस में वन टू वन चर्चा करेंगे। सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी को भोपाल बुलाया गया है। पहले दिन मुख्यमंत्री कमिश्नर और कलेक्टर से बात करेंगे। इसके बाद अगले दिन आईजी और एसपी से चर्चा करेंगे। कोरोना के बाद पहली बार फिजिकल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। इससे पहले दो बार कॉन्फ्रेंस स्थगित हो चुकी हैं। 16 और 17 जनवरी को कॉन्फ्रेंस आयोजित होनी थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था। बैठक को लेकर सभी विभागों से पहले ही जानकारी भेजने के लिए कहा गया था।

मप्र में 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने मिशन 2023 फतह करने की फुलपूफ रणनीति बना ली है। इस रणनीति के तहत भाजपा का पूरा फोकस जहां 2018 में हारी 103 सीटों पर है, वहीं अपने कब्जे वाली सीटों की भी लगातार समीक्षा की जा रही है। पार्टी को विश्वास है कि शिव-वीडी की रणनीति से इस बार भाजपा 51 फीसदी वोटों के साथ 200 सीटों का टारगेट आसानी से पा लेगी।

20 23 में मप्र सहित 9 राज्यों में चुनाव होना है। राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। मप्र में विधानसभा चुनाव होने में अब एक साल से भी कम का समय रह गया है। ऐसे में प्रदेश का राजनीतिक माहौल

गर्म होने लगा है, तो वहीं राजनीतिक दल भी अपनी-अपनी चुनावी रणनीतियां तय करने में जुट गए हैं। हालांकि सत्ता की चाबी जनता किसे सौंपने वाली है ये तो भविष्य

ही बताएगा लेकिन एक बात तय है कि 2023 का चुनावी मुकाबला आसान नहीं होने वाला है। मैदान में भाजपा पूरी शक्ति के साथ उतरेगी जैसा कि वह हर चुनाव में करती है। इसके लिए पार्टी ने रणनीति बनाई है कि इस बार कमजोर जनाधार वाले विधायकों का टिकट हर हाल में काटा जाएगा। पार्टी इसके लिए सर्वे भी कराएगी।

गौरतलब है कि इस बार भाजपा ने 51 फीसदी वोट के साथ 200 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए पार्टी ने पूरी जमावट शुरू कर दी है। राज्य के बजट के बाद इस बार अप्रैल-मई से टिकट को लेकर एक्सरसाइज शुरू होने वाली है। भाजपा में इस बार टिकट के पैटर्न में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। कमजोर जनाधार वाले विधायकों के टिकटों पर इस बार खतरा है। फिर से जीत नहीं सकने वाले विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। भाजपा जल्द सभी 230 सीटों पर बड़ा सर्वे करवाएगी। इस सर्वे में सैंपल साइज बढ़ा लिया जाएगा ताकि हर सीट पर जनता की राय लेकर मौजूदा विधायक की खामियों, खूबियों और जीतने वाले उम्मीदवार पर तस्वीर साफ हो सके। संगठन के स्तर पर पहले भी कुछ सर्वे हुए हैं, लेकिन उनका सैंपल साइज बड़ा नहीं था। भाजपा संगठन के स्तर पर भी कई बार फीडबैक लिया गया है। भाजपा चुनावी साल में अब जो सर्वे करवाएगी, वह टिकट वितरण में बड़ा आधार बनेगा। अप्रैल-मई से लेकर अगस्त, सितंबर तक सर्वे का दौर चलेगा। हालांकि, हर चुनाव से पहले पार्टियां सर्वे करवाती रही हैं, लेकिन इस बार भाजपा सर्वे के पैटर्न में बदलाव करेगी और ज्यादा लोगों के बीच पहुंचकर राय लेने के लिए

कमजोर विधायकों का कटेगा टिकट



जीत के शिल्पकार बनेंगे पन्ना प्रमुख

गुजरात चुनाव में मिली ग्रैंड सक्सेस को भाजपा मप्र में भी दोहराना चाहती है। इसके लिए गुजरात चुनाव मॉडल को प्रदेश में लागू करने की अटकलें भी हैं। गुजरात की जीत में पन्ना प्रमुख को मुख्य हथियार बताया जा रहा है। इसी तर्ज पर भाजपा पन्ना प्रमुख के सहारे मप्र में विधानसभा चुनाव को बड़े आंकड़े से जीतने में जुट गई है। पार्टी का दावा है कि अब तक चार लाख पन्ना प्रमुख बना लिए हैं। साथ ही बूथ अध्यक्षों को पन्ना प्रमुख बनाने के साथ एप से जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि पन्ना प्रमुख वह कहा जाता है, जिसके पास वोटर लिस्ट के एक पन्ने की जिम्मेदारी होती है। हर पन्ने पर पांच पन्ना सदस्य होते हैं। मप्र में भाजपा चुनावी तैयारी में जुट गई है। उसका पूरा फोकस पन्ना प्रमुखों पर है। प्रदेश में 64 हजार 100 बूथ पर भाजपा पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है। करीब 13 लाख बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संगठन एप से जोड़ा गया है। बूथ पर भाजपा ने एक बूथ अध्यक्ष, महामंत्री और बीएलए की नियुक्ति की है। इसके साथ ही पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति भी बनाई, लेकिन उनकी संख्या कम है। अब भाजपा ने बूथ अध्यक्षों को पन्ना प्रमुख और समिति बनाने और डिजिटल एप से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में वोटर लिस्ट में 18 लाख पन्ने हैं, जो बढ़कर 20 लाख के करीब पहुंचने की उम्मीद है।

सैंपल साइज बढ़ा करवाया जाएगा।

मप्र एक ऐसा राज्य है जहां भाजपा लगभग 18 साल से सरकार चला रही है और जमीन पर भी अच्छी तरह से पकड़ बनाए हुए है। आलाकमान ने अबकी बार 200 के पार का लक्ष्य निर्धारित कर चुनावी रणनीति बनाने के लिए शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा के साथ ही शिव प्रकाश को जिम्मेदारी सौंपी है। भाजपा की यह त्रिमूर्ति अभी से आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाकर संगठन को काम पर लगाएंगे। वहीं प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, सह प्रभारी पंकजा मुंडे व विश्वेश्वर टुंडे मॉनीटरिंग करेंगे। शिवराज सिंह चौहान इस राज्य का लंबे समय से नेतृत्व कर रहे हैं और चार बार मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। प्रदेश में अभी भी जमीनी स्तर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही एक बड़ा चेहरा दिखाई देते हैं। वहीं वीडी शर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से प्रदेश में अपनी लोकप्रियता बढ़ाई है। गौरतलब है कि 2003, 2008 और 2013 में कांग्रेस को 75 सीटों के नीचे समेटने वाली भाजपा 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से पिछड़ गई। कांग्रेस को 114 और भाजपा को 109 सीटें मिली। इस कारण 15 साल बाद मप्र में कांग्रेस की सरकार बनी। जबकि भाजपा का वोट प्रतिशत (41.6 प्रतिशत) और कांग्रेस (41.5 प्रतिशत) से अधिक था। हालांकि 15 माह बाद ही कांग्रेस की सरकार गिर गई और एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बन गई है। अब भाजपा की रणनीति यह है कि वह 2023 में कांग्रेस का सूपड़ा साफ करना चाह रही है। इसके लिए अभी से

रणनीतिक जमावट की जा रही है।

भाजपा सूत्रों का कहना है कि पार्टी अभी से मिशन 2023 की तैयारी में इसलिए जुटी हुई है कि आलाकमान ने आगामी विधानसभा चुनाव में 200 से अधिक सीटों जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। गौरतलब है कि 2018 में भी भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अबकी बार 200 के पार का नारा दिया था। मप्र विधानसभा चुनाव तक भाजपा की तरफ से इस नारे को खूब हवा दी गई और दावा किया गया कि भाजपा इस बार सीटों का आंकड़ा 200 पार करेगी। 28 नवंबर 2018 को हुई बंपर वोटिंग के बाद लगा कि भाजपा का दावा हकीकत में बदल सकता है, लेकिन भाजपा 109 पर सिमटकर रह गई। दरअसल, भाजपा ने यह लक्ष्य इसलिए निर्धारित किया है कि क्योंकि मप्र विधानसभा की 230 सीटों में से 207 ऐसी सीटें हैं जिनको भाजपा कभी ना कभी जीत चुकी है। भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी कहते हैं कि 2018 में भाजपा ने इसी आधार पर 200 पार का नारा दिया था, लेकिन पार्टी बहुमत के आंकड़े (116) को भी नहीं छू पाई। इसके पीछे वजह थी रणनीतिक कमजोरी और अतिविश्वास। इसलिए भाजपा आलाकमान ने इस बार 3 साल पहले से ही चुनावी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है।

आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा जिलों में जाकर फीडबैक ले रहे हैं। गत दिनों उन्होंने जबलपुर में भाजपा के संभागीय कार्यालय में महाकौशल के सांसद और विधायकों से वन टू वन चर्चा की। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने करीब तीन घंटों तक सांसद-विधायक से चर्चा की। जिसमें संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने पर मंथन हुआ। संभाग की 38 विधानसभा पर एक-एक विधायक से वीडी शर्मा ने बंद कमरे में चर्चा की। बैठक में संभाग से 43 सदस्य आपेक्षित थे जिसमें 37 मौजूद रहे। संभागीय बैठक करने के बाद वीडी शर्मा ने कहा कि संगठनात्मक दृष्टि से कई पहलुओं पर कार्य विस्तार को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि आगामी 2023 के चुनाव की तैयारी भी शुरू हो गई है। शर्मा ने कहा कि



अनेक योजनाओं की मदद से केंद्र व प्रदेश की सरकारें गरीबों का जीवन बदल रही हैं। जीवन बदलने के इस अभियान में जनप्रतिनिधि भी सहभागी बनें। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए सभी अपने वार्डों में जुट जाएं। और लोगों तक नर सेवा ही नारायण सेवा का मंत्र लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना और जनहित की अन्य योजनाओं का लाभ पहुंचाने में जुट जाएं। प्रदेशाध्यक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार हम कांग्रेस की नाकामियों से 2014 का लोकसभा चुनाव जीते, उस समय हमें 17 करोड़ वोट मिले। जबकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में हम 23 करोड़ वोट के प्रचंड बहुमत से जीते। इसमें गरीब कल्याण की योजनाओं के कारण ही 6 करोड़ वोटों की वृद्धि हुई है। ऐसे में अब भाजपा के संगठन की ताकत और विचार के बल पर 2024 का चुनाव जीता जाएगा। अतः सभी जनप्रतिनिधि संगठन को सुदृढ़ बनाने में जुट जाएं। प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा के अनुसार हमको गर्व होना चाहिए कि हम डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे नेताओं द्वारा खड़ी की गई पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जब कश्मीर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में धारा 370 लगाई गई, तो मंत्रिमंडल से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जनसंघ की स्थापना इसके बाद ही हुई। पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 1980 में भाजपा की स्थापना हुई। उसी बलिदानी भाजपा के हम कार्यकर्ता हैं।

गौरतलब है कि 51 प्रतिशत वोट शेयर के

साथ अजय होने का संकल्प लेकर भाजपा ने 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए रणनीति पर अमल शुरू कर दिया है। मप्र में पार्टी ने कुशाभाऊ ठाकरे जन्मशती वर्ष में बूथ विस्तारक योजना तैयार की थी। इसके तहत बूथ स्तर पर काम की निगरानी और संदेश आदि पहुंचाने के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया गया। इतना ही नहीं, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की जानकारी, उनसे जुड़े डेटा का डिजिटलाइजेशन भी किया गया। इसके अच्छे परिणाम देखकर पार्टी अखिल भारतीय स्तर पर इसके प्रशिक्षण की योजना बना रही है। इसमें मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सहित पन्ना प्रभारियों तक की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। इसके तहत केंद्र एवं प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से चर्चा कर भाजपा के पक्ष में अभी से माहौल बनाने की तैयारी है। पार्टी ने स्मार्ट बूथ पर जो काम शुरू किया है, उसके अनुसार अब बूथ स्तर के कार्यकर्ता को भी नई पहचान मिल सकेगी। पार्टी प्रदेश के 65 हजार बूथ अध्यक्ष, महामंत्री और बूथ एजेंट को पार्टी संगठन में विशेष तक्जो देने जा रही है। भाजपा पिछले कुछ वर्षों में वृहद स्तर पर सदस्यता अभियानों के बाद खुद को विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बताती आ रही है। इसका श्रेय किसी बड़े चेहरे या पदाधिकारियों के बजाय लाखों कार्यकर्ताओं को दिया जाता है, लेकिन उन्हें अलग से विशेष पहचान की कमी महसूस होती रही है।

● कुमार विनोद

हारी सीटों पर माइक्रो लेवल पर काम

अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा का सबसे ज्यादा ध्यान आकांक्षी विधानसभा सीटों पर है। यह वह सीटें हैं जिनमें पार्टी को पिछली बार पराजय मिली थी। इनकी संख्या 103 है। अब इन सीटों के हर बूथ में 51 प्रतिशत मत पाने के लिए पार्टी ने रणनीति तैयार की है। इसमें कार्यकर्ताओं को साधने से लेकर मतदाताओं को रिझाने तक विशेष योजना है। इस योजना के तहत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव जीत का प्लान बनाकर मैदानी मोर्चे पर सक्रिय हो गए हैं। गत दिनों आकांक्षी विधानसभा सीटों को जीतने की रणनीति पर चर्चा के लिए आकांक्षी विधानसभा प्रभारियों की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने प्रभारियों को जीत का मंत्र दिया। शर्मा ने बताया कि पार्टी ने प्रत्येक बूथ पर 51 प्रतिशत मत पाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सबसे ज्यादा जोर इस बात पर है कि प्रदेश में विकास के जो कार्य भाजपा सरकार ने किए हैं वह निचले स्तर तक पहुंचें। पार्टी की रीति-नीति हर मतदाता को पता हो। यह तभी हो सकता है जब एक-एक बूथ को सुदृढ़ किया जाए।

म प्र में ब्यूरोक्रेट्स के पास कितनी अचल संपत्ति है और वह कहां से मिली है, ये जानकारी उन्हें हर हाल में देनी होगी। इस संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग कार्मिक ने निर्देश जारी किया है। निर्देश के अनुसार अखिल भारतीय सेवाओं के मप्र कॉडर के सभी अधिकारियों को 1 जनवरी से 31 जनवरी 2023 के बीच अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा डीओपीटी को ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। अगर किसी ब्यूरोक्रेट्स ने नियमित तौर से अपनी अचल संपत्ति का खुलासा नहीं किया है, तो उसे अब 11 साल का ब्यौरा देना पड़ेगा। जिस विंडो पर आईपीआर भरी जाती है, वह खुली रहेगी। डीओपीटी ने भी इस बाबत सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वे संबंधित अधिकारियों से तय समय सीमा में आईपीआर भरवाना सुनिश्चित करें।

जारी किए गए निर्देश में कहा गया है कि 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आईएएस अधिकारियों को अपनी अचल संपत्ति का विवरण पत्रक ऑनलाइन कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय को देना है। इसे अनिवार्य रूप से देना है। जो अधिकारी अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं करते हैं उनकी अगले वेतनमान में पदोन्नति इसके कारण प्रभावित हो सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह भी कहा है कि ऑनलाइन प्रस्तुत किए गए अचल संपत्ति के विवरण पत्रक की अलग से मैनुअली कॉपी प्रिंट आउट या हार्ड कॉपी अब सामान्य प्रशासन विभाग या डीओपीटी को भेजने की जरूरत नहीं है। यदि मप्र कॉडर का कोई आईएएस अधिकारी 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा देने में असमर्थ है तो इसके लिए वैधानिक कारण का उल्लेख कर वह इसके लिए अनुमति लेकर बाद में अपनी संपत्ति का ब्यौरा दाखिल कर सकेगा।

गौरतलब है कि कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय की अपर सचिव डीसी उमाशंकर ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर अखिल भारतीय सेवाओं आईएएस, आईपीएस और आईएफएस से 1 से 31 जनवरी के बीच अचल संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन भरने के निर्देश दिए हैं। संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन मॉड्यूल में इलेक्ट्रॉनिक रूप से देना है। इसके लिए मैनुअली जानकारी की स्कैन कॉपी का उपयोग भी किया जा सकेगा।

बीते 11 वर्षों में कभी भी यदि किसी आईएएस अफसर ने किसी साल अपनी प्रॉपर्टी की जानकारी सरकार को नहीं दी है तो उसे अब देनी होगी। फिर भी यदि कोई अफसर जानकारी नहीं देता है तो उसे अगली वेतनवृद्धि नहीं मिलेगी। इसलिए ऐसे आईएएस अफसरों की खोजबीन शुरू कर दी गई है, जिन्होंने अचल



हर ब्यूरोक्रेट्स को देना होगा अचल संपत्ति का ब्यौरा

विजिलेंस क्लियरेंस के लिए जरूरी है आईपीआर भरना

केंद्र सरकार ने आईएएस अधिकारियों के लिए (ए) प्रस्ताव सूची में शामिल करने के उद्देश्य से सतर्कता मंजूरी लेना अनिवार्य किया है। (बी) पैल में या (सी) में कोई भी प्रतिनिधित्व, जिसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी आवश्यक है, उस वक्त संबंधित अधिकारी की विजिलेंस क्लियरेंस देखी जाती है। यदि कोई अधिकारी पिछले वर्ष की अपनी वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न अगले वर्ष की 31 जनवरी तक जमा करने में विफल रहता है, तो उसे सतर्कता मंजूरी से वंचित कर दिया जाएगा। वर्ष 2020 के लिए आईपीआर दाखिल नहीं करने वाले त्रुटिपूर्ण आईएएस अधिकारियों पर कार्रवाई के संबंध में, आईएएस (आचरण) नियम, 1968 के नियम 16 (2) के तहत कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को दोषी अधिकारियों की सूची अग्रेषित की गई थी। संबंधित वेतन नियमों में संशोधन के माध्यम से संबंधित आईएएस के अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति प्रदान करने के लिए भी आईपीआर समय पर जमा करना एक अनिवार्य शर्त है।

संपत्ति की जानकारी नहीं दी है। मप्र के तीन आईएएस ऐसे भी हैं जिन्होंने नियमों का उल्लंघन

करते हुए पिछले वर्षों में अपनी संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन नहीं किया है। जिन अफसरों ने ब्यौरा नहीं दिया है उनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2009 बैच के आईएएस शिवपाल ने वर्ष 2017 का संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। उन्हें स्मरण पत्र भेजे गए थे लेकिन बिना जानकारी दिए ये 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त हो गए। दूसरे आईएएस 2012 बैच के आईएएस संतोष कुमार वर्मा हैं जिन्होंने 2021 का संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। ये वर्तमान में निलंबित चल रहे हैं। उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तीसरी आईएएस 2015 बैच की आईएएस रानी बंसल है। जिन्होंने वर्ष 2020 और 2021 का अपना संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। ये तीन साल से अपनी नौकरी से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित चल रही थीं जिसके चलते डीओपीटी ने उनकी सेवाएं स्वतः त्यागपत्र के आधार पर समाप्त कर दी हैं।

आईएएस अधिकारी की पिछले साल तक अर्जित कुल संपत्ति के बाद खरीदी या बेची गई संपत्ति का ब्यौरा इसमें स्वयं के नाम से खरीदी या लीज पर ली गई संपत्ति का ब्यौरा तो देना ही है, साथ ही अपने परिवार के सदस्यों, पत्नी, उन पर आश्रित बच्चों या अन्य किसी के नाम से खरीदी गई अचल संपत्ति का ब्यौरा भी देना है। इसमें उन्हें यह जानकारी भी देना है कि संपत्ति खरीदने या लीज पर लेने के पहले उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग कार्मिक से इसकी विधिवत अनुमति लेकर संपत्ति खरीदी या लीज पर ली है या नहीं। यदि पारिवारिक संपत्ति वसीयत में उसे उस वर्ष में प्राप्त हुई है। कोई संपत्ति उसे पारिवारिक सदस्यों द्वारा या किसी अन्य के द्वारा दान में मिली है तो उसकी जानकारी भी देनी होगी।

● सुनील सिंह

मप्र में एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुशासन की बातें करते थकते नहीं हैं, वहीं दूसरी तरफ स्थिति यह है कि सरकारी अफसर आम आदमी तो छोड़िए हाईकोर्ट तक की नहीं सुनते हैं। इसका अंदाजा अवमानना के मामलों के आंकड़ों पर गौर करके लगाया जा सकता है। प्रदेश में पिछले 5 साल में यानी 2018 से लेकर अक्टूबर 2022 तक अधिकारियों-कर्मचारियों पर हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना के 15780 मामले हुए हैं। इसमें राज्य मंत्रालय में बैठकर नीति निर्धारण करने वाले अफसरों से लेकर कलेक्टर-एसपी तक शामिल हैं। जिस तरह मप्र में अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ अवमानना के मामले दर्ज हो रहे हैं, उससे यह साफ लगता है कि अफसरों के ठेंगे पर हाईकोर्ट के आदेश हैं।

शासन-प्रशासन के द्वारा हाईकोर्ट के बहुत सारे आदेशों की अवहेलना के कारण हाईकोर्ट में लंबित मुकदमों की संख्या चार लाख के पार हो गई है। मालूम हो कि अवमानना मामलों की बढ़ोत्तरी भी चिंताजनक है। इस साल महज 10 माह के भीतर अवमानना मामले ढाई हजार के पार हो चुके हैं। ऐसे में वर्ष बीतने के साथ ही इनकी संख्या तीन हजार पार होने के पूरी उम्मीद है। जानकारी के अनुसार अफसरशाही की टालमटोल इसकी मुख्य वजह है। यद्यपि सरकारी नुमाइंदा जनता के सेवक हैं किंतु वे आम आदमी की गुहार सुनना तो दूर अदालती आदेश तक नहीं मानते। यह देखने में आया है कि जैसे ही हाईकोर्ट की ओर से अवमानना नोटिस जारी होता है, संबंधित शासकीय विभागों की नींद टूटती है और वे कारण बताओ नोटिस का जवाब पेश करके शीघ्र ही आदेश का पालन सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाते हैं। वहीं, अगर उक्त आंकड़ों से साफ है कि शासन-प्रशासन के द्वारा हाईकोर्ट के बहुत सारे आदेशों की अवहेलना की जाती है। जिसका खामियाजा उन्हीं पक्षकारों को भुगताना पड़ता है, जो न्याय की आस में हाईकोर्ट आते हैं। जब उनकी याचिका पर पूर्व में पारित आदेश का निर्धारित समयावधि में पालन सुनिश्चित नहीं होता, तो वे नए सिरे से अवमानना याचिका दायर करने विवश होते हैं।

वहीं हाईकोर्ट अवमानना प्रकरणों में सख्ती बरतते हुए अवमानना याचिकाओं का उसी सूरत में पटाक्षेप करता है, जबकि पूर्व आदेश का पालन कर दिया जाता है। हालांकि एक बार जिस याचिका पर आदेश पारित कर दिया जाता है, जब नए सिरे से उसी से संबंधित अवमानना याचिका दायर होती है, तो हाईकोर्ट में जाहिर तौर पर लंबित मुकदमों का बोझ बढ़ जाता है। इस वजह से पक्षकारों को लंबे समय तक अदालत व वकील के चक्कर काटने विवश होना पड़ता है। हाईकोर्ट का कीमती समय व पक्षकार



हाईकोर्ट के आदेश नहीं मानते अफसर

मुकदमा नीति को लागू करने हर विभाग में पहल

राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मुकदमा नीति बनाना था और इस नीति के तहत विभागों में आंतरिक परिवाद समितियों का गठन करना था, ये समितियां प्रदेश के हर एक विभाग और विभागाध्यक्ष, कलेक्टर, तहसील और ब्लॉक कार्यालय में गठित होना था। लेकिन सिर्फ सामान्य प्रशासन विभाग ने रस्म अदायगी के चलते समिति गठित कर दी लेकिन उसकी कोई बैठक नहीं हुई। अन्य विभागों और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में तो इस समिति के गठन का नामोनिशान तक नहीं है। इन समितियों के गठन का उद्देश्य विभागीय स्तर पर कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाना था, जिससे कर्मचारी सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में न पहुंचें और वहां मुकदमों की संख्या न बढ़े। सेवा शर्तों संबंधी मामलों में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा छोटे-मोटे मामलों के संबंध में कर्मचारी के पक्ष में सहानुभूति पूर्वक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

का धन, ऊर्जा व समय खराब होता है।

मप्र के हाईकोर्ट ने एक बार फिर से सख्त रुख अपनाया है। दरअसल अधिकारियों-कर्मचारियों को लगातार दिए निर्देश और आदेश के बावजूद आदेश का पालन न करने की स्थिति में अब हाईकोर्ट द्वारा सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। हाईकोर्ट ने अधिकारियों को सख्त लहजे में हिदायत दी है कि हर हाल में आदेश का पालन सुनिश्चित हो, ऐसा नहीं करने की स्थिति में संबंधित अधिकारी परिणाम भुगतने

के लिए तैयार रहें। इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो आला अधिकारी को भी हाईकोर्ट में पेश होकर अपना जवाब पेश करना होगा। हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थिति में हाईकोर्ट की अवमानना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सिविल और क्रिमिनल केसों की पेंडेंसी को निपटाने की नीति मप्र में कारगर साबित नहीं हो पा रही है। राज्य सरकार की नीति है कि कोई भी पेंडिंग केस 3 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन मप्र में 11 साल पुराने केस तक लंबित हैं। इतना ही नहीं, पिछले एक साल में ही हाईकोर्ट पर 23 हजार केसों का बोझ बढ़ गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में सभी राज्यों के केसों का ब्यौरा दिया है, जिसमें मप्र में पेंडिंग केसों की संख्या 4 लाख 17 हजार निकली है। यह स्थिति तब है जब मप्र में न्याय देने वाले जजों की संख्या बमुश्किल 32 है। यानी हर जज के पास 13 हजार से अधिक केस लंबित हैं। कोर्ट में इस महीने के शुरुआत में 4 लाख 17 हजार 288 मामले लंबित थे, जिनमें 260371 सिविल के और 156917 क्रिमिनल के। पिछले साल यह संख्या 3 लाख 94 हजार 220 थी, यानी एक साल में 23 हजार से ज्यादा मामले बढ़ गए। यह जानकारी राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय कानून मंत्री किरन रिजिजू ने दी है। यह स्थिति तब है, जब लगातार कोर्ट में बढ़ रहे मामलों को कम करने के लिए राज्य सरकार ने मुकदमा नीति बनाई हुई है। मुकदमा नीति में साफ है कि सरकारी मुकदमों को कम किया जाए ताकि कोर्ट में विचाराधीन मामलों का निराकरण 15 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष किया जा सके।

● बृजेश साहू

म प्र के बासमती चावल को जीआई टैग देने की प्रक्रिया का विरोध करने वाला हरियाणा यहां की मंडियों से बासमती धान खरीदकर उसमें से चावल निकालकर अपने नाम से बेच रहा है। गौरतलब है कि जब भी मप्र के बासमती को जीआई टैग देने की बात होती है हरियाणा, पंजाब सहित कई राज्य इसकी क्वालिटी को खराब बताकर इसका विरोध शुरू कर देते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन दिनों प्रदेश की मंडियों से हरियाणा सरकार की सरकारी एजेंसी हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड (हैफेड) बासमती धान की खरीदी कर रही है।

गौरतलब है कि जीआई रजिस्ट्री ने 15 फरवरी 2016 को देश के 7 राज्यों में उत्पादित बासमती धान को जीआई टैग दिया। जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, उप्र और जम्मू-कश्मीर के कुछ जिलों शामिल रहे। मप्र में उत्पादित बासमती धान को भी जीआई टैग देने मप्र शासन तथा मप्र क्षेत्र बासमती ग्रोबर एसोसिएशन ने जीआई रजिस्ट्री के समक्ष मांग पत्र पेश करते हुए मप्र में उत्पादित बासमती धान को जीआई टैग देने की मांग की, लेकिन पंजाब और हरियाणा सरकार और यहां के ऑल इंडिया राइस मिलर्स ने आपत्ति जताई की मप्र में उत्पादित बासमती धान की क्वालिटी सही नहीं है। अतः मप्र की बासमती को जीआई टैग नहीं दिया जाए। मगर मौजूदा समय में हरियाणा सरकार की सरकारी एजेंसी हैफेड मप्र में उत्पादित बासमती धान की खरीदी कर रही है और धान से चावल निकालकर अपने प्रदेश का जीआई टैग लगाकर देश में सप्लाई कर रही है।

प्रदेश में उत्पादित बासमती की क्वालिटी खराब कहने वाला राज्य हरियाणा की सरकार की संस्था हैफेड मौजूदा समय में मप्र की रायसेन, पिपरिया, बरेली, विदिशा सहित अन्य मंडियों से बासमती धान की खरीदारी कर रही है। इतना ही 4 लाख क्विंटल से ज्यादा प्रदेश में उत्पादित बासमती धान का परिवहन भी हो चुका है। मप्र क्षेत्र बासमती ग्रोबर एसोसिएशन के पदाधिकारी और दावत फूड लिमिटेड के एडवाजर केके तिवारी के अनुसार मप्र में उत्पादित बासमती धान भारी मात्रा में हरियाणा पहुंच रहा है। हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड (हैफेड) बासमती धान की खरीदी कर रही है और टर्कों से मप्र में उत्पादित बासमती धान का परिवहन हो रहा है। तिवारी ने कहा कि यहां यह विषय उल्लेखनीय है कि मप्र की बासमती धान का प्रकरण अभी मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है एवं अभी तक मप्र की बासमती को जीआई टैग नहीं दिया गया है।

हरियाणा प्रदेश हैफेड द्वारा भारी मात्रा में मप्र



मप्र के बासमती अपने नाम से बेच रहा हरियाणा

बासमती का आकर्षण

मप्र के किसानों ने दो वजहों से बासमती उगाना शुरू किया। पहला, उत्तर भारत खासकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उप्र के कई किसानों ने वहां अपनी जमीन बेच दी क्योंकि जमीन छोटे-छोटे खंडों में बंट रही है और इस वजह से कम मुनाफा दे रही थी। उन्होंने मप्र में सस्ते दरों पर ज्यादा बड़ी जमीन खरीदी ली। वे अपने साथ उच्चतर कृषि तकनीकें लेकर आए और बासमती जैसी फसलें भी ले आए। उनकी कामयाबी को देखकर स्थानीय किसान भी बासमती उगाने लगे। दूसरा यह कि ब्रांडेड चावल कंपनियों ने राज्य के कई इलाकों में इस फसल की शुरुआत की। इसके लिए उन्होंने प्रदर्शन किए, परीक्षण किए और बीज तक वितरित किए। इस उत्पाद की विदेशों, खासकर खाड़ी के देशों, यूरोप और अमेरिका में बहुत मांग है। ब्रांडेड चावल कंपनियों ने मप्र से धान की खरीद शुरू कर दी। इसे वे अपने संयंत्रों में प्रसंस्कृत करने लगे और चावल का निर्यात करने लगे।

की बासमती क्रय करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि बासमती के ट्रेड (व्यवसाय) में गुणवत्ता की दृष्टि से मप्र की बासमती को प्राथमिकता (प्रिफरेंस/वरीयता) दी जाती है। उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में यह उचित होगा कि केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा उक्त तथ्यों का संज्ञान लेते हुए मप्र के किसानों के हित में मप्र शासन के प्रस्ताव अनुसार प्रदेश के प्रस्तावित जिले के किसानों द्वारा लगाई जाने वाले बासमती को अविलम्ब जीआई टैग उपलब्ध कराए, ताकि प्रदेश के किसानों को जीआई संकेतक का लाभ मिल सके। उच्चतम न्यायालय ने मप्र के प्रकरण को

देखकर 2 सितंबर 2021 को मद्रास उच्च न्यायालय चेन्नई को यह निर्देश दिए हैं कि प्रकरण को नए सिरे परीक्षण या सुनवाई की जाए। उल्लेखनीय है कि मप्र के प्रकरण को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 27 फरवरी 2020 को खरीज कर दिया गया था। इसके विरुद्ध मप्र शासन तथा मप्र क्षेत्र बासमती ग्रोबर एसोसिएशन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अलग-अलग याचिकाएं प्रस्तुत की थीं और उनकी याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय ने 2 सितंबर 2021 को उक्त आशय के निर्देश दिए कि मप्र के प्रकरण को नए सिरे से सुना जाए और उनके द्वारा खारिज करने संबंधी मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश को अटैच कर दिया।

कॉपीराइट, पेटेंट या ट्रेडमार्क की तरह जीआई एक बौद्धिक संपदा अधिकार है जो किसी उत्पाद को एक खास टैग प्रदान करता है जिससे उसके मूल्य समेत उसके निर्यात की संभावना भी बढ़ जाती है। भारत ने विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होने के नाते 1994 के ट्रेड-रिलेटेड आसपेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स (टीआरआईपीएस) समझौते की शर्तों के अनुसार, 1999 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स (रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन) कानून बनाया था। यह कानून 2003 से प्रभाव में आया। किसी उत्पाद को जीआई दर्जा मिलने के बाद दूसरे उत्पादक अपने माल को असली नहीं बता सकते। कुछ व्यक्तियों का समूह, संगठन या अधिकरण चेन्नई में रजिस्ट्रार के यहां जीआई टैग के लिए आवेदन करने के योग्य होते हैं, जिसके लिए उन्हें बताना होता है कि उनके उत्पाद को इसकी जरूरत क्यों है। शुरुआती जांच के बाद आवेदन जीआई जर्नल में प्रकाशित होता है। अगर कोई आपत्ति न हो, तो उस विशेष जीआई टैग के लिए मंजूरी दे दी जाती है। इस फैसले के खिलाफ अगर कोई अपील होती है तो उसे चेन्नई में बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड (आईपीएबी) के पास भेजा जाता है।

● श्याम सिंह सिकरवार

म प्र पावर जनरेंटिंग कंपनी के ताप विद्युत गृह में कोयले की राखड़ का निष्पादन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार फ्लाई ऐश का उपयोग सड़कों और भवनों के निर्माण में किया जाना चाहिए, लेकिन ताप विद्युत गृहों से निकलने वाली राख सीमेंट कंपनियों को बेची जा रही है। कांग्रेस विधायक ब्रह्मा भलावी ने थर्मल पावर प्लांटों पर सीमेंट उद्योगों को राख बेचने का आरोप लगाया है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2021 को अधिसूचना जारी करते हुए कहा था कि ऐसे सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी और निजी विभाग जो सड़क बिछाने, सड़क और फ्लाई ओवर के किनारों और लिग्नाइट या कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र से 300 किमी के भीतर बांधों के निर्माण संबंधी कार्यकलापों में लगे हुए हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से राख का उपयोग किया जाना है। परियोजना स्थल पर निशुल्क राख पहुंचाई जाएगी।

जानकारी के अनुसार श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह खंडवा में 12 हजार टन प्रतिदिन निकलती है। वहीं सारणी ताप विद्युत गृह से 2500 टन प्रतिदिन, बिरसिंहपुर ताप विद्युत गृह से आठ हजार टन प्रतिदिन, अमरकंटक ताप विद्युत गृह से 700 टन प्रतिदिन राख निकलती है। प्रदेश के ताप विद्युत केंद्रों से निकलने वाली लाखों मीट्रिक टन फ्लाई ऐश को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। केंद्र सरकार के निर्देश हैं कि थर्मल पावर से निकलने वाली फ्लाई ऐश का उपयोग सड़कों और भवनों के निर्माण में किया जाए। बावजूद ज्यादातर प्लांटों से राख सीमेंट कंपनियों को बेची जा रही है। उधर, सड़कों के निर्माण में आसपास अथवा पहाड़ों की मिट्टी खोदकर मिलाई जा रही है। जिससे पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तापीय विद्युत गृहों के पास वर्तमान में लाखों मीट्रिक टन राख जमा है। अकेले सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट ग्राम दोंगालिया जिला खंडवा में हर दिन औसतन 12,693 मीट्रिक टन से अधिक राख उत्पन्न होती है। लेकिन इसने वर्ष 2019 से अबतक एक भी निर्माण कंपनी को राख उपलब्ध नहीं कराई है। झाबुआ पावर लि. बरेला जिला सिवनी, सासन पावर लि. ग्राम सिद्धिखुर्द सिंगरौली, जेपी निगरी सुपर थर्मल पावर प्लांट निगरी सिंगरौली, महान इनर्जन और जेपी बीना थर्मल पावर सिरचोपी सागर ने भी सड़कों के लिए राख उपलब्ध नहीं कराई है।

जानकारी के अनुसार थर्मल पावर निर्माण कंपनियों को इसलिए राख उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, क्योंकि सीमेंट फैक्ट्रियों को बेचने से लाखों का फायदा होता है। बिचौलियों के सक्रिय होने से राख की हेरा-फेरी होती है। इससे प्लांट के अफसरों की कमाई होती है। हालांकि जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 से नवंबर 2022 तक के



सीमेंट कंपनियों को बेची जा रही राख

मृत्त की राख से महाराष्ट्र में बन रहे सड़क, भवन

उधर, महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी की सड़क और इमारत में मृत्त की राख उपयोग हो रही है। मृत्त के ताप विद्युत गृह में जले हुए कोयले की राख का इस्तेमाल हो रहा है। पहली बार प्रदेश से राख को मालगाड़ी में भेजा गया है। पिछले कुछ दिनों में मृत्त से 80 हजार टन के आसपास राख महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे में भेजी गई है। बिजली कंपनी नए साल के पहले माह में एक लाख बीस हजार टन राख और देश के अलग-अलग इलाकों में भेजने की उम्मीद जाहिर कर रहा है। बिजली कंपनी को मालगाड़ी से राख भेजना सड़क मार्ग से सस्ता पड़ रहा है। अभी करीब 145 रुपए टन ट्रेन में खर्च आ रहा है जबकि सड़क पर ये खर्च 400 रुपए टन होता है। सारनी के सतपुड़ा थर्मल पावर हाउस और खंडवा के सिंगाजी थर्मल पावर हाउस से मालगाड़ियों के जरिए यह राख मुंबई भेजी जा रही है। सारनी पावर हाउस से 4000 मीट्रिक टन राख की एक खेप हाल ही में पुणे होती हुई मुंबई भेजी गई है। मृत्त पावर जनरेशन कंपनी के प्रबंध संचालक मनजीत सिंह ने कहा कि पर्यावरण के लिहाजा से ताप गृह से निकलने वाली राख का शत-प्रतिशत निष्पादन होना आवश्यक है। यदि निष्पादन नहीं हुआ तो हजार रुपए प्रति टन की दर से जुर्माना लगाया जाता है। इस वजह से राख का निष्पादन करने का प्रयास हो रहा है। उनके अनुसार राख का इस्तेमाल ब्रिक्स बनाने, सीमेंट कंपनी, भवन और सड़क निर्माण के लिए होता है। अभी मुंबई के अलावा कुछ जगह मालगाड़ी से करीब 20 रैक सप्लाई किया जा चुका है। अभी इन दोनों थर्मल पावर हाउस की राख से मुंबई में सड़कों के निर्माण का काम हो रहा है। साथ ही यह राख सीमेंट फैक्ट्रियों में भी सप्लाई की जा रही है।

बीच एमबी पावर अनूपपुर ने अनूपपुर से व्यंकटनगर और अनूपपुर से मनेंद्रगढ़ मार्ग के लिए 1105 मी. टन राख उपलब्ध कराई है। एनटीपीसी सिंगरौली ने वाराणसी एनएच 29 बायपास के लिए 7,60,977, एमओआरटीएच प्रयागराज एनएच 330 के लिए 89,350 पटना एनएच 319 को 41,791 और डाल्टनगंज एनएच 75 व 98 के लिए 27,729 मी. टन राख उपलब्ध कराई है। वहीं सतपुड़ा सारणी में वर्ष 2021-22 में एनएच 69 इटारसी से बैतूल खंड निर्माण हेतु 23,476 मी. टन, एनटीपीसी खरगोन ने वर्ष 21-22 में धनगांव-बोरगांव सेक्शन, एनएच 347 बीजी एवं 753 एल के लिए दो लाख मी. टन, गाडरवारा थर्मल नरसिंहपुर ने वर्ष

21-22 में एनएचआई-47 एवं 30 की सड़क निर्माण परियोजना को 5,70,000 मीट्रिक टन राख उपलब्ध कराई है। सिंगाजी थर्मल पावर खंडवा के सीई आरपी पांडेय का कहना है कि थर्मल पावर से राख उपलब्ध कराने का मामला प्रोसेस में है। तीन माह पहले टेंडर एप्रूवल के लिए उच्च स्तर पर भेजा है। निर्माण कंपनियां ही फ्लाई ऐश नहीं ले रही हैं। आसपास और पहाड़ों की मिट्टी खोद लेते हैं। हमें मजबूरी में सीमेंट प्लांट देना पड़ता है। ठेकेदार फ्री में भी नहीं उठा रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि राख निर्माण स्थल पर पहुंचाए, इसलिए भी ठेकेदार गंभीर नहीं हैं।

● अरविंद नारद

6

हाल ही में चलाए गए मतदाता सूची में नाम जोड़ने के अभियान के आंकड़े अब सामने आ गए हैं। इनमें सूबे में सर्वाधिक मतदाता युवा वर्ग के सामने आए हैं। अब यही युवा तय करेंगे कि मप्र में अगली सरकार किसकी बने। यही वजह है कि इन आंकड़ों के सामने आने के बाद अब भाजपा व कांग्रेस ने भी युवाओं को साधने के प्रयास तेज कर दिए हैं। आयोग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में इस बार जो मतदाता सूची अपडेट की गई है उसमें 18 से 39 साल के युवा मतदाताओं की संख्या 2.83 करोड़ पाई गई है। यह प्रदेश के कुल मतदाताओं की संख्या के हिसाब से करीब 52 फीसदी होते हैं। यानि कि जिस दल को प्रदेश में युवाओं का साथ मिल जाएगा उसकी सरकार बनना तय हो जाएगी।



मप्र में कुल मतदाताओं की संख्या 5 करोड़ 39 लाख 87 हजार है, वहीं इनमें से 11 लाख 81 हजार मतदाता इस बार चुनाव में पहली बार मतदान करेंगे। यही वजह है कि बेरोजगारी जैसे मामले को लेकर

सरकार जहां अब पूरी तरह से संजीदा दिखने लगी है तो विपक्ष इस मामले को बड़ा मुद्दा बनाने के प्रयास में लगा है। इतना ही नहीं प्रदेश सरकार को भी अब युवा नीति बनाने की याद आने लगी है। युवाओं की इतनी बड़ी तादाद को देखते हुए ही कांग्रेस ने अभी से बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। हर जगह इस मुद्दे को कांग्रेस तूल दे रही है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि, प्रदेश में आने वाली कंपनियों में प्रदेश के युवाओं को रोजगार के मौके नहीं मिल पा रहे, जबकि सरकार दावा करती है कि प्रदेश में आने वाली कंपनियों में सिर्फ प्रदेश के युवाओं को ही मौके मिलेंगे। जबकि हकीकत यह है कि सिर्फ कुछ फीसदी प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल पा रहा है, प्रदेश में करीबन 29 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं, सरकार को सभी को रोजगार देना चाहिए।

आगामी विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी मुद्दा न बने, इसके लिए प्रदेश सरकार पहले से ही जुट गई है। प्रदेश में 1 लाख 10 हजार पदों पर भर्तियों की जा रही हैं, जो अगस्त माह तक पूरी कर ली जाएंगी। साथ ही सरकार की कोशिश इन भर्तियों को डेढ़ लाख तक पहुंचाने की है, इसके अलावा

युवा बनवाएंगे अगली सरकार

प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के लिए लगातार रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। पिछले साल सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ-विक्रेता योजना, संत रविदास स्व-रोजगार योजना, मुख्यमंत्री

युवा इंटरनशिप योजना, मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना जैसी कई योजनाएं शुरू की गई हैं। वहीं प्रदेश सरकार इसी माह युवा नीति भी लाने जा रही है, इसके लिए कॉलेज स्तर पर युवाओं से संवाद किया जा रहा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी के मुताबिक सरकार युवा सहित सभी वर्गों का पूरा ख्याल करती है, सभी वर्गों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन योजनाओं का लोगों को पूरा लाभ मिल सके, इसकी भी चिंता सरकार कर रही है।

बीते विधानसभा चुनाव में बाहरी प्रत्याशियों की वजह से कई सीटों पर जमानत गंवाने वाली कांग्रेस ने सबक लेते हुए इस बार स्थानीय नेताओं को ही प्रत्याशी बनाए जाने का तय किया है। इसकी वजह से उन क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं ने राहत की सांस ली है, जहां पर बाहरी नेताओं की वजह से स्थानीय नेता चुनाव लड़ने से वंचित हो रहे थे। खास बात यह है कि कांग्रेस द्वारा बाहरी प्रत्याशियों को टिकट देने के किए गए प्रयोग से कांग्रेस को कई अपनी परंपरागत सीटों से भी हाथ धोना पड़ा है। इनमें निवाड़ी और वारा सिवनी का उदाहरण कांग्रेस के सामने है। यही वजह है कि कांग्रेस ने अब इस तरह

18 लाख से अधिक मतदाता जुड़े

निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़वाने के लिए चलाए गए अभियान में इस बार 18.39 लाख मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। इनमें भी 1 लाख 8 हजार मतदाता ऐसे हैं, जो 17 साल से ऊपर हैं और 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले 18 साल की उम्र पूरी कर लेंगे, जिससे उन्हें भी मतदान करने का अधिकार मिल जाएगा। इसी तरह से प्रदेश में 18 से 19 साल के मतदाताओं की संख्या 11.81 लाख है और यह पहला मौका होगा, जब वे अपने मताधिकार का पहली बार उपयोग करेंगे। अगर 20 से 29 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या देखें तो उनका आंकड़ा 1.29 करोड़ और 30 से 39 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 1.44 करोड़ है, इस तरह देखा जाए तो प्रदेश में 18 से 39 साल के युवा वोट 2.83 करोड़ हैं। इन वोटर्स में कॉलेज जाने वाले से लेकर बेरोजगार, नौकरीपेशा और काम-धंधा करने वाले युवा तक शामिल हैं। इसके अलावा पहली बार वोट डालने वाले युवा वोटर्स की संख्या कुल मतदाताओं के हिसाब से करीबन 2 फीसदी होती है। इसकी वजह से यह तो तय है कि प्रदेश में सरकार किसकी बने यह युवा ही तय करेंगे। अगर बीते चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो भाजपा और कांग्रेस के बीच हार-जीत का अंतर बेहद मामूली यानि की एक फीसदी से भी कम रहा था। उस समय भाजपा को 41.0 प्रतिशत, जबकि कांग्रेस को 40.9 फीसदी मत मिले थे। इससे यह तो तय है कि पहली बार मतदान करने वाले युवाओं का हार जीत में बड़ा रोल रहने वाला है।

के प्रयोग से तौबा कर ली है। इस मामले की जानकारी खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मीडिया को चर्चा में दी है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस स्थानीय लोगों को ही टिकट में प्राथमिकता देगी। यानी बाहरी को संबंधित विधानसभा क्षेत्र में मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि जो लोग जमीन पर अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें टिकट दिया जाएगा। कमलनाथ ने कहा कि जिन सीटों पर कांग्रेस कई चुनाव से लगातार हार रही है, वहां से भी फीडबैक मिल रहा है कि जनता अब बदलाव चाहती है। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस में गुटबाजी से इनकार करते हुए कहा कि कोई किसी नेता का ज्यादा करीबी होता है। कोई किसी दूसरे नेता का। जब पूछा गया कि कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी। इस पर उन्होंने कहा कि मैं शिवराज सिंह की तरह घोषणाएं नहीं करता, पर नेता-कार्यकर्ताओं के साथ ही जनता में जबरदस्त उत्साह है। सतना में आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में अजय सिंह के न पहुंचने के सवाल पर नाथ ने कहा कि वे कहीं व्यस्त थे। सूचना उन्होंने दे दी थी। सांसद प्रज्ञा ठाकुर के हेट स्पीच पर कहा कि भाजपा को सोचना चाहिए कि जड़ कहां है। माई के लाल वाले बयान से कांग्रेस को फिर फायदा होगा, इस पर नाथ ने कहा कि सरकार को सबसे बातचीत करनी चाहिए।

कांग्रेस एक-एक विधानसभा सीट की जमीनी हकीकत देख रही है। सर्वे का भी सहारा लिया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नाथ 50 सीटों का फीडबैक भी ले चुके हैं। नाथ ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जनता से बहुत सारी जानकारी मिल जाती थी। पूछता था कि कहां से हो, बताओ आपके यहां कौन ठीक रहेगा। सर्वे कराने पर कहा- सर्वे हमेशा होते हैं, लेकिन वे सिर्फ इशारा होता है। लंबे समय से हार रही सीटों पर छह माह पहले टिकट देने के सवाल पर कहा इस पर हम सबसे चर्चा कर रहे हैं।

कमलनाथ ने कहा है कि जिस तरह से भाजपा सरकार अधिकारियों और पुलिस पर दबाव बनाकर काम करवा रही है, इससे काफी संकट की स्थिति बनती जा रही है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अधिकारी-कर्मचारी प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों की बैठक में उन्होंने यह बात कही। नाथ ने वादा किया कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते ही पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकारों द्वारा समाज में बिखराव किया जा रहा है। भाषा का विरोध किया जा रहा है। धर्म को बांटा जा रहा है। खालिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं। आज जो तस्वीर हमारे सामने है, उसे बदलने हमें हमारी संस्कृति और संविधान का रक्षक बनना होगा। भाजपा की राजनीति गुमराह करने ओर ध्यान मोड़ने की है। प्रदेश में शिवराज सरकार में तो भ्रष्टाचार का ऐसा आलम है कि आज पैसा, पुलिस और प्रशासन की राजनीति हो



बूथ लेवल एजेंट और प्रभारी होंगे नियुक्त

कांग्रेस भी सत्ता में वापसी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए पूरा ध्यान मतदान केंद्रों पर स्थिति को मजबूत करने पर लगाया जा रहा है। जिला स्तर पर विभिन्न सहयोगी संगठनों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए पहली बार जिलों में संगठन मंत्री नियुक्त किए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अब जिला और ब्लाक इकाइयों को निर्देश दिए हैं कि मतदान केंद्र स्तर पर पन्ना प्रभारी नियुक्त किए जाएं। प्रत्येक केंद्र पर मतदाता सूची का सत्यापन हो और जो भी ऐसा नाम पाया जाए, जो वहां नहीं रहता है या गलत दर्ज है तो उसकी लिखित शिकायत निर्वाचन अधिकारियों से करने के साथ रिपोर्ट प्रदेश कार्यालय को भेजी जाए। मोर्चा-प्रकोष्ठों के प्रभारी महामंत्री जेपी धनोपिया ने बताया कि 64 हजार 100 मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल एजेंट और प्रभारी नियुक्त किए जा रहे हैं। कुछ जिला और ब्लॉक इकाइयों ने बूथ लेवल एजेंट नियुक्त कर दिए हैं। मतदाता सूची का सत्यापन भी कराया जाएगा। इसके लिए पन्ना प्रभारी नियुक्त होंगे। वहीं प्रदेश कांग्रेस ने जिलों में संगठनों के बीच समन्वय के लिए अभी 16 जिला संगठन मंत्री नियुक्त किए हैं। 10 संगठन मंत्री एक-दो दिन में नियुक्त हो जाएंगे। इसके बाद अन्य जिलों में भी नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए उन नेताओं को चयन किया जा रहा है, जो चुनाव नहीं लड़ेंगे।

रही है। यदि आपको संस्कृति और संविधान को बचाना है तो अगले सात माह के लिए अपना कार्यक्रम बनाएं, भाजपा की ध्यान मोड़ने की राजनीति का जवाब हमें जनता के बीच जाकर देना है। मप्र कांग्रेस पूर्व अधिकारी-कर्मचारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डीएस राय ने कहा कि हमें आदिवासियों को और जोड़ना होगा। भाजपा ने

आदिवासियों का नाम बदलकर वनवासी कर दिया है। इससे उनकी पहचान ही बदल दी है। आरोप लगाया कि भाजपा हमेशा से कर्मचारियों की विरोधी रही है।

मिशन-2023 यानी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस फतह हासिल कर मप्र में फिर से सरकार बनाने के प्रयास में लगी है। इसके लिए पार्टी भाजपा की तर्ज पर विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रही है। हर एक वोटर तक पहुंचने के लिए कांग्रेस पन्ना प्रभारी बनाने जा रही है। प्रदेश में 64 हजार 100 मतदान केंद्र हैं। प्रदेश कांग्रेस ने सभी वर्गों में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए पार्टी पन्ना प्रभारी बनाएगी। चुनाव के दृष्टिगत सभी स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। मतदान केंद्रवार जानकारी भी तैयार करवाई जा रही है। पार्टी को उम्मीद है कि मिशन 2023 में कांग्रेस की जीत के शिल्पकार पन्ना प्रभारी बनेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश में वोटर लिस्ट में 18 लाख पन्ने हैं, जो बढ़कर 20 लाख के करीब पहुंचने की उम्मीद है। इसको देखते हुए ही प्रदेश में ही कांग्रेस को एक करोड़ से अधिक पन्ना समिति सदस्यों की आवश्यकता होगी। यह एक बड़ा नंबर है, जिसे कांग्रेस हासिल करना चाहती है। यदि यह सफल हो जाती है तो उसके पास सदस्य के प्रति परिवार तीन वोटर के हिसाब से सीधे-सीधे तीन करोड़ वोट होंगे। अब कांग्रेस की तरफ से कोई ना कोई घर-घर तक जाएगा और लोगों से संवाद स्थापित करेगा।

बता दें इसमें पन्ना प्रमुख की भूमिका अहम होगी। पन्ना प्रमुख हर वोटर से मिलकर और फोन से संपर्क करता है। जब तक उसके पन्ने का आखिरी वोटर मतदान तक नहीं पहुंच जाता है, उसकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। चुनाव शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद हर पन्ना प्रमुख रिपोर्ट तैयार करता है। उसके फीडबैक के आधार पर तय होता है कि कितने लोगों ने पार्टी के पक्ष में मतदान किया। इससे जीत की संभावना का अंदाजा भी लगाया जाता है।

● डॉ. जयसिंह सेंधव

ती न दशक पहले बना भोपाल में भाजपा का प्रदेश कार्यालय जमींदोज होना शुरू हो गया है। इसकी जगह डेढ़ सौ करोड़ की लागत से नया आलीशान और हाईटेक नया भवन बनाया जाएगा। यह भवन दस मंजिला होगा, जिसकी छत पर हेलीकॉप्टर भी उतर सकेगा। उधर, इस भवन को तोड़े जाने पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और इस भवन निर्माण से जुड़े रहे पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा ने इस पर आपत्ति जताते हुए इसे अनर्थ बताया है। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए नए भवन के बेसमेंट में 500 से अधिक वाहनों की पार्किंग और मुख्य कार्यालय को वार-रूम की तर्ज पर बनाया जाएगा। भाजपा संगठन ने इस महत्वाकांक्षी मेगा प्रोजेक्ट को विधानसभा चुनाव 2023 के पहले पूरा करने का टारगेट रखा है।

भवन के कुछ हिस्से के कॉमर्शियल उपयोग की प्लानिंग भी है। सत्ता-संगठन के दिग्गज नेताओं और पार्टी हाईकमान के बीच नए प्रोजेक्ट को लेकर निर्णायक चर्चा के बाद इसकी डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया है। मौजूदा बिल्डिंग को जमींदोज कर बेसमेंट में पार्किंग बनाने के लिए खुदाई का काम किया जाना है। पार्टी सूत्रों का कहना है निर्माण कार्य जल्द ही पूरा हो सके, इसलिए दिन-रात काम शुरू कराया जा रहा है। मिशन 2023 के पहले धूमधाम के साथ भाजपा नए कार्यालय भवन में प्रवेश की तैयारी कर चुकी है। नए भवन पर कितना खर्च होगा। इसका अधिकृत रूप से अब तक कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि नई बिल्डिंग जी प्लस 8 बनाई जा रही है, जिसमें करीब 5 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन होने का अनुमान है। कंस्ट्रक्शन क्षेत्र से जुड़े लोगों का प्रारंभिक अनुमान है कि पूरा प्रोजेक्ट 150 करोड़ रुपए के बीच पहुंचेगा।

राजधानी के बीचों-बीच करीब दो एकड़ के विशाल भूखंड पर स्थित मौजूदा कार्यालय भवन तीन दशक पहले बना था। हालांकि भवन बेहद मजबूत और व्यवस्थित है, लेकिन संगठन की जरूरतों व पार्किंग के लिहाज से भवन छोटा पड़ने लगा था। संगठन के पदाधिकारियों को बैठने के लिए कक्षों की कमी के अलावा आईटी और सोशल मीडिया की भावी जरूरतों के हिसाब से जगह नहीं थी। बड़े कार्यक्रम अथवा बैठकों के दौरान प्रदेश के सभी जिलों से जब पदाधिकारी आते हैं तो मुख्यालय के बाहर लिंक रोड पर जाम लग जाता है। स्व. कुशाभाऊ ठाकरे चाहते थे, भाजपा का अपना कार्यालय हो। इसके लिए जमीनें देखी गईं। तब तक स्व. सुंदरलाल पटवा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को आवेदन दे दिया। स्व. सिंह ने पीएनटी चौराहे पर भाजपा कार्यालय के लिए जमीन दे दी। चुनाव आए और भाजपा की सरकार बन गई।

हाईटेक होगा भाजपा कार्यालय



पार्टी के अन्य कार्यालय भी संवारे

भाजपा ने पिछले कुछ सालों में अपने पार्टी दफ्तरों पर फोकस किया है। राजधानी दिल्ली में 8000 वर्ग मीटर में हाईटेक ऑफिस फरवरी 2018 में शुरू किया गया। इसी तरह मप्र के जबलपुर ऑफिस को भी नई रंगत दी गई। इसके साथ ही भोपाल स्थित जिला कार्यालय को भी संवारा जा चुका है। गौरतलब है कि भाजपा के वर्तमान भवन की नींव तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के कार्यकाल में 1991 रखी गई थी। इस भवन को बनने में करीब दो साल का वक्त लगा था। तब करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से 74 हजार वर्गफीट में परिसर का निर्माण हुआ था। इसमें 20 हजार वर्ग फीट पर कार्यालय और 19 हजार वर्गफीट पर आवास और करीब 27 हजार वर्गफीट पर कुछ दुकानों समेत अन्य निर्माण किया गया था। समय के साथ यह दफ्तर पुराना हो गया था और संगठन की अन्य जरूरतों के हिसाब से यह छोटा पड़ने लगा था। इमारत सिर्फ 27 साल पुरानी है लेकिन पार्टी अब इसे तमाम आधुनिक साधनों से सुसज्जित करना चाहती है। फिलहाल आरटीओ की पुरानी इमारत से ही भाजपा का काम किया जा रहा है। भोपाल स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय से पार्टी के दिग्गज नेताओं की कई यादें भी जुड़ी हैं। भाजपा की पहली राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक भी इसी मुख्यालय में हुई थी। उस समय अटल और आडवाणी इस कार्यसमिति की बैठक में शामिल हुए थे। लेकिन बदलते जमाने के साथ भाजपा हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ अब नई बिल्डिंग का निर्माण कर रही है। कुछ महीने पहले ही भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने भाजपा मुख्यालय को तोड़कर नया मुख्यालय बनाने का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी निरीक्षण किया था।

सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री बने। तब मौजूदा कार्यालय वाली जगह मिली। यह हाउसिंग बोर्ड की थी। भाजपा की पहली राष्ट्रीय कार्यसमिति बैठक इसमें हुई। तब अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी भी आए थे। इस भवन का निर्माण 1995-96 में किया गया था। उस समय भवन ढाई करोड़ में बनना था। प्रदेशभर के कार्यकर्ताओं से दो करोड़ एकत्रित हुए। 50 लाख कम पड़े तो दुकानें देकर राशि जुटाई। उस समय शैलेंद्र प्रधान पर इंजीनियरिंग, उमाशंकर गुप्ता पर हिसाब-किताब और जयंत ठाकरे पर गुणवत्ता का जिम्मा था। समन्वय का काम भंवर सिंह शेखावत ने किया था।

माणिकचंद चौबे और नानूराम दादा ने पहले प्रारंभिक भूमिपूजन किया था, क्योंकि जनसंघ के सबसे पुराने कार्यकर्ता यही थे। बाद में

राजमाता ने विधिवत इसका भूमिपूजन किया था। दरअसल उस समय भाजपा के पास दफ्तर नहीं था, जिसकी वजह से कुशाभाऊ ठाकरे मानसिक रूप से परेशान रहते थे। कुशाभाऊ ठाकरे, लखीराम कांवरे और सुंदरलाल पटवा ने ही यह जगह चुनी थी। इस मामले में रघुनंदन शर्मा का कहना है कि इतना मजबूत और पुराना कार्यालय टूटना नहीं चाहिए था। इस भवन को तोड़ जाने का भाजपा के पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा ने कड़ा विरोध किया था और उन्होंने इसे न तोड़े जाने को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर अन्य वरिष्ठ नेताओं को पत्र भी लिखा था। इसके अलावा परिसर के बाहर तरफ के दुकानदारों ने भी इसका विरोध किया था पर पार्टी ने इस पर ध्यान नहीं दिया।

● लोकेंद्र शर्मा

ढे श में मनरेगल योजनल इसललए ललगू की गई है, तलकल ग्रलमीण बेरोजगलरों को अधलक से अधलक रोजगलर मलल सके। लेकलन इसके इतर मनरेगल की योजनलओं में ही मजदूरों की बजलय मशीनों से कलम करलय जल रहल है। ऐसल ही मलमलल प्रदेश के रलयसेन जलले में सलमने आलय है। यहलं मनरेगल के तहत बनने वलली सडुक और स्टलप डैम के नलरुमलण में न केवल नलयनों को तलर-तलर कलय गलय, बल्ललक मजदूरों की जगह मशीनों से कलम करवललय गलय। यही नहलं अधलकलरलयों ने मललीभगत कर योजनल को जमकर पलीतल लगलय। इस मलमले की शलकलयत पंचलयत एवं ग्रलमीण वलकलस मंत्री, रलज्यमंत्री, प्रमुख सचलव और आयुक्त से भी की गई। शलकलयत के बलद जब अधलकलरलयों ने इसकी जलंच की तो इसमें कई तरह की खलमलयलं सलमने आई हैं।

ग्रलमीणों दुरलरल की गई शलकलयत के अनुसलर गोपीसुर से हथलयरल टोलल तक सडुक नलरुमलण स्वीकृतल के पूर्व प्रचललत मलरुग वलवलदलस्पद होने के करलण स्थलनीय कृषकों दुरलरल ललगभग 1 कलमी के मलरुग नलरुमलण हेतु अपनी नलजल भूमल शलसन को हस्तलंतरलत कर स्वयं के वलय से जेसीबी मशीन दुरलरल आवश्यक करलय जैसे समतलीकरण, सलफ-सलफलई एवं गडुढे भरलई कलय जलकर नवलन मलरुग को प्रचललत कलय गलय, जलस पर 15 हजलर रुपए कल वलय कृषकों के दुरलरल स्वयं कलय गलय। अतः सडुक नलरुमलण की स्वीकृतल पश्चलत करलय एजेंसी दुरलरल जंगल सलफलई के नलम पर कलय गलय वलय फर्जी है। पूर्व से प्रचललत मलरुग के दोनों और कलसनों की नलजल भूमल पर जेसीबी मशीन से खुदलई की जलकर अर्थवर्क कल करलय संपलदलत कलय गलय, लेकलन इसमें नलधलरलत चौडलई कल धयलन नहलं रखते हुए कई जगह अत्यंत सकरी सडुक बनलई गई है, जो कई जगह से कटने लगी है। अर्थवर्क के दुरलरलन पलनी डललकर अच्छी तरह कम्पेक्शन कल करलय नहलं कलय गलय, परलणलम स्वरूप सडुक पर कई जगह बडे-बडे गडुढे हो गए हैं एवं जगह-जगह सडुक कटने लगी है।

अर्थवर्क पश्चलत गोपीसुर से हथलयरल टोलल तक नलरुमलत अर्थवर्क पर स्लेक्टेड मटेरलयल कल उपयोजन न करते हुए मुरम-कोपलरल के स्थलन पर ललल मलटुटी डलली गई, वह भी 3 से 4 इंच डललनल पलय गलय है। उपयोजन की गई सलमग्रल गुणवत्तलहीन होने के करलण बरसलत के दलनो में कुछ बह गई तथल कुछ अर्थवर्क में धंस गई, जलसकी वजह से जगह-जगह बडे-बडे गडुढे नलरुमलत हो गए हैं। यहलं भी तकनीकी स्वीकृतल अनुसलर पलनी कल उपयोजन कर अच्छी तरह कम्पेक्शन नहलं कलय गलय।

हथलयरल घलट के नलले पर तैयलर की गई रपटल पुललयल में ललगलए गए पलडप की फललटलंग प्रॉपर नहलं की गई है। पलडप ललगने के बलद 2 से पलडप के मध्य खलली जगह पर नलरुमलण स्थल के बगल



मजदूरों की जगह मशीनों से काम

स्टलपडैम में खलमलयलं ही खलमलयलं

शलकलयत के बलद करलयलय अधीक्षण यंत्री ग्रलमीण यलंत्रलकीय भोपल के अधीक्षण यंत्री सज्जन सलंह चौहलन ने मौकल मुआयनल कर जो नलरीक्षण प्रतलवेदन तैयलर कलय गलय है, उसके अनुसलर स्टलपडैम लखनपुर में खलमलयलं ही खलमलयलं नजर आई। स्टलपडैम दोनों तरफ से कट गलय है। वहलं सूचनल बर्ड नहलं लगलय गलय है, जलससे यह स्पष्ट नहलं होता है कल यह वही संरचनल है। सलथ ही सलथ उक्त स्टलपडैम स्थल 20 से 15 मीटर लंबलई में ही बनल है। जबकल प्रलंकलन 65 मीटर लंबलई कल बनल हुआ है। स्थल चयन सही नहलं है। दोनों तरफ के कलनलर उथले तथल कमजोर हैं। स्टलपडैम की डुरलइंग पढने योग्य नहलं है। डलजलइन, टोपोशीट, सलइट प्ललन आदल कुछ नहलं है। तकनीकी स्वीकृतल जलरल करने वलले अधलकलरल दुरलरल कलसी भी तरह कल परीक्षण तकनीकी स्वीकृतल जलरल करते समय नहलं कलय गलय है। स्टलपडैम में प्रयुक्त कड़ी शटर नलधलरलत गेट एवं मलपडंड कल नहलं होकर नलमन स्तर कल है। स्टलपडैम नलरुमलण में कलय गलय संपूर्ण वलय नलष्फल होकर वसूली योग्य है।

की मलटुटी खुदलई की जलकर भर दी गई। जबकल यहलं स्लेक्टेड मटेरलयल से भरलई कलय जलकर प्रॉपर कम्पेक्शन कलय जलनल चललए थल। रपटे पर कलंक्रीट कल करलय कलए जलने के पूर्व उक्त लूज स्वलयल की सलफलई न की जलकर उसी पर मुरम वलखलकर बगैर अच्छी तरह धम्मस कलए कलंक्रीट

कर दलय गलय। मई के मलह में कलंक्रीट करने के पश्चलत दूसरे दलन उक्त कलंक्रीट पर पलनी भरकर तरलई की गई, जो मलत्र 3 दलन तक ही रही। जबकल उक्त कलंक्रीट पर कम से कम 15 से 20 दलन पलनी की तरलई की जलनी चललए थी, जो नहलं की गई, परलणलमतः गुणवत्तल प्रभलवलत होनल स्वलभलवलक है।

हथलयरल घलट से अगरलयल तक नलरुमलत अर्थवर्क पर डलली गई सलमग्रल मुरम के नलम पर ललल मलटुटी एवं पक्के पत्थरों कल डंपरों से परलवहन कर टैक्टर के मलध्यम से फैललकर वलखलय गलय। पहली बलरलश होने पर ही वह ललल मलटुटी बहकर खेतों में चलती गई, शेष बचे पत्थर सडुक पर दलखलई दे रहे हैं। उपयोजन में ललए गए पत्थरों कल आकलर 60 से 100 एमएम से ललगलकर 50 कलगुरल, 80 कलगुरल-100 कलगुरल से 150 कलगुरल तक गोल पत्थर मौके पर देखे जल सकते हैं। इन पत्थरों की मलत्रल परलवहन कलए गए कुल मटेरलयल कल ललगभग 65 प्रतलशत है, शेष 35 प्रतलशत सलमग्रल अमलनक स्तर की ललल मलटुटी है। अतः मुरम-कोपलरल के नलम पर उपयोजन की गई समस्त सलमग्रल मलरुग नलरुमलण में सहायक न होकर अनुचलत गडुढों कल नलरुमलण भी करेगी और डलले गए पत्थर सडुक के समतल एवं सुगमतल के ललए बलधक होंगे। कई जगह इतनल कम मटेरलयल डललल गलय है कल अर्थवर्क की सतह तक स्पष्ट दलखलई दे रही है। हथलयरल घलट पुललयल के दोनों घलट सेक्शन में हलर्ड मटेरलयल नहलं डललने के करलण बलरलश के समय वलहनों के आवलगमन में कठनलई होती है।

● रलकेश ग्रोवर

अगर सबकुछ ठीक रहा तो भोपाल मप्र का पहला शहर होगा, जिसमें 2023 में लोग यह लाइन सुन सकेंगे कि अगला स्टेशन एम्स है...दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे...कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। नए साल में विधानसभा चुनाव से पहले भोपाल में मेट्रो ट्रेन दौड़ने लगेगी। भोपाल और इंदौर में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है। भोपाल में पहले ट्रायल और लोकार्पण होगा, वहीं स्थानीय दिक्कतों के चलते इंदौर में तीन महीने बाद लोग मेट्रो की सवारी कर सकेंगे। इंदौर में दिसंबर 2023 तक मेट्रो का ट्रायल हो जाएगा।

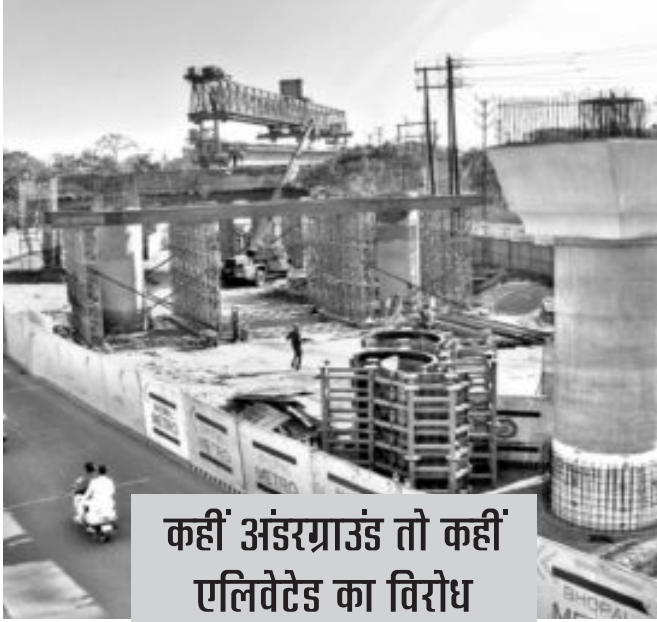
मप्र मेट्रो ट्रेन कॉर्पोरेशन के एमडी मनीष सिंह ने पिछले दिनों कोच खरीदी, पटरियां बिछाने से लेकर अन्य महत्वपूर्ण टेंडरों को मंजूरी दी है। इंदौर और भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 156 कोच की खरीदी की जाएगी, जिसमें से इंदौर के लिए 75 और भोपाल के लिए 81 कोच होंगे।

मेट्रो का पहला रूट एम्स से करोंद तक कुल 16.05 किलोमीटर लंबा है। इसमें से 6.22 किमी एम्स से सुभाषनगर के बीच का काम प्रायोरिटी कॉरिडोर के रूप में 2018 में शुरू हुआ था। इसका 80 प्रतिशत से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। 9 महीने में बाकी बचे 20 प्रतिशत काम को पूरा करने का टारगेट है। पिलर खड़े होने और गर्डर लॉन्चिंग के बाद मेट्रो कॉर्पोरेशन का पूरा फोकस डिपो और स्टेशन बनाने में है, क्योंकि इन्हीं में वक्त लगेगा। कोरोना के कारण काम रुका फिर भी इस साल सितंबर तक काम पूरा करने का दावा किया जा रहा है।

एम्स से सुभाष नगर अंडरब्रिज तक आठ स्टेशन बनने हैं। ये स्टेशन एम्स, अलकापुरी, डीआरएम ऑफिस, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, डीबी सिटी, एमपी नगर जोन-1, आयकर भवन और सुभाष नगर अंडरब्रिज में बन रहे हैं। सुभाषनगर में स्टेशन का काम जमीन से ऊपर दिख रहा है। स्टेशन 100 मीटर लंबे और कम से कम 14 मीटर चौड़े होंगे। इनका 90 प्रतिशत काम बाकी है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और डीबी सिटी जैसे चहल-पहल वाले स्थानों पर फुटओवर ब्रिज (एफओबी) बनेंगे।

भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट का तीसरा बड़ा काम डिपो का है, जो 323 करोड़ रुपये से सुभाषनगर अंडरब्रिज के पास स्टड फॉर्म की 26.41 हेक्टेयर (65.26 एकड़) जमीन पर बनाया जा रहा है। यहां एक साथ 4 मेट्रो ट्रेन खड़ी हो सकेंगी। डिपो में अभी जमीनी स्तर पर ही काम चल रहा है।

इस साल शुरू होगा मेट्रो का सफर



कहीं अंडरग्राउंड तो कहीं एलिवेटेड का विरोध

इंदौर में अभी मेट्रो के पहले चरण का काम चल रहा है। रोबोट चौराहे से आगे दूसरे चरण का काम शुरू होगा, जिसमें खजराना, बंगाली चौराहा, कनाड़िया रोड, पलासिया, एमजी रोड, रीगल, कोठारी मार्केट, राजवाड़ा, बड़ा गणपति, रामचंद्र नगर, एयरपोर्ट शामिल है। शहर के मध्य क्षेत्र के व्यापारी मेट्रो के प्रस्तावित रूट का विरोध कर रहे हैं। कोठारी मार्केट में व्यापारी अंडरग्राउंड मेट्रो का विरोध कर रहे हैं। एमजी रोड के व्यापारी इसे एलिवेटेड करने के खिलाफ हैं। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और सांसद सुमित्रा महाजन की ओर से कुछ सुझाव इस संबंध में दिए थे, जिसमें मेट्रो को रेसकोर्स रोड से ले जाते हुए सुभाष मार्ग से ले जाने की बात है। यहां अंडरग्राउंड होने से दिक्कत नहीं होगी। इससे बाजार, व्यापार और राजवाड़ा सब बच जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इंदौर में मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास किया था। तब उन्होंने कहा था कि मेट्रो के कार्यक्रम में शामिल होने जयपुर गया था। उस समय मैं केंद्र में मंत्री था। यहां मेरे मन में विचार आया कि मप्र में मेट्रो को लेकर कोई चर्चा ही नहीं है। इसके बाद लौटकर मैंने उस समय भाजपा सरकार में मंत्री रहे बाबूलाल गौर से भोपाल और एक अन्य शहर के लिए मेट्रो की डीपीआर बनाने को कहा था।

यहां न केवल मेट्रो का रखरखाव होगा, बल्कि कंट्रोलिंग सिस्टम भी यहीं होगा। सिग्नलिंग, कम्युनिकेशन, पावर सप्लाई सबकुछ यहीं से होगा।

एम्स से सुभाषनगर का रूट बनने के बाद सुभाष नगर से करोंद के बीच यानी बाकी के 9.83 किलोमीटर मेट्रो रूट का काम होगा। इस रूट पर 39 एकड़ से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। अलग-अलग लोकेशन की लगभग 8 एकड़ जमीन पर 5 प्लाजा, 6 स्टेशन, 4 पार्किंग, 2 यार्ड बनेंगे। पुराने शहर में अतिरिक्त पार्किंग व्यवस्था पर फोकस है। पुल बोगदा के पास मेट्रो का जंक्शन बनेगा, यहां दोनों लाइनें आकर मिलेंगी। पुल बोगदा से मेट्रो अंडरग्राउंड हो जाएगी। पहला अंडरग्राउंड स्टेशन मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ बनेगा। जहां ईरानी डेरे की जमीन ली गई है। नादरा बस स्टैंड का मेट्रो स्टेशन भी अंडरग्राउंड रहेगा।

भोपाल में लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए 352 सिटी बसें दौड़ रही हैं। इसके अलावा ऑटो, ई-रिक्शा और प्राइवेट व्हीकल अलग हैं। इतने व्हीकल होने से ट्रैफिक का भारी दबाव रहता है। कई जगह तो सुबह-शाम पीक ऑवर्स के समय जाम की स्थिति बन जाती है। अकेले होशंगाबाद रोड पर पीक ऑवर्स के चार घंटों के दौरान 4 हजार से ज्यादा गाड़ियां चलती हैं। मेट्रो ट्रेन चलने से सड़क का ट्रैफिक कम हो जाएगा। इतना ही नहीं बढ़ते पेट्रोल के दाम के बीच मेट्रो पॉकेट फ्रेंडली होगी। वाहन कम होने से कम धुआं होगा, जिससे पर्यावरण की सेहत भी सुधरेगी।

इंदौर मेट्रो ट्रेन प्रायोरिटी कॉरिडोर में गांधी नगर से लेकर रेडिसन-रोबोट चौराहे तक का काम तेजी से चल रहा है। इसकी लंबाई 17.2 किलोमीटर है, जिसमें 5.9 किमी का काम पहले पूरा होगा। 11.6 किमी का काम बाद में होगा। गांधीनगर से सुपर कॉरिडोर के बीच में 5 किलोमीटर रूट पर सितंबर 2023 में मेट्रो ट्रेन चलाकर ट्रायल किया जाएगा। इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने में फिलहाल अधिकारी जुटे हैं। सिविल कंस्ट्रक्शन के जनरल मैनेजर केंसी चौहान ने बताया कि गांधीनगर से रेडिसन स्टेशन तक कुल 17.2 किमी के 16 स्टेशन हमारी प्राथमिकता है। गांधीनगर से सुपर कॉरिडोर तक 5 किलोमीटर में हम सितंबर 2023 तक 6 स्टेशन का काम पूरा कर लेंगे। यह नॉन कॉमर्शियल सर्विस रहेगी।

● प्रवीण सक्सेना

चुनावी साल में मद्र में शराब महंगी नहीं होगी। 2023 की नई आबकारी नीति में सरकार शराब पर एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ा रही है। साथ ही इस बार कोई नई दुकान भी नहीं खोली जाएगी और न ही नए अहाते खुलेंगे। चुनावी साल होने के

कारण इस बार आबकारी नीति में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया जा रहा है। आबकारी विभाग के ड्राफ्ट के मुताबिक लाइसेंस फीस 10 प्रतिशत बढ़ाकर ठेका रिन्यू करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग के साथ नए साल के पहले सप्ताह में होने वाली बैठक में चर्चा होगी। इसके बाद नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। नई शराब नीति 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। पिछले साल देसी शराब सस्ती करने के लिए शराब बनने से लेकर ग्राहक तक पहुंचने का कर्माई का मार्जिन घटाया गया था। पिछले साल आबकारी विभाग ने उप-दुकानें खोलने का प्रस्ताव दिया था, जिसे मुख्यमंत्री ने खारिज कर दिया था। सरकार ने पिछले साल विदेशी शराब पर एक्साइज ड्यूटी 10 से 13 प्रतिशत तक कम कर दी थी। जिससे शराब सस्ती हो गई थी। खपत बढ़ने से सरकार का खजाना भरा और मौजूदा वित्तीय वर्ष में उसे 1300 करोड़ अधिक आय हुई है। खास बात यह है कि वाणिज्यिक कर विभाग फिलहाल शराब पर वैट नहीं बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है।

सरकार ने पिछले साल होम बार लाइसेंस देने का निर्णय लिया था। इसका मतलब है अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय एक करोड़ रुपए है, तो वह व्यक्ति घर पर बार खोल सकता है। इसके अलावा, घर पर शराब रखने की लिमिट 4 गुना कर दी गई थी। इससे पहले घर में एक पेटी बीयर और 6 बॉटल शराब रखने की अनुमति थी। इस बार इस नियम में बदलाव करने का प्रस्ताव भी नहीं है। मद्र में एक अप्रैल 2022 से शराब दुकानों का नया कंपोजिट शॉप मॉडल लागू किया गया। तभी से बीयर की खपत हर महीने नए रिकॉर्ड बना रही है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि साल 2019-20 की तुलना में इस वित्त वर्ष की तिमाही में बीयर की खपत 49 प्रतिशत बढ़ गई है, जबकि देसी शराब की खपत 24 प्रतिशत तो विदेशी की 30 प्रतिशत बढ़ी है। आबकारी विभाग ने 2020-21 और 2021-22 को कोविड-19 प्रभावित वर्ष मानकर अपनी इस साल की ग्रोथ की तुलना 2019-20 से की है। विभागीय अधिकारियों की मानें तो देसी शराब के ग्रामीण ठेकों में बीयर पहली बार बेची जा रही है। ज्यादातर वृद्धि वहीं से आ रही है। अप्रैल 2022 में बीयर की खपत 61 प्रतिशत तक बढ़ी है। साल 2021-22 में कुल बीयर का उत्पादन 13.48 करोड़ बल्क लीटर था। 2019-20 की तुलना में यह 31 प्रतिशत बढ़ा था। इस बार उत्पादन 20 करोड़ बल्क लीटर को भी पार कर

महंगी नहीं होगी शराब



उमा भारती की नाराजगी दूर करने की कोशिश

शिवराज सरकार चुनावी साल में आबकारी नीति में प्रस्तावित प्रावधान को पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की इस मुद्दे पर नाराजगी दूर करने के तौर पर भी देखा जा रहा है। प्रस्तावित नीति में शराब दुकानों को धार्मिक, शैक्षणिक संस्थाओं और हॉस्टल से 50 मीटर की हवाई (एरियल) दूरी पर खोलने की अनुमति दिए जाने का उल्लेख है, जबकि मौजूदा नीति में 50 मीटर की पैदल दूरी पर दुकान खोलने का प्रावधान है। वाणिज्यिक कर विभाग के अफसर कहते हैं कि यदि नया प्रस्ताव मान लिया जाता है तो करीब एक चौथाई यानी 800 दुकानें बंद हो जाएंगी। इन दुकानों को बंद किया जाएगा या फिर शिफ्ट किया जाएगा, इसका फैसला मुख्यमंत्री लेंगे। प्रदेश में वर्तमान में 3605 शराब दुकानें हैं। बता दें कि उमा भारती पिछले एक साल से शराब दुकानों को बंद करने को लेकर सार्वजनिक तौर पर बयान देकर शिवराज सरकार की मुश्किलें बढ़ा चुकी हैं। 2018 में 149 अहाते (ओपन बार) बंद किए गए। कुल अहातों की संख्या 2750 थी। गर्ल्स स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल के अलावा धार्मिक स्थलों से 50 मीटर दूर तक शराब दुकानों को प्रतिबंधित किया गया। झई जोन बनाने का निर्णय हुआ। ये जोन पवित्र नदियों, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल और गर्ल्स हॉस्टल के पास घोषित किए गए। झई जोन में शराब पीना अपराध की श्रेणी में रखा गया। देसी शराब दुकानों की 15 प्रतिशत और विदेशी शराब दुकानों का 10 प्रतिशत तक रिन्यूअल फीस तय की गई थी। 2023 में नए अहाते नहीं खुलेंगे। वर्तमान में प्रदेश में शराब दुकानों की संख्या 3605 शराब दुकानें हैं। जबकि अहाते करीब 3 हजार हैं। गर्ल्स स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल के अलावा धार्मिक स्थलों से 50 मीटर हवाई (एरियल) दूरी पर शराब दुकानों को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव है। झई जोन घोषित पवित्र नदियों, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल और गर्ल्स हॉस्टल के पास शराब पीने पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

सकता है। पहले तीन महीने में ही बीयर का उत्पादन 8 करोड़ लीटर के पार हो चुका है।

मौजूदा वित्तीय वर्ष में नवंबर 2022 तक 12 करोड़ पूफ लीटर देसी शराब बिक गई। आबकारी विभाग का अनुमान है कि 31 मार्च तक यह आंकड़ा बढ़कर 14 करोड़ पूफ लीटर हो जाएगा। ऐसे में अगले साल 16 करोड़ पूफ लीटर शराब की खपत होने की उम्मीद है। इसको ध्यान में रखते हुए देसी शराब की सप्लाई के ठेके के लिए प्रति डिसलर को उत्पादन क्षमता का 80 प्रतिशत या 2 करोड़ पूफ लीटर सप्लाई, दोनों में से जो अधिक हो का ठेका दिया जाएगा।

आबकारी सूत्रों का कहना है कि पिछले साल 12 करोड़ पूफ लीटर देसी शराब की बिक्री का अनुमान था। इसको ध्यान में रखते हुए सप्लाई के लिए 3-3 करोड़ पूफ लीटर सप्लाई का ठेका दिया गया था। यह ठेके 4 डिसलर्स ने लिए थे, लेकिन शराब सस्ती होने के कारण डिमांड बढ़ गई, लेकिन डिसलर इसे समय पर पूरा नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति अप्रैल-मई महीने में बन गई थी। इसे ध्यान में रखकर अब नया नियम प्रस्तावित किया गया है। बता दें कि प्रदेश में देसी शराब उत्पादन करने वाली 22 डिसलरीज हैं।

● जितेंद्र तिवारी

जनवरी की दस्तक के साथ ही कड़ाके की सर्दियां स्वाद के चटोरों के चेहरों पर जितनी चमक ला सकती हैं, उससे कहीं ज्यादा रौनक बाघ के तस्करों के चेहरों पर आएगी। जानकारी के मुताबिक, अवैध आखेट मारे गए बाघों की खालें, हड्डियों और अन्य अंग तस्करी के जरिए थाईलैंड और म्यांमार की सीमा पर जा रहे हैं। गोल्डन सिटी के नाम से कुख्यात मंडी में इनकी हाट ऐसे लगती है, जैसे हमारे यहां सब्जियों की। इस पूरे गोरखधंधे को वन्य जीवन व्यापार (वाइल्ड लाइफ ट्रेड) कहा जाता है। चीन, तिब्बत सरीखे देशों में बाघ के अंगों की मांग ज्यादा होने से भारत में बाघों के शिकार की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इस बाबत हो रहे नित नए खुलासे इस बात की तस्दीक करते हैं कि स्थानीय शिकारी 20-30 हजार से दो लाख तक के मुनाफे के लाभ में बाघों को मौत के घाट उतार रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में बाघों के अंगों को 25 से 30 लाख तक में बेचा जा रहा है।

जानकारों का कहना है कि सरिस्का से बाघों के अंग गुडगांव और दिल्ली से सीमा पार कर अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहुंचते हैं। सूत्रों का कहना है कि बाघों के पैरों के नाखून का इस्तेमाल ज्यादातर तांत्रिक क्रियाओं के लिए किया जाता है। तिब्बत में बाघों की हड्डियों का उपयोग शक्तिवर्धक दवाएं बनाने के लिए किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय संगठन ट्रेफिक की ताजा रिपोर्ट 'स्किन एंड बोन्स' से इसका खुलासा होता है। रिपोर्ट बताती है कि जनवरी 2000 से जून 2022 तक के बीच 50 देशों में 3,377 बाघों के बराबर अंगों की तस्करी की गई। इन वर्षों में तस्करी की 2,205 घटनाएं सामने आईं। भारत में जनवरी, 2018 से जून 2022 के बीच ही 165 घटनाएं हुईं। मतलब साफ है कि भारत से तस्करी ज्यादा हो रही है। हालांकि विशेषज्ञ इस रिपोर्ट को विश्वसनीय नहीं मानते। इसकी वजह चीन थाईलैंड, इंडोनेशिया अफ्रीकी देशों में टाइगर का पालतू होना है। यानी वन्य जीव कानून होने के बावजूद तस्करी अपेक्षाकृत आसान है। इसलिए केस भी कम होंगे।

संभवतः यही वजह रही कि रणथंभोर टाइगर रिजर्व से बाघों को कोटा स्थित मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में शिफ्ट करने की मांग पहले कुतर्कों में उलझकर रह गई। इसकी वजह थी रणथंभोर रिजर्व में महज तीन साल के बाघ की रहस्यमयी मौत को लेकर अजब-गजब पहेलियां बुझाने का अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया था। हालांकि वन विभाग के सूत्र इन चर्चाओं को खारिज करते हैं कि यह घटना बाघ और मानवों के बीच संघर्ष का नहीं आखेट का नतीजा थी। हालांकि जब लोग रणथंभोर के फलोदी की रेंज के डागरवाड़ा गांव के एक बच्चे की मौत बाघ से हमले में होने की बात करते हैं, तो बाघ-मानव



बाघों पर कहर टूटने का मौसम

दो हिस्सों में बांटा धौलपुर से कोटा तक का कॉरिडोर

सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श के बाद अक्टूबर 2017 में राज्य सरकार ने इसे मंजूरी भी दे दी थी। इस आदेश के तहत धौलपुर से कोटा तक के कॉरिडोर को दो हिस्सों में बांटा गया था। पहले हिस्से में धौलपुर से लेकर रणथंभोर तक का इलाका शामिल कर भरतपुर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के केसरबाग को भी रणथंभोर से जोड़ दिया गया था, जबकि सवाई माधोपुर करौली और बूंदी वन क्षेत्र पहले से ही रणथंभोर के क्षेत्राधिकार में था। ग्रीन कोर संस्था का मसौदा कई बातों की तरफ ध्यान बंटता है। मसलन नदियों के तटीय इलाकों और उनसे सटे नालों के आसपास ही ज्यादातर वन क्षेत्र में बाघों का पर्यावास है। दूसरी तरफ कोटा से धौलपुर तक चंबल नदी और वन क्षेत्र बाघों के लिए खासा मुफीद रहा है। रहा सवाल बाघों की चहलकदमी का? उनके पदचिन्ह इस बात की तस्दीक करते हैं कि रणथंभोर के बाघ धौलपुर के झिरी क्षेत्र में भी आते जाते हैं।

संघर्ष के कयासों को बल मिलता नजर आता है। लेकिन सूत्र अवैध आखेट की संभावना से भी इनकार नहीं करते। अलबत्ता इस बात को गलत बताते हैं कि रणथंभोर भी आगे चलकर अवैध आखेट सरिस्का बन जाएगा?

शुरुआत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने रणथंभोर के बाघों को कोटा रिजर्व में शिफ्ट करने की अनुमति जारी कर दी थी। लेकिन वन महकमा इनको जोड़ें या फिर इकलौते बाघों को भेजने पर आनाकानी में अड़ा रहा, जबकि वन्य जीव प्रेमी भी इस बात से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि बाघों या जोड़ों की बजाय बाघिनों

को भेजा जाए। उनका तर्क था कि कोटा स्थित मुकुंदरा हिल्स में दो बाघ और एक बाघिन मौजूद हैं। यदि बाघिन भेजी जाती है, तो नया अभयारण्य जल्द से जल्द आबाद हो सकेगा।

वन्य जीव प्रेमियों ने केंद्र सरकार से भी इस बात का आग्रह किया। लेकिन आसपास के इलाकों में मानवीय गतिविधियों और अवैध आखेट के चलते वन्यजीव प्रेमी बाघों की सुरक्षा को लेकर मुतमईन नहीं थे। उनका कहना था कि इस मामले में वन महकमा आज भी डांवाडोल है। अभी भी वन विभाग मुकुंदरा में बसे हजारों लोगों का विस्थापन कर उन्हें गांवों से सुरक्षित नहीं निकाल पाया है। ऐसे में मुकुंदरा हिल्स में बाघों का कुनबा बढ़ने के साथ बाघ और मानवों के बीच टकराव को बढ़ाएगा। यह स्थिति तो बाघ संरक्षण की कोशिशों को भी मटियामेट कर देगी। पीपुल्स फॉर एनीमल्स संगठन के प्रदेश प्रभारी ने इन अंदेशों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री को भी पत्र लिखा था। उनका कहना है कि मुकुंदरा को टाइगर रिजर्व घोषित किए हुए 20 साल हो गए। लेकिन गांवों के विस्थापन समस्या तो जस की तस अटकी रही है। दूसरी तरफ वन्यजीव प्रेमी इस बात को लेकर भी हैरान हैं कि इंसानी जिंदगियों के साथ-साथ बेशकीमती बाघों को बचाने के लिए कोई दो साल पहले वन विभाग ने धौलपुर से कोटा तक के रियासतकालीन रॉयल राजस्थान टाइगर कॉरिडोर को फिर से जिंदा करने की कोशिश की थी। लेकिन ताजुब है, ये कोशिशें आज तक भी सिरे नहीं चढ़ीं? पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था ग्रीन कोर के सूत्रों का कहना है कि 10 अगस्त 2017 को संस्था ने करौली और धौलपुर से कोटा और झिरी तक टाइगर कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा था।

● विकास दुबे

दिल्ली के जंतर मंतर पर 2011 में अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चल रहा था। आंदोलन इतना प्रभावी हो गया था कि लोकपाल की मांग पर केंद्र की कांग्रेस सरकार बार-बार केजरीवाल को बातचीत का न्यौता दे रही थी। बात किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। ऐसे में एक दिन झल्लाकर कांग्रेस के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल को ऑफर दे दिया कि राजनीति में भ्रष्टाचार की इतनी ही चिंता है तो इन लोगों को आंदोलन छोड़ राजनीति में उतर आना चाहिए। उस समय तक आंदोलन में शामिल लोगों का राजनीतिक पार्टी बनाने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन आंदोलन का संयोजन कर रहे अरविंद केजरीवाल ने संभवतः इस सलाह को गंभीरता से ले लिया और आम आदमी पार्टी के जन्म के साथ ही भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन खत्म हो गया।

आज आम आदमी पार्टी दिल्ली की स्थानीय पार्टी की छवि से बाहर निकलकर 10 साल के भीतर ही एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। राजनीति के अपने 10 सालों के इस सफर में आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा किसी को नुकसान पहुंचाया है तो वह कांग्रेस ही है। दिल्ली में जो जगह कांग्रेस की थी अब उस जगह आम आदमी पार्टी अपनी जड़ें जमा चुकी है। दिल्ली के बाहर अभी तक पंजाब और गुजरात में आम आदमी पार्टी ने अपनी जगह बनाना शुरू किया है, और दोनों ही जगहों पर उसका उदय कांग्रेस की कब्र पर हुआ है। दिल्ली नगर निगम चुनाव परिणाम आए, जिसमें केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने 250 सीटों में से 134 सीटें जीत लीं। 15 सालों से दिल्ली के तीन नगर निगमों पर काबिज भाजपा को इस चुनाव में 104 वार्डों पर ही जीत मिली है। लेकिन आप वोट शेयर देखेंगे तो पाएंगे कि बीते 2017 के चुनाव के मुकाबले आम आदमी पार्टी का वोट शेयर ही नहीं बढ़ा बल्कि भाजपा का वोट शेयर भी बढ़ा है।

2017 के नगरपालिका चुनाव में भाजपा को 36.08 प्रतिशत वोट मिले थे जबकि इस बार उसे 39.09 प्रतिशत वोट मिले हैं। यानी सीटें कम होने के बावजूद भाजपा के वोट शेयर में 3 प्रतिशत की बढ़त हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी के वोट शेयर में बीते नगरपालिका चुनाव के मुकाबले लगभग 15.82 प्रतिशत का उछाल आया है। आम आदमी पार्टी को 2017 में 26.23 प्रतिशत वोट मिले थे जबकि इस बार दिल्ली नगर निगम चुनाव में 42.05 प्रतिशत वोट मिले हैं। अगर इस बार कांग्रेस के वोटों की बात करें तो 2017 में 21.09 प्रतिशत वोट के मुकाबले इस बार उसे 11.68 प्रतिशत वोट मिले हैं और 9.41 प्रतिशत वोटों की भारी गिरावट आई है। इसके साथ ही निर्दलियों एवं अन्य उम्मीदवारों के वोट शेयर में भी भारी गिरावट आई है। इस बार कांग्रेस एवं अन्य उम्मीदवारों के वोट कम होकर भाजपा और आम आदमी पार्टी में बंट गए हैं। ये नतीजे बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे दिल्ली



आम आदमी पार्टी का उदय

आम आदमी पार्टी का विकास कांग्रेस की कीमत पर

हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणाम देखें तो साफ दिखता है कि वहां कांग्रेस चुनाव मुकाबले में है इसलिए आम आदमी पार्टी अपने पैर नहीं जमा पाई है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा में सीधी टक्कर है, क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी अपना पैर नहीं जमा पाई है। साफ है, आम आदमी पार्टी का विकास कांग्रेस की कीमत पर ही हो रहा है। जहां-जहां कांग्रेस खत्म हो रही है वहां-वहां आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक ताकत के रूप में उभर रही है। हो भी क्यों नहीं, आम आदमी पार्टी का गठन और शुरुआत भाजपा के विरोध में तो हुआ नहीं था। उसकी शुरुआत ही कांग्रेस के विरोध में हुई थी। ऐसे में वह कांग्रेस का विकल्प बन रही है तो इसमें आश्चर्यजनक क्या है? अपने अंतर्विरोधों और गलत राजनीतिक नैरेटिव के कारण देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस एक कब्र में परिवर्तित होती जा रही है। उस कब्र पर जिस नई नवेली पार्टी का उदय और विकास हो रहा है, हो सकता है वही भविष्य में कांग्रेस की जगह ले ले। फिलहाल तो 10 सालों में आम आदमी पार्टी के विस्तार से तो यही संकेत मिल रहे हैं।

विधानसभा के समय थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 53.57 प्रतिशत वोट मिले थे। भाजपा को बीते विधानसभा चुनाव में 38.51 प्रतिशत वोट मिले थे। स्वाभाविक है, दोनों पार्टियों में वोटों का यह बड़ा अंतर सीटों का अंतर भी बन गया। भाजपा को सिर्फ 8 सीटें मिली जबकि आम आदमी पार्टी को 62 सीटों पर जीत मिली। 2020 में जहां आम आदमी पार्टी के वोट शेयर में मामूली गिरावट आई थी वहीं भाजपा का वोट शेयर 6.21 प्रतिशत बढ़ा था। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल वोट का मात्र 4.26 प्रतिशत मत मिला था। 2013 से दिल्ली में

कांग्रेस लगातार पतन के गर्त में जा रही है जिसका सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। भाजपा का मतदाता न केवल उसके साथ बना हुआ है बल्कि हर बार थोड़ा बहुत बढ़ भी रहा है। कांग्रेस तेजी से धराशायी हुई है। वहीं अपना वोट शेयर बढ़ाकर भी भाजपा दिल्ली में केजरीवाल का मुकाबला नहीं कर पा रही है। दिल्ली में कांग्रेस का पतन ही आम आदमी पार्टी की सफलता का सबसे बड़ा कारण है।

लगभग यही स्थिति पंजाब में भी है जहां कांग्रेस को बुरी तरह हराकर अब आम आदमी पार्टी सत्ता में है। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 42.01 प्रतिशत वोट मिला था, जो 2017 के 23.7 प्रतिशत के मुकाबले में लगभग दोगुना था। इसका जबरदस्त लाभ आम आदमी पार्टी को मिला और उसे पंजाब में 117 सीटों में 92 सीटों पर जीत हासिल हुई। 2017 में 77 सीटें जीतने वाली कांग्रेस को 38.5 प्रतिशत के मुकाबले में 22.97 प्रतिशत वोट ही मिले। इसका असर ये हुआ कि कांग्रेस पंजाब में धड़ाम से गिर गई और 18 सीटों पर सिमट गई। हां, शिरोमणि अकाली दल की सहयोगी भाजपा की इस राज्य में पहले भी कोई खास हैसियत नहीं थी। इस बार उसने अपने दम पर चुनाव लड़ा फिर भी उसके वोटों में 2017 के मुकाबले एक प्रतिशत की बढ़त हुई है। अब ऐसा ही कुछ गुजरात में भी दिखाई दे रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को कुल 49.04 प्रतिशत वोट मिले थे तो कांग्रेस को 41.44 प्रतिशत वोट। राज्य में कांग्रेस ने भाजपा को कड़ी टक्कर देते हुए 77 सीटें जीत ली थी। लेकिन इस बार 2022 में भाजपा ने जहां अपने वोटों में तीन प्रतिशत से अधिक की बढ़त की है, वहीं कांग्रेस के वोटों में 22 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आ रही है। आखिरी चुनाव परिणाम आते-आते हो सकता है कांग्रेस के वोट शेयर में थोड़ा सुधार हो भी जाए लेकिन वह अपने पिछली बार के वोट प्रतिशत को बरकरार नहीं रख पाएगी।

● राजेश बोरकर



देश का हॉट स्पॉट बना मध्य प्रदेश

प्रवासी, ग्लोबल समिट और खेलो इंडिया ने बढ़ाई मप्र की साख

चुनावी साल में भाजपा के लिए संजीवनी बनेंगे ये बड़े आयोजन

संघ की प्रयोगशाला के बहुतेरे प्रयोगों के हिसाब से मप्र भाजपा के लिए सबसे ज्यादा मुफीद रहा है। इस कारण किसी न किसी बहाने यहां संघ, विहिप से लेकर प्रमुख अनुषांगिक संगठनों के बड़े आयोजन सरकारी और गैरसरकारी माध्यमों से होते रहते हैं। इनका अपरोक्ष फायदा सरकार को मिलता है। वहीं चुनावी साल में मप्र में प्रवासी भारतीय सम्मेलन, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जी-20 देशों के सम्मेलन का आयोजन मप्र में किया जा रहा है। दरअसल ये सभी आयोजन भाजपा की रणनीतिक सोच के परिणाम हैं।

● राजेंद्र आगाल

मा जपा देश के हृदय प्रदेश को विकास के मॉडल के रूप में देश के सामने प्रस्तुत करती आ रही है। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि मप्र में जो प्रयोग सफल होता है उसका देशव्यापी प्रभाव पड़ता है। यही वजह है कि चुनावी साल में मप्र देश का हॉट

स्पॉट बना हुआ है। अभी हाल ही में यहां प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सफल आयोजन हो चुका है। आगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स और जी-20 देशों के सम्मेलन आयोजित किए जाने वाले हैं। इन आयोजनों से मप्र की अर्थव्यवस्था को तो पंख लगेंगे ही, साथ ही प्रदेश की साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगी। साथ

ही इन आयोजनों के माध्यम से भाजपा चुनावी समीकरण साधेगी। इसलिए मिशन 2023 और 2024 पर नजर रखते हुए ये बड़े आयोजन मप्र में आयोजित किए जा रहे हैं। यह स्पष्ट है कि भाजपा यह अच्छे से जानती है कि इस तरह के जलसों से प्रवासियों की ब्रांडिंग, प्रमोशन और राष्ट्र सेवा के साथ राजनीतिक हित भी साधे जा सकते हैं।

गौरतलब है कि 2020 में जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, पार्टी तभी से चुनावी तैयारी में जुटी है। अब इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी 200 सीटों का टारगेट पाने के प्रयास में जुट गई है। पार्टी के इस अभियान में प्रदेश में होने वाले बड़े आयोजन निश्चित रूप से भाजपा के लिए संजीवनी बनेंगे। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बाद अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट चल रही है। आने वाले दिनों में मद्र में कई बड़े आयोजन होने हैं। इनमें 30 जनवरी से 11 फरवरी के बीच प्रदेश के आठ शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होगा, जबकि 13 से 15 फरवरी के बीच इंदौर जी-20 देशों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसमें जी-20 देशों के कृषि मंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा 21 से 24 फरवरी के बीच प्रदेश की राजधानी भोपाल में आठवां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित होगा। इन तमाम आयोजन के पीछे भाजपा अपना राजनीतिक फायदा देख रही है।

15 लाख करोड़ का निवेश

मद्र की आर्थिक राजधानी इंदौर में दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया। इस समिट में मद्र में 15 लाख 42 हजार 514 करोड़ रुपए का निवेश आया है। जिससे 29 लाख नए रोजगार मिलेंगे। एमपीआईडीसी ने सफलतापूर्वक 23 व्यापार संगठनों के साथ 36 एमओयू करार पर हस्ताक्षर किए हैं। यह संगठन 215 से अधिक देशों में 15 निवेश और सहयोग के क्षेत्रों में कार्यरत हैं। ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में समापन समारोह को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि थका तो नहीं हूँ अभी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों का लगातार सपोर्ट मिला है। अब विदाई की बेला चुकी है। जिन्होंने इंटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट दिए हैं, उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। मद्र में एक बार उंगली पकड़ ली तो वो आसानी से छूटती नहीं है। जिस तरह सब लोग मिले, ऐसा लग रहा था कि मेरा एक पूरा परिवार है। मैंने पूरी कोशिश की कोई निराशा न जा पाए। ये अद्भूत प्यार भारत का संस्कार है।

मुख्यमंत्री शिवराज ने आगे कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 84 देशों के प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ 447 इंटरनेशनल बिजनेस डेलीगेट्स, 401 इंटरनेशनल बॉयर्स शामिल हुए। 5 हजार से ज्यादा डेलीगेट्स आए। जी-20 के सभी देश आए। इंदौर अद्भूत है, इंदौर से मद्र में निवेश का नया दौर प्रारंभ हो रहा है। अभी तो हम आंकड़े गिन रहे हैं। जाते-जाते भी लोग कह रहे हैं कि मद्र में निवेश करेंगे। निवेश की आइडियल डेस्टिनेशन है मद्र। हमने



आयोजनों को उपलब्धि के रूप में पेश करेगी भाजपा

मद्र में होने वाले उपरोक्त बड़े आयोजनों को भाजपा पहले विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव में इसे अपनी उपलब्धि के रूप में पेश करेगी। गौरतलब है कि मद्र सरकार द्वारा प्रदेश को कंपलीट बिजनेस सॉल्यूशन के साथ पयूचर रेडी स्टेट बनाने से प्रदेश में निवेश के लिए देश-विदेश के निवेशकों का रुझान बढ़ रहा है। यहां बिजनेस स्टार्ट करने के लिए शासकीय अनुमतियों से लेकर इंडस्ट्री प्रारंभ करने के बाद उसके सफल संचालन के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य मद्र भारत का हृदय है और आज ये सबसे तेज गति से विकास पथ पर अग्रसर है। राज्य प्राकृतिक संसाधनों और खनिजों से संपन्न है। राज्य में 95 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र, 7 स्मार्ट सिटी और बेहतरीन यातायात व्यवस्था है। राज्य में खेती एवं प्रोसेसिंग क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है, जिससे औद्योगिक निवेश के लिए माहौल बन रहा है। इसके साथ ही फार्मास्यूटिकल ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, लॉजिस्टिक, आईटी, अक्षय ऊर्जा, पर्यटन, शहरी विकास ऐसे क्षेत्र हैं, जहां निवेश की अपार संभावनाएं हैं। राज्य में कुशल मानव संसाधन और उचित मूल्य पर भूमि की उपलब्धता, राज्य में औद्योगिक वातावरण को तैयार करती है। सरकार की नीति और प्रशासन का सहयोग इस दिशा में मददगार साबित हो रहा है। मद्र में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए वह सभी कुछ है, जो निवेश के लिए आवश्यक है। ऐसे में मद्र में जो बड़े निवेश हो रहे हैं उससे प्रदेश सरकार की साख बढ़ रही है।

18 साल में शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। बीमारू से हम अग्रणी राज्यों में शुमार हुए हैं। संसाधन से संपन्न हैं। शांति के टापू हैं। अध्यात्म में अव्वल हैं। पर्यटन में बेजोड़ हैं। हमने अपनी कोर क्षमताओं को ही अपनी शक्ति बनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 10 पार्टनर को धन्यवाद देता हूँ। कई मीटिंग में व्यापारी अधिकारियों ने भाग लिया।

जमीन के लिए कोई परमिशन नहीं लगेगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगपतियों को अगर जमीन मिल गई, तो कोई परमिशन नहीं लगेगी। जो भी नियम प्रक्रिया है, उसे खुद ही पालन करो आप पर पूरा भरोसा है। उद्योगपतियों के सेटअप खड़ा करने के बाद उसका तीन साल तक कोई निरीक्षण नहीं करेगा। आप लोग आगे बढ़ते रहो पूरा भरोसा है। इंदौर में 10,000 की क्षमता का एक और नया कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। मद्र में 15 लाख 42 हजार 514 करोड़ रुपए निवेश आया। मद्र भविष्य में भारत के टॉप-3 एक्सपोर्ट स्टेट में शामिल होगा। मद्र से पिछले साल की अपेक्षाकृत ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है। प्रदेश के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, सोया, गेहूं सहित कृषि, मसाला, कॉटन यार्न एवं अन्य क्षेत्रों निर्यात के बेहतर अवसर होंगे। यह बात अतिरिक्त सचिव डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड संतोष सारंगी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दूसरे दिन ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में फॉस्ट्रिंग एक्सपोज़िशन फ्रॉम एमपी सेशन में निवेशकों से कही। अतिरिक्त सचिव सारंगी ने कहा कि मद्र के एक्सपोर्ट में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए राँ मटेरियल के स्थान पर फाइनल प्रोडक्ट पर फोकस करेंगे। कॉटन यार्न के स्थान पर फैब्रिक और अपेरल, सोयाबीन के स्थान पर सोयाबीन उत्पाद, मसाले, होम फर्निशिंग प्रोडक्ट, जेम्स और ज्वेलरी प्रदेश



मंच से लंच तक शिवराज का ही रहा दबदबा...

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रशासनिक क्षमता के साथ-साथ राजनीतिक कलाबाजी में भी पारंगत हो गए हैं। जब भी लगता है कि उनकी स्थिति थोड़ी कमजोर हुई, तो वे कोई ना कोई अचूक दांव चलकर मजमा लूट लेते हैं। इस बार प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के साथ-साथ ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जैसे दो बड़े आयोजन हुए और उसमें मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से अपना दबदबा कायम रखा। मंच से लंच तक कोई भी उनके इर्द-गिर्द नहीं भटक पाया। काबिना मंत्रियों से लेकर तमाम विरोधी ठिकाने लग गए और मौका पाने के प्रयास में तरसते रह गए। इस दौरान भरपूर राजनीतिक माइलेज भी मामाजी ने पा लिया और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वरदहस्त भी उन्हें अब हासिल हो गया लगता है, क्योंकि जिस तरह सम्मेलन में उन्होंने प्रशंसा की, वहीं समिट के वर्चुअल उद्घाटन को भी तैयार हो गए। सबसे लंबे समय तक प्रदेश के मुख्यमंत्री की कंसी पर काबिज शिवराज सिंह ने पूर्व के सारे घाघ राजनीतिज्ञों को भी पीछे छोड़ दिया है। वरना एक जमाने में स्व. अर्जुन सिंह को प्रदेश की राजनीति में सबसे चतुर खिलाड़ी माना जाता था और उसके बाद दिग्गी राजा का नाम लिया जाने लगा, लेकिन मामाजी ने सभी खुर्राट राजनीतिज्ञों को पीछे छोड़ दिया और जिसने भी थोड़ा विरोध किया, वो कब कहां ठिकाने लग गया, उसे भी पता नहीं चल सका। अभी जो आयोजन इंदौर में हुए, उसमें भी शिवराज सिंह ने साबित कर दिया कि उनकी रणनीति के आगे किसी की कोई चाल नहीं चल सकती। गुजरात चुनाव में अपनाए गए मॉडल और उसके बाद लगातार राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम रही कि अब मप्र में भी नेतृत्व परिवर्तन जल्द होने जा रहा है, लेकिन जब-जब ऐसी स्थिति पूर्व में भी बनी, तब मामाजी ने अपने तरकस से कोई ना कोई अभेद तीर छोड़कर इस तरह की सारी अटकलों को धराशायी कर दिया।

के एक्सपोर्ट में अहम भूमिका अदा करेंगे। प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा मनु श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2021-22 में एक्सपोर्ट 58 हजार 407 करोड़ का रहा है। काबुली चना, सोयाबीन, फार्मा, टेक्सटाइल और कृषि उत्पादों में प्रदेश अग्रणी रहा है। मप्र से 200 से भी अधिक देशों में निर्यात होता है। जिसमें अमेरिका, बांग्लादेश और चीन में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। प्रदेश में नए उद्योग लगाने और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उत्पाद निर्मित करने की अपार संभावनाएं हैं।

फॉस्टरिंग एक्सपोर्ट्स फ्रॉम एमपी सेशन में फ्लेक्सीटफ ग्रुप के सौरभ कलानी ने कहा कि मप्र के व्यापार को और अधिक संवर्धित करने के लिए 3-पी-परफार्मेंस पॉलिसी और परसेप्शन पर काम करना होगा। सरकार के द्वारा सिंगल

विंडो सिस्टम से क्लीयरेंस हो रहा है। कलानी ने कहा कि एक्सपोर्ट्स को ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलती है तो निर्यात और अधिक बढ़ने की संभावनाएं बढ़ेंगी। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन कार्डिसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन अरुण कुमार गरोडिया ने कहा कि मप्र का व्यापार संवर्धन में अत्यधिक सहयोगात्मक रूख है। प्रदेश पॉवर सरप्लस स्टेट है। रॉ मटेरियल की बहुतायत है। केंद्र सरकार की मदद से एमएसएमई सेक्टर में बहुत अधिक प्रोग्रेस की जा सकती है।

टेक्सटाइल की अपार संभावनाएं

डीएमएल ग्रुप के प्रमोटर हरीश लखनी ने कहा कि मप्र को अपने उत्पादों की ब्रांडिंग करनी चाहिए। मप्र में बेहतर कार्य हो रहा है। यहां टेक्सटाइल की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।

क्या बोले दिग्गज निवेशक

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेश के मंच पर पहले दिन देश के दिग्गज उद्योगपति पहुंचे। उद्योगपति इस बात से काफी संतुष्ट दिखाई दिए कि प्रदेश के विकास की रफतार सरपट है। 20 साल में तेजी से तस्वीर बदल चुकी है। उनके निवेश के लिए यहां अपार संभावनाएं हैं। टीसीएस के चेयरमैन एन. चन्द्रशेखरन ने कहा कि मप्र में अपार संभावनाएं हैं। इसकी 62 प्रतिशत आबादी कामकाजी है। राज्य में समृद्ध प्राकृतिक संसाधन हैं। पर्यटन में जबरदस्त अवसर हैं। आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला का कहना है कि देश के बीच में स्थित होने से मप्र में बहुत लाभ हैं। यहां 3 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क है। 5000 किलोमीटर की रेलवे लाइन है। यह प्रदेश मुंबई और दिल्ली कॉरिडोर की तरह नए औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट के एमडी पार्थ जिंदल ने कहा कि जेएसडब्ल्यू मप्र में निवेश के लिए नया है। हमने बिरला, टाटा समेत अन्य समूहों के उदाहरणों से सीखा है। देखा है कि प्रदेश कितना निवेश फ्रेंडली स्थान है। हम पीछे नहीं रहना चाहते और तेजी से निवेश करना चाहते हैं। हमने पन्ना जिले में लाइमस्टोन खदानें ली हैं। जल्द ही अत्याधुनिक एकीकृत सीमेंट प्लांट करीब 3 हजार करोड़ के निवेश के साथ शुरू करने वाले हैं। दूसरा निवेश हम ब्रांड न्यू जेएसडब्ल्यू पेंट्स में 1500 करोड़ के निवेश के साथ पीथमपुर में करेंगे। अवाडा समूह के चेयरमैन विनीत मित्तल का कहना है कि पहले जब बड़े उद्योग मप्र में निवेश के लिए आते थे, तब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कई सवाल उठते थे। अब ऐसा नहीं। मेरे साथी प्रशांत चौबे ने बताया कि सागर में जब पढ़ाई करते थे, तब भोपाल आने में पूरा दिन लगता था, अब सिर्फ तीन घंटे लगते हैं। हमने 2013 में 151 मेगावॉट के एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट को साकार किया। अब आगरा में 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। प्रदेशभर में 1000 मेगावॉट के पावर प्रोजेक्ट्स स्थापित कर रहे हैं। इंदौर के पास सिलिकॉन टू मॉड्यूल मैनुफैक्चरिंग में निवेश कर रहे हैं, जो कि अवाडा ग्रुप के बड़े निवेशों में से एक है। रिलायंस के एग्जी. डायरेक्टर निखिल आर. मेसवानी ने कहा कि लगभग 150 बिलियन डॉलर के साथ मप्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग पांच प्रतिशत का योगदान दे रहा है। मप्र को कभी बीमारू राज्य के रूप में गिना जाता था। राज्य ने अपने औद्योगिक गलियारे का विस्तार किया है और खुद को निवेश का डेस्टिनेशन बनाया।

फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ ही पार्टनरशिप के द्वारा कंपनियों स्थापित कर प्रमोट करने की आवश्यकता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल और सीईओ अजय सहाय ने कहा कि मप्र ऑटोमोबाइल, फार्मास्युटिकल और वेल्यू एडिशन के क्षेत्र में बहुत बढ़िया कार्य कर रहा है। प्रदेश में 250 से अधिक फार्मास्युटिकल कंपनियां काम कर रही हैं। यहां पर मेडिसन और आर्गेनिक प्रोडक्ट्स के चेन्नै में व्यापक अवसर मौजूद हैं। सत्र में विशेषज्ञों ने निवेशकों के प्रश्नों के उत्तर दिए। प्रदर्शन सुविधा शाह ने आभार व्यक्त किया।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से मप्र में करोड़ों का निवेश हुआ है। पहले तीन दिनी प्रवासी भारतीय सम्मेलन और फिर दो दिवसीय इन्वेस्टर्स समिट के जरिए मप्र ने नई उड़ान भरी। इसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आधिकारिक समापन हो गया पर इसमें हुए निवेश से प्रदेश में नई औद्योगिक क्रांति की उम्मीद जाग उठी है। समिट में सरकार को देश-दुनिया के प्रमुख निवेशकों से 15 लाख 42 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। समिट के समापन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान किया। उन्होंने बताया कि इससे करीब 29 लाख नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। सरकार ने निवेशकों को लुभाने के लिए 7 सूत्रीय रणनीति बनाई है। इसमें नंबर संवाद, दूसरा, सहयोग। तीसरा सुविधा, इसमें सरल नीति रखेंगे। चौथा मंजूरीयां, बिना चक्कर लगाए काम। पांचवां सेतु, ये पोर्टल लाएंगे। छठा सिंगल विंडो, इसमें रियल सिंगल विंडो होगी। सातवां समन्वय, इसमें मिलकर काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हमारी रणनीति है। यूएसए के काउंसिल जनरल माइक हंकी ने भारत के लिए वीजा क्षमता बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, भारत के सबसे ज्यादा छात्र यूएसए आते हैं। उन्हें वीजा की परेशानी आती है। इसलिए हम क्षमता बढ़ा रहे हैं, ताकि छात्रों के साथ व्यापार और टूरिस्ट वीजा जल्द मिल सके। शिक्षा के क्षेत्र में भारत और मप्र में कई संभावनाएं हैं। यूएसए की कई यूनिवर्सिटी यहां आना चाहती हैं। वे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चर्चा के सत्र को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस समिट से हम टेक ऑफ कर रहे हैं, अनंत आकाश में ऊंची उड़ान भरने के लिए। मप्र की धरती पर हम किसी को निराश नहीं होने देंगे। निवेश की हर बाधा दूर की जाएगी। अब उद्योगों को एक बार जमीन आवंटन हो जाने के बाद किसी तरह की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। तीन साल तक किसी तरह की चेकिंग या जांच-पड़ताल नहीं होगी। निवेशकों को बस नियम-कानून का पालन करना होगा।



आयोजन से बहेगी विकास की गंगा

प्रवासी भारतीय सम्मेलन, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन इंदौर में हुए तो वहां सरकार ने कई विकास कार्य करवाए हैं। वहीं खेले इंडिया यूथ गेम्स, जी-20 देशों के सम्मेलन प्रदेश के कई शहरों में होंगे, तो वहां भी विकास की गंगा बहेगी। इससे भाजपा बड़े वोट को साधने की कोशिश करेगी। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के अलावा 30 से 11 फरवरी के बीच मप्र में खेले इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन होगा। प्रदेश के आठ शहर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और खरगोन (महेश्वर) में यूथ गेम्स के आयोजन होंगे। जबकि एक गेम (साइकिलिंग) दिल्ली में होगा। पहली बार वाटर स्पोर्ट्स अर्थात् कयाकिंग कैनोइंग, कैनो सलालम और तलवारबाजी, खेले इंडिया गेम्स के इस संस्करण का हिस्सा होंगे। 13 दिन तक 27 खेल 9 शहरों के 23 गेम वेन्यू में होंगे। लगभग 6 हजार खिलाड़ी, 303 अंतर्राष्ट्रीय और 1089 राष्ट्रीय ऑफिशियल्स इन गेम्स का हिस्सा होंगे। वहीं, फरवरी में इंदौर जी-20 देशों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 13 से 15 फरवरी तक होने वाला यह तीन दिवसीय सम्मेलन एग्रीकल्चर पर फोकस रहेगा। इसमें जी-20 देशों के कृषि मंत्री शामिल होंगे। खास यह कि यह साल अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष है इसलिए भी समिट में इस पर भी मंथन होगा। वहीं भारत के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी प्रगति की उपलब्धियों का उत्सव राजा भोज की नगरी भोपाल में होगा।

मप्र अजब है, गजब है और सजग भी

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मप्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मप्र आस्था और आध्यात्म से लेकर पर्यटन, स्किंग डेवलपमेंट और एजुकेशन में अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। ये समिट तब हो रही है जब भारत की आजादी का अमृत काल शुरू हो चुका है। हम सभी मिलकर विकसित भारत के निर्माण के लिए जुटे हुए हैं। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो ये हमारा सिर्फ एम्प्रीशन नहीं बल्कि हर भारतीय का संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत विश्व के कई देशों से बहुत अच्छी स्थिति में है। भारत इस साल जी-20 ग्रुप में भी बढ़ती हुई इकॉनोमी वाला देश है। एक ताजा सर्वे में बताया गया कि विश्व के ज्यादातर इन्वेस्टर्स भारत को पसंद कर रहे हैं। भारत इज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ बिजनेस पर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक निर्णायक सरकार, सही नीयत से चलने वाली सरकार विकास को गति देकर दिखाती है। विकास के लिए सभी फैसले उतनी ही तेजी से लिए जाते हैं। आपने भी देखा है हमने बीते 8 वर्षों में रिफॉर्म की स्पीड को बढ़ाया है। बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्मिंग और गवर्नर से जुड़े रिफॉर्म हों, जीएसटी के रूप में वन नेशन वन टैग जैसा सिस्टम बनाना हो, छोटी-छोटी गलतियों को ठीक करना हो... ऐसे कई रोड़े हमने इन्वेस्टमेंट के नजरिए से हटाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का नया भारत अपने प्राइवेट सेक्टर की ताकत पर भी भरोसा

करते हुए आगे बढ़ रहा है। हमने डिफेंस, माइनिंग और स्पेस जैसे अनेक स्ट्रैटेजिक सेक्टर को भी प्रावेट सेक्टर के लिए खोल दिया है। दर्जनों लेबर लॉज को फोर कोड्स में समाहित करना भी अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। कम्पलाइजेशन के बोझ को कम करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों के स्तर पर अभूतपूर्व प्रयास चल रहे हैं। बीते कुछ समय में करीब 40 हजार कम्पलाइजेशन को हटाया जा चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया। जिससे मप्र जुड़ चुका है। इससे अभी तक लगभग 50 हजार स्वीकृतियां दी जा चुकी हैं। भारत का आधुनिक होता इंफ्रा हो रहा है। भारत में एक नेशनल प्लेटफार्म पर देश की सरकार, एजेंसियां और इन्वेस्टर्स से जुड़ा अपडेटेड डाटा रहता है। भारत दुनिया के सबसे कॉम्पिटिटिव लॉजिस्टिक प्लेटफार्म के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए कमिटेड है। इसी लक्ष्य के साथ हमने नेशनल इन्वेस्टर्स पॉलिसी लागू की है।

भारत स्मार्टफोन डेटा कंजप्शन में नंबर वन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत स्मार्टफोन डेटा कंजप्शन में नंबर वन है। ग्लोबल इंटेक में नंबर वन है। भारत आईटीवीपीएन आउटसोर्सिंग में नंबर वन है। भारत तीसरा बड़ा एबुपेशन मार्केट और ऑटो मार्केट है। भारत के डिजिटल इंफ्रा को लेकर आज हर कोई विश्वास से भरा हुआ है। भारत एक तरफ गांव-गांव तक ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क पहुंचा रहा है। वहां तेजी से 4जी नेटवर्क का विस्तार कर रहा है। 5जी से हर इंडस्ट्री और कंज्यूमर के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स से लेकर एआई तक जो भी नए अवसर बन रहे हैं वो भारत में विकास की गति को और तेज करेंगे। इन प्रयासों से ही आज मेक इन इंडिया को ताकत मिल रही है।



दुनिया भर के इन्वेस्टर्स में पॉपुलर हो रही प्रोडक्शन लिंकड इंसेटिव स्कीम

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेन्यूफैक्चरिंग की दुनिया में भारत तेजी से अपना विस्तार कर रहा है। प्रोडक्शन लिंकड इंसेटिव स्कीम के तहत ढाई लाख करोड़ से अधिक के इंसेटिव की घोषणा की जा चुकी है। ये दुनिया में पॉपुलर हो रही है। ये स्कीम दुनियाभर के इन्वेस्टर्स में पॉपुलर हो रही है। इससे अब तक करीब 4 लाख करोड़ प्रोडक्शन हो चुका है। मप्र में भी सैकड़ों करोड़ का निवेश आया है। मप्र को बड़ा टेक्सटाइल हब बनाने में इसका बड़ा योगदान है। इस स्कीम का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आप सभी को ग्रीन एनर्जी को लेकर भारत की आकांक्षा से जुड़ना चाहिए। हेल्थ, एग्रीकल्चर, न्यूट्रीशियन हर लिहाज से भारत में नई संभावनाएं आपका इंतजार कर रही है। ये भारत के साथ-साथ एक नई ग्लोबल सप्लाय चैन के निर्माण का अवसर है। मप्र का सामर्थ्य और संकल्प आपकी प्रगति में दो कदम आगे

चलेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक जमाना था जब मप्र को बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन अब मप्र ने अपनी नई पहचान बनाई है। एक बार मैंने अमेरिका में कहा था कि मप्र की सड़कें अमेरिका से ज्यादा बेहतर हैं। उस पर लोगों ने बहुत ज्यादा हल्ला भी मचाया था। कल प्रवासी भारतीयों ने खुद कहा कि इंदौर की सड़कें लंदन वालों से भी ज्यादा अच्छी हैं। हम दिन और रात काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन्वेस्टर्स से बड़ा वादा करते हुए कहा कि यहां जो इन्वेस्टर आए हैं, वो मैप पर हाथ रखकर बता दें कि उनको कौन सी जमीन चाहिए। हम 24 घंटे में वो जमीन आवंटित करके देंगे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मप्र शांति का टापू है। मप्र में स्किल्ड मैनपावर की कोई कमी नहीं है, जो मप्र आता है यहीं का होकर रह जाता है। हम सब कुछ सहयोग करने का काम करते हैं। हमारी पूरी कैबिनेट और ब्यूरोक्रेसी सपोर्ट करती है। हम आपको परेशान किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं केवल मुख्यमंत्री नहीं मप्र का सीईओ भी हूँ।

प्रवासी और इन्वेस्टर्स समिट के बाद अगले माह जी-20 की बैठक

प्रवासी सम्मेलन और इन्वेस्टर्स समिट की मेजबानी मिलने के बाद इंदौर को एक ओर मेजबानी के लिए तैयार किया जा रहा है। अगले माह इंदौर में जी-20 की बैठक का आयोजन होना है। कृषि समूह की एक दिनी बैठक के लिए इंदौर के होटल शेरटन ग्रैंड पैलेस का चयन किया गया है, जहां जी-20 देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इस बार जी-20 सम्मेलन की थीम एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य रखी गई है। भारत इस बार जी-20 सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और विभिन्न शहरों में अलग-अलग विषयों पर बैठकों का आयोजन होगा। 50 से अधिक शहरों में वर्कस्ट्रीम के स्कोर पर 200 से अधिक कार्यक्रम होंगे। इंदौर में अगले महीने की 13, 14 और 15 तारीख को बैठक होगी, जिसमें सभी देशों के प्रतिनिधि आएंगे। बैठक का आयोजन होटल शेरटन ग्रैंड पैलेस में किया जा रहा है। जी-20 के सदस्य देशों के रूप में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं, जिनके प्रतिनिधि इंदौर आएंगे, वहीं अतिथि देशों में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरीशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात भी हैं। 12 से 13 जनवरी के बीच ग्लोबल साउथ मीट होगी, जो वर्चुअली रहेगी। 16 से 17 जनवरी को पुणे में पहली इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रुप मीटिंग होगी। 18 से 20 जनवरी के बीच तिरुअनंतपुरम, 30 और 31 जनवरी को चंडीगढ़, 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच चेन्नई, 2 से 4 फरवरी के बीच जोधपुर, 2 और 3 फरवरी को गुवाहाटी, 5 से 10 जनवरी के बीच बेंगलुरु में कई विषयों पर बैठक रखी गई है। इसी तारीख में कच्छ में पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक, 13 से 15 फरवरी के बीच इंदौर में पहली कृषि कार्य समूह की बैठक होगी।

छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस सत्ता में बनी रहने के लिए अपने सभी विधायकों को ग्राउंड में उतार रही है। दूसरी तरफ भाजपा फिर से सत्ता की कुर्सी पाने के लिए ग्राउंड में कांग्रेस को घेरना चाहती है। लेकिन आखिर वो क्या मुद्दा होगा जो मैदान से सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता बनेगी।

दरअसल इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले के स्थिति में कांग्रेस प्रदेश में मजबूत नजर आ रही है। क्योंकि राज्य में पिछले 4 साल में हुए 5 उपचुनाव में कांग्रेस को ही जीत मिली है और भाजपा को करारी हार मिली है। इससे कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। लेकिन भाजपा ने भी पूरी ताकत से लड़ने का मन बना लिया है तो कांग्रेस के लिए ये सफर आसान नहीं होगा। क्योंकि बढ़ते अपराध को लेकर भाजपा ने बिलासपुर में पिछले साल बड़ा आंदोलन किया है। इसके साथ बेरोजगारी भत्ता के लिए रायपुर में बड़ी रैली की गई है और अब पीएम आवास और कर्मचारियों के नियमितीकरण के मामले में प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं।

छत्तीसगढ़ में अब तक धर्मांतरण के मुद्दे पर भाजपा आक्रामक मोड में है। नारायणपुर के बवाल के बाद भाजपा ने कांग्रेस को घेरना भी शुरू कर दिया है। रायपुर में हुए भाजपा के धरना प्रदर्शन में सभी नेताओं ने धर्मांतरण के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरा है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि धर्मांतरण का मुद्दा ट्राइबल इलाकों में ही है। मैदानी इलाकों में इसका असर बहुत कम है। लेकिन पूरे प्रदेश में आरक्षण का विवाद सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है।

दरअसल 19 सितंबर 2022 में हाईकोर्ट ने 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण को रद्द कर दिया। इससे राज्य के आदिवासियों को मिल रहे 32 प्रतिशत आरक्षण घटकर 20 प्रतिशत हो गया। इससे राज्य के आदिवासी समाज नाराज हो गए। इस मामले में सरकार की तरफ से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर आदिवासी आरक्षण 32 प्रतिशत करने का विधेयक पारित कर दिया और विधेयक राज्यपाल को भेज दिया गया। लेकिन विवाद यहां थमा नहीं। यहां से दोगुनी रफ्तार में प्रदेशभर में फैल गया। कांग्रेस सरकार ने आदिवासी ही नहीं ओबीसी और जनरल का भी आरक्षण बढ़ा दिया। सरकार ने ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस को 4 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया।

धर्मांतरण और आरक्षण चुनावी मुद्दा



विधेयक रोकने के पीछे भाजपा की ही साजिश

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि आरक्षण विधेयक के मामले में भाजपा की कथनी और करनी जनता के बीच में उजागर हो गई है। सदन में, जहां भाजपा के विधायक आरक्षण विधेयक को सर्वसम्मति से सहमति प्रदान करते हैं, वहीं जब आरक्षण विधेयक हस्ताक्षर के लिए राजभवन पहुंचता है, तब भाजपा आरक्षण को रोकने के लिए राजभवन के पीछे खड़ी होकर राजनीतिक षड्यंत्र करती है। प्रदेश के 76 प्रतिशत आबादी आरक्षण के अधिकार से वंचित करती है। आरएसएस और भाजपा से जुड़े बड़े नेता कई बार सार्वजनिक मंचों से आरक्षण को खत्म करने की बात कह चुके हैं। पूर्व की रमन सरकार के दौरान भी आरक्षण खत्म करने षड्यंत्र दिखा है।

इसके बाद राज्य का कुल आरक्षण 76 प्रतिशत हो गया। वर्गवार आरक्षण की बात करें तो अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत, ओबीसी-27, एसटी-32 और ईडब्ल्यूएस को 4 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया गया है। लेकिन सरकार के इस विधेयक को राज्यपाल ने एक महीने से मंजूरी नहीं दी है। इससे राज्य में भाजपा और कांग्रेस की मैदानी लड़ाई शुरू हो गई है।

आरक्षण पर कांग्रेस और भाजपा की जुबानी जंग अब मैदान-ए-जंग पर उतर आई है। नए साल के शुरुआत के साथ कांग्रेस और भाजपा दोनों आरक्षण पर एक-दूसरे को घेरने के लिए मैदान में उतर आई हैं। कांग्रेस ने 3 जनवरी को आरक्षण पर चुनावी साल का सबसे बड़ा प्रदर्शन किया है। मंच से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरक्षण की लड़ाई लड़ने का आव्हान किया है। इसके अलावा पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने मंच से चुनावी आगाज भी कर दिया। उन्होंने भाजपा को 15 से शून्य पर लाने की हजारों की भीड़ में ऐलान कर दिया। इससे अब तय माना जा रहा है कि आरक्षण पर कांग्रेस चुनावी साल में भाजपा को पीछे छोड़ने की तैयारी में है। इसके अलावा भाजपा भी आरक्षण पर ही कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। 4 जनवरी को भाजपा ने मुख्यमंत्री निवास घेराव करने की कोशिश की और पुलिस के साथ

झूमाझटकी हुई। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सरकार से जल्दी आरक्षण लागू करने की मांग की है और आरक्षण को लेकर सरकार पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। यानी भाजपा ने भी आरक्षण के मामले को अपने चुनावी मुद्दे में शामिल कर लिया है। अब आने वाले वक्त में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां आरक्षण पर एक-दूसरे को घेरते हुए दिखाई दे सकती हैं।

प्रदेश भाजपा प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कांग्रेस पर सवाल दागते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब यह पूछा कि 58 प्रतिशत आरक्षण जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, आप उसे फिर से लागू करवाना चाहते हैं तो भूपेश बघेल सरकार ने हां क्यों नहीं कहा? उसके लिए एक महीने का समय क्यों मांग लिया? सर्व आदिवासी समाज, अनुसूचित जाति समाज भी सरकार प्रायोजित कांग्रेस की तथाकथित महारैली को समर्थन नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि सभी अच्छी तरह समझ रहे हैं कि आरक्षण विरोधी कांग्रेस सभी वर्गों के साथ धोखेबाजी कर रही है। जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल की गरिमा के प्रतिकूल टिप्पणी कर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं तो यह स्पष्ट है कि उनके ही इशारे पर कांग्रेस स्तरहीन प्रपंच करते हुए जगह-जगह पोस्टर लगा रही है।

● रायपुर से टीपी सिंह

6

भारत जोड़ो यात्रा के बहाने राहुल गांधी खुद को पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कांग्रेस को भी पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दो साल से हवा बन रही थी कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों से भी पिछड़ गई है और क्षेत्रीय दल कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं। पंजाब में हार के बाद यह हवा कुछ ज्यादा ही तेजी से फैली थी। बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद ममता बनर्जी ने खुद को विपक्ष की धुरी बनाने की कोशिश की, तो बिहार में भाजपा से गठबंधन तोड़कर नीतीश कुमार ने विपक्ष का नेता बनने की कोशिश की।



2024 के लिए कांग्रेस की रणनीति

राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो पदयात्रा के जरिए और कुछ किया हो या न किया हो, दो काम तो सफलतापूर्वक कर दिए हैं। पहला यह कि वह पप्पू वाली छवि से बाहर निकल आए हैं और खुद को पूर्णकालिक राजनीतिज्ञ के तौर पर स्थापित किया है। दूसरा काम यह किया है कि उन्होंने इन महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय नेताओं को राजनीतिक तौर पर पीछे धकेल दिया है। कमलनाथ ने कह ही दिया है कि 2024 में राहुल गांधी विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे। इस पर नीतीश कुमार ने तो यह कहकर एक तरह से हथियार डाल दिए हैं कि राहुल गांधी को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ने पर उन्हें कोई ऐतराज नहीं। बाकी महत्वाकांक्षियों की अकड़ भी 2024 आते-आते ढीली पड़ जाएगी। अपनी पदयात्रा के दौरान दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने सभी क्षेत्रीय दलों को संदेश दिया है कि कांग्रेस फेडरलिज्म के आधार पर क्षेत्रीय दलों के साथ ऐसा गठबंधन करना चाहती है, जिसमें सबका सम्मान और बराबरी हो। कांग्रेस ने ऐसा पहली बार कहा है, जिसमें यह संदेश दिया गया है कि विपक्षी दलों का जो गठबंधन बनेगा, उसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं होगा। यानी जिस तरह पहले यूपीए चला या जिस तरह एनडीए चल रहा

है, विपक्ष का नया गठबंधन वैसा नहीं होगा। यह कुछ-कुछ वैसी ही रणनीति है, जैसी सोनिया गांधी ने 2004 के लोकसभा चुनाव से पहले अपनाई थी। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा को एक समान बताने वाले अखिलेश यादव को करारा जवाब देने की बजाय यह कहकर उप्र में उनका नेतृत्व स्वीकार करने का संदेश दिया कि उप्र में समाजवादी पार्टी भाजपा का विकल्प बन सकती है, लेकिन सारे देश में वह विकल्प नहीं बन सकती।

राहुल गांधी क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर संघीय मोर्चा बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन पुराने कांग्रेसियों की घर वापसी के प्रयास शुरू कर दिए हैं, जो भाजपा के साथ नहीं हैं। जिनमें ममता बनर्जी, जगनमोहन रेड्डी, केसीआर और कोनाई संगमा चार तो मुख्यमंत्री ही हैं। ये चारों अपनी क्षेत्रीय पार्टियां बनाकर अपने बूते पर मुख्यमंत्री बने हैं। इनमें से सिर्फ ममता बनर्जी ने ही सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने से पहले कांग्रेस छोड़ी थी, बाकी तीनों सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद उन्हीं से मतभेदों के चलते कांग्रेस छोड़कर गए। अगर बदली हुई कांग्रेस इन नेताओं को उनके राज्यों में उन्हें ही क्षेत्रप मानने को तैयार हो जाए, तो 2024 में भाजपा को

मुस्लिम तुष्टीकरण वाली राजनीति का प्रभाव हुआ कमजोर

बीते एक दशक में भारत की राजनीतिक सच्चाई तो यह हो गई है कि राजनीतिक रैलियों या सम्मेलनों में दाढ़ी-टोपी वाले लोगों को बढ़ा चढ़ाकर शामिल करने से राजनीतिक दल ही बचने लगे हैं। भारत की मुस्लिम तुष्टीकरण वाली राजनीति का प्रभाव कमजोर हुआ है। उन्हें भी उसी तरह एक सामान्य वोटर समझा जा रहा है जैसे बाकी वोटर हैं। तो क्या राहुल गांधी की नफरत छोड़े, भारत जोड़ो का नारा मुस्लिम राजनीति को फिर से उसी तरह स्थापित करने की पहल है, जैसा 2014 से पहले हुआ करती थी? पदयात्रा के बीच राहुल गांधी बार-बार जो बोल रहे हैं उससे संदेश तो यही जा रहा है कि वो राजनीति में रिलीजियस माइनोरिटी की सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। उनके बयान, उनके नारे ये संदेश दे रहे हैं कि 2014 के बाद भारत के धार्मिक अल्पसंख्यक हाशिये पर चले गए हैं। इस हाशिये को ही उन्होंने संभवतः नफरत से परिभाषित किया है और उनको राजनीति की मुख्यधारा में स्थापित करने को ही प्यार का नाम दिया गया है, जिसका दुकानदार स्वयं राहुल गांधी अपने आप को घोषित कर ही चुके हैं।

9

चुनौती देने वाली सशक्त कांग्रेस पुनर्जीवित हो सकती है। गांधी परिवार को एहसास हो गया है कि उसे कांग्रेस के क्षेत्रों की अनदेखी करके दिल्ली से पार्टी और राज्यों की कांग्रेसी सरकारें चलाने का खामियाजा भुगतना पड़ा है।

कांग्रेस आलाकमान तानाशाहीपूर्ण व्यवहार नहीं करता और ममता बनर्जी, जगनमोहन रेड्डी, केसीआर और कोनार्ड संगमा के हाथों में उनके राज्यों की बागडोर दी होती, तो न वे कांग्रेस छोड़कर जाते, न कांग्रेस देश में इतनी कमजोर होती। इस मंथन के बाद गांधी परिवार और कांग्रेस के बाकी नेताओं के रुख में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कोशिश यह हो रही है कि जो छोड़कर गए हैं, उन्हीं की शर्तों पर उन सबकी घर वापसी करवाई जाए। जो बात असंभव सी लगती है, उसकी बड़ी शुरुआत 29 दिसंबर को हो गई है, जब कांग्रेस छोड़ने के 23 साल बाद कांग्रेस स्थापना दिवस पर शरद पवार पुणे में कांग्रेस के दफ्तर पहुंचे। हालांकि यह भी बड़ी घटना है, लेकिन इससे बड़ी घटना यह है कि उन्होंने वहां अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया, जिन्होंने 2014 से भारत को कांग्रेस मुक्त करने का बीड़ा उठाया हुआ है। शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस इस देश की रग-रग में है, वह कभी खत्म नहीं होगी।

शरद पवार ने 1999 में विदेशी मूल के मुद्दे पर तब कांग्रेस छोड़ दी थी, जब वाजपेयी सरकार गिराने के बाद सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहती थीं। शरद पवार के साथ पीए संगमा और तारिक अनवर ने भी विदेशी मूल के मुद्दे पर ही कांग्रेस छोड़ी थी, तारिक अनवर कांग्रेस में लौट चुके हैं। शरद पवार अब उन्हीं सोनिया गांधी की रहनुमाई वाले यूपीए में शामिल हैं और यूपीए सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। शरद पवार के अलावा गुलामनबी आजाद बड़े नेता हैं, जिन्होंने हाल ही में राहुल गांधी से मतभेदों के चलते पार्टी छोड़ी थी। अभी यह तो नहीं कहा जा सकता कि मल्लिकार्जुन खड्गे ने किस से बात की है, और किस से नहीं की है, लेकिन सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। गुलामनबी आजाद ने इन खबरों का खंडन किया है कि वह कांग्रेस में वापस लौट रहे हैं, उन्होंने किसी बातचीत से भी इनकार किया है। उनकी रणनीति दूसरी है, वह जम्मू-कश्मीर में चुनाव बाद भाजपा से गठबंधन कर वहां राष्ट्रवादी सरकार बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस कभी मुप्ती परिवार, तो कभी अब्दुल्ला परिवार से गठबंधन कर उन्हीं की सरकार बनवाने की रणनीति पर चलती रही है। एक बार जरूर तीन साल के लिए गुलामनबी आजाद मुख्यमंत्री बने थे।

राहुल गांधी ने कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए तीन बड़े कदम उठाए हैं। उनका पहला कदम यह था कि उन्होंने खुद कांग्रेस अध्यक्ष



कांग्रेस भी कम्युनिस्ट पार्टियों की राह पर

90 के दशक में जब राम मंदिर आंदोलन के कारण मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ध्वस्त होनी शुरू हो गई तो सेक्युलर खेमे में बहुत हलचल हुई थी। उस समय सेक्युलर राजनीति के सारे कर्मकांड कम्युनिस्ट पार्टियां तय करती थीं। भाजपा की बढ़त से बेचैनी इतनी बढ़ी कि पहले भाजपा को लंबे समय तक कम्युनल या सांप्रदायिक दल कहा गया लेकिन जब लगा कि इतने से बात नहीं बनेगी तो कम्युनिस्ट पार्टियों ने दूसरी चाल चली। सेक्युलर पार्टियों की पटना में हुई एक रैली में सीपीआई के महासचिव एबी वर्धन ने हिंदू वोटर्स से अपील करते हुए भगवान राम का वास्ता देकर भाजपा को वोट न करने की अपील ही कर दी थी। आप कह सकते हैं कि यह कम्युनिस्ट पार्टियों का प्लान बी था। जिस राम को काल्पनिक चरित्र बताकर कम्युनिस्ट पार्टियां उनका अपमान करती थीं, अचानक से उन्हें वो ऐसे आदर्श पुरुष नजर आने लगे जिनके अनुयायी कभी भी भाजपा जैसी कम्युनल पार्टी को वोट दे ही नहीं सकते। अपनी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने जब-जब राम का जिक्र किया तब-तब एबी वर्धन वाली सोच ही सामने रखी कि राम महान थे लेकिन उनके अनुयायी आरएसएस और भाजपा जैसे नफरत फैलाने वाले लोगों का साथ कैसे दे सकते हैं? भले ही भारत में कम्युनिस्ट पार्टियों का पतन हो गया है लेकिन कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोग आज भी एक प्रेशर ग्रुप के रूप में बहुत प्रभावशाली हैं। एनजीओ, पत्रकारिता, न्यायापालिका, फिल्म और साहित्य में आज भी कम्युनिस्ट एक ताकतवर लॉबी के रूप में मौजूद हैं। कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े कन्हैया कुमार हों या फिर संदीप सिंह। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के अगुवा यही लोग हैं। वही लोग राहुल गांधी के आंख-कान हैं। वो जैसा भारत राहुल गांधी को दिखाते हैं, राहुल गांधी वैसा ही भारत देखते हुए दिल्ली पहुंच जाते हैं।

बनने से इनकार कर कांग्रेस संगठन को गांधी परिवार से बाहर लाने में प्रमुख भूमिका निभाई। नए अध्यक्ष का चुनाव बाकायदा गुप्त मतदान के जरिए करवाया गया, जिसने एक बार फिर साबित किया कि कांग्रेस दूसरे दलों से अलग है और उसमें अंदरूनी लोकतंत्र की बेहद गुंजाइश है। इसका श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को दिया जा सकता है तो वह राहुल गांधी हैं। यह प्रयोग अन्य राजनीतिक दलों के लिए चुनौती है, जहां बंद कमरों में सर्वोच्च नेतृत्व ही अध्यक्ष चुन लेता है। दूसरा कदम उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का उठाया, जिसने अखबारी सुर्खियों से गायब हुई कांग्रेस को एक बार फिर घर-घर में पहुंचा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंसों, बयानों और ट्विटर से बाहर निकलकर कांग्रेस जमीन पर दिखाई दे रही है। राहुल गांधी का तीसरा कदम अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक पर जाना है। इस एक कदम के जरिए

उन्होंने भाजपा और अन्य दलों के ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश की है। ब्राह्मण भारतीय राजनीति की रीढ़ की हड्डी रहे हैं। 1952 के पहले चुनावों के बाद भारत के 22 राज्यों में से 13 में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने थे। पहली लोकसभा में हर चौथा सांसद ब्राह्मण था। 1989 में मंडल-कमंडल की राजनीति ने ब्राह्मणों को हाशिए पर ला दिया है। इस समय देश में सिर्फ ममता बनर्जी और हेमंत बिस्व सरमा ही ब्राह्मण मुख्यमंत्री हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार दो लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी हार के बाद, जब राहुल गांधी खुद अमेठी में हार गए, तो ऐसा लगता था कि राहुल गांधी राजनीति में पिट चुके हैं। लेकिन अपनी 3500 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उन्होंने खुद को पुनर्स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया।

● विपिन कंधारी

दिल्ली की कुर्सी समेत सबसे अधिक सूबों में भाजपा और उसके सहयोगियों की सत्ता है। इसलिए अपनी हुकूमतों को बचा पाने के लिए भाजपा के लिए आगामी वर्ष बेहद चुनौतीपूर्ण और सियासी त्वस्तता भरा होगा। कांग्रेस और भाजपा विरोधी तमाम क्षेत्रीय दलों के लिए 2023 करो या मरो के संघर्ष से भरा होगा। साल 2023 के शुरु से लेकर अंत तक 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन्हें सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। कर्नाटक, मप्र और त्रिपुरा में भाजपा की सरकार है जबकि नागालैंड, मेघालय और मिजोरम की सत्ता पर क्षेत्रीय दल काबिज है, लेकिन भाजपा सहयोगी दल के तौर पर है।



बिछेगी 2024 की सियासी बिसात...

साल 2022 अलविदा हो चुका है और नए साल की दस्तक के साथ हम 2023 में प्रवेश कर गए हैं। भारत के सियासी परिदृश्य के लिहाज से 2023 को चुनावी साल के तौर पर देखा जा रहा है। इस साल दक्षिण भारत से लेकर पूर्वोत्तर और उत्तर भारत के हिंदी पट्टी वाले राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि साल 2023 के चुनावी नतीजे और राजनीतिक गतिविधियों से सिर्फ 2024 की सियासी बिसात ही नहीं बिछेगी बल्कि लोकसभा चुनाव की दशा और दिशा भी तय हो जाएगी?

साल 2023 के शुरु से लेकर अंत तक 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। साल के शुरु में चार राज्यों में चुनाव हैं जबकि साल के आखिर में पांच राज्यों में चुनाव हैं। दक्षिण भारत के कर्नाटक और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होंगे तो पूर्वोत्तर के मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम में चुनाव होने हैं जबकि हिंदी पट्टी के तीन बड़े राज्यों मप्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने हैं।

कर्नाटक, मप्र और त्रिपुरा में भाजपा की सरकार है जबकि नागालैंड, मेघालय और मिजोरम की सत्ता पर क्षेत्रीय दल काबिज है, लेकिन भाजपा सहयोगी दल के तौर पर है। वहीं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है तो तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस

काबिज है। इन राज्यों के चुनाव देश की सियासत के लिहाज से बेहद अहम हैं, क्योंकि इसके ठीक बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में ज्यादातर राज्यों में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है तो क्षेत्रीय दलों की भी अग्निपरीक्षा है।

जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इस साल होंगे या नहीं यह तस्वीर साफ नहीं है। हालांकि, जम्मू-कश्मीर के सीटों का परिसीमन हो चुका है और चुनाव कराने के लिए केंद्र की मोदी सरकार कह चुकी है कि जल्द ही चुनाव कराए जाएंगे। जम्मू-कश्मीर के मौसम को देखते हुए अप्रैल-मई में कर्नाटक के साथ विधानसभा चुनाव कराए

जाने के आसार हैं। ऐसा होता है तो फिर साल 2023 में कुल 10 राज्यों में चुनाव होंगे।

साल 2023 में 9 राज्यों के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर के चुनाव होते हैं तो फिर कुल 10 राज्यों में चुनाव होंगे। इन 10 राज्यों में लोकसभा की 83 सीटें आती हैं, जो कुल 543 संसदीय सीटों की 17 फीसदी सीटें होती हैं। ऐसे में 2023 के चुनावी नतीजों का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। इसीलिए साल 2023 को देश की सियासत के लिए काफी अहम माना जा रहा है। 2023 में देश के जिन राज्यों में चुनाव हैं, उनमें से ज्यादातर और अहम राज्यों में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला होगा। मप्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में कांग्रेस और भाजपा के बीच

दक्षिण-पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय दलों का टेस्ट

साल 2023 में कांग्रेस-भाजपा ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय दलों को भी आजमाइश से गुजरना होगा। दक्षिण भारत के कर्नाटक में जेडीएस को भी अपने सियासी वजूद को बचाए रखने के लिए जद्दोजहद करनी होगी जबकि तेलंगाना में बीआरएस के लिए इस बार भाजपा से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा ने केसीआर के खिलाफ आक्रामक मोर्चा खोल रखा है तो कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में भी क्षेत्रीय दलों से ही दो-दो हाथ करने होंगे। त्रिपुरा में लेफ्ट को अपनी वापसी के लिए भाजपा से ही नहीं बल्कि टीएमसी से भी टकराना होगा। ऐसे ही मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में कांग्रेस के अगुवाई वाले क्षेत्रीय दलों के गठबंधन और भाजपा के गठबंधन से मुकाबला है। ऐसे में अगर क्षेत्रीय दलों ने अपना प्रदर्शन बेहतर किया तो छोटे दलों की अहमियत बढ़ेगी।

सीधी चुनावी जंग होगी। इन चार राज्यों में से कांग्रेस और भाजपा के पास दो-दो राज्य हैं। ऐसे में कांग्रेस अपने दोनों राज्यों की सत्ता को बचाए रखते हुए भाजपा से कर्नाटक और मद्रास की सत्ता हासिल करने की कोशिश में रहेगी। लेकिन राजस्थान का सियासी रिवाज हर 5 साल पर सत्ता परिवर्तन का रहा है। ऐसे में कांग्रेस के लिए काफी जद्दोजहद करनी होगी। वहीं, भाजपा को 2018 में इन चारों राज्यों में हार का मुंह देखना पड़ा था, कर्नाटक में वह बहुमत नहीं साबित कर पाई थी। 2019 के बाद मद्रास और कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस के जरिए कांग्रेस विधायकों के बगावत से भाजपा को सरकार बनाने का मौका मिला। ऐसे में भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती दक्षिण भारत के अपने इकलौते दुर्ग को बचाए रखने की है, क्योंकि रेड्डी बंधु ने अपनी अलग पार्टी बना ली है और बीएस येदियुरप्पा भी मुख्यमंत्री की कुर्सी बसवराज बोम्मई को सौंप चुके हैं। ऐसे में भाजपा की कोशिश रहेगी कि अपने इन दोनों किलों को बचाकर कांग्रेस के हाथों से मद्रास और राजस्थान छीन ले।

वर्ष 2023 सियासी सरगमियों और चुनावों के नाम होगा। इस वर्ष देश के करीब दस राज्यों में चुनाव हो सकते हैं। 2024 के शुरू में ही लोकसभा चुनाव होने हैं इसलिए 2023 को लोकसभा का चुनावी वर्ष भी मान सकते हैं। इसी साल लोकसभा चुनाव के रण की तैयारी भी होगी और विभिन्न सूबों में विधानसभा चुनावों का भी तांता लगा रहेगा। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उप्र का निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण प्रकरण के बाद काफी अहम और चर्चित हो गया है। ये चुनाव भी 2023 में ही होना है। दिल्ली की कुर्सी समेत सबसे अधिक सूबों में भाजपा और उसके सहयोगियों की सत्ता है इसलिए अपनी हुकूमतों को बचा पाने के लिए भाजपा के लिए आगामी वर्ष बेहद चुनौतीपूर्ण और सियासी व्यस्तता भरा होगा। कांग्रेस और भाजपा विरोधी तमाम क्षेत्रीय दलों के लिए 2023 करो या मरो के संघर्ष से भरा होगा। भाजपा जैसे शक्तिशाली दल से लड़ने के लिए आगामी वर्ष में विपक्षी दलों की एकजुटता के प्रयास किसी बड़ी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होंगे।

विभिन्न राज्यों के चुनावी नतीजे लोकसभा चुनाव के नतीजों की आशंकाएं बताएंगे। मद्रास, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और जम्मू-कश्मीर में भी 2023 में चुनाव हो सकते हैं।

राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार वापसी का संघर्ष करेगी और मद्रास में भाजपा को ये संघर्ष करना होगा। 2018 में मद्रास में कांग्रेस जीती थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ तमाम कांग्रेसी विधायकों की बगावत ने भाजपा सरकार बनवा दी। छत्तीसगढ़ एक ऐसा सूबा है जहां कांग्रेस ने मजबूती से जीत हासिल की थी और भाजपा की करारी हार हुई थी। 2018 के



विपक्षी एकता की बिछेगी बिसात

2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकजुटता की कवायद 2023 में ही होनी है। इतना ही नहीं 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर भी कोशिशें तेज होंगी। 2023 में होने वाले चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती है तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए को टक्कर देने वाले एक मजबूत विपक्षी ताकत के तौर पर उभरकर सामने आएगी। वहीं, कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर नहीं हुआ और अपने दो राज्यों से किसी को गंवाती है तो उस पर क्षेत्रीय दलों का दबाव बढ़ेगा, क्योंकि केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी, केसीआर, नीतीश कुमार तक अपनी-अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। बिहार में सियासी बदलाव के बाद से नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकता का नारा बुलंद किए हुए हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी, केसीआर, शरद पवार जैसे नेता अपने-अपने स्तर पर लगातार विपक्षी एकजुटता की कवायद में जुटे हैं। ऐसे ही देश की सियासत में तेजी से आम आदमी पार्टी अपनी जगह बनाती जा रही है। दिल्ली के बाद पंजाब में उसकी सरकार है और गुजरात और गोवा में उसके विधायक हैं। दिल्ली एमसीडी में भी काबिज हो गई है और अपना मेयर बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में साल 2023 में विपक्षी दलों की गोलबंदी तेजी से होने की उम्मीद है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए महज एक साल से भी कम वक्त बचेगा।

खंडित जनादेश के बाद कर्नाटक का सियासी नाटक सबको याद होगा। यहां किसी को बहुमत नहीं मिला था। पहले कांग्रेस ने जेडीएस को समर्थन दिया और कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने। फिर बाद में तमाम उठापटक के बाद भाजपा ने कर्नाटक में सरकार बनाने में सफलता हासिल कर ली थी।

ऐसे ही देश के कई राज्यों में कांग्रेस, भाजपा और क्षेत्रीय दलों का कॉकटेल जनाधार विधानसभा चुनावों में ये भी तय करेगा कि किस क्षेत्रीय दल का किस राष्ट्रीय पार्टी से कैसा रिश्ता है! 2023 में लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनावों की तैयारियों की बेला में सरकारें जनकल्याणकारी योजनाओं की झड़ी से जनता को लुभाने का भरपूर प्रयास करेंगी। इसके अतिरिक्त चुनावी सियासत ध्रुवीकरण के प्रयास और भावनात्मक कार्ड खेलने का माहौल भी पैदा कर सकती है। 2023 में ही अयोध्या में निर्माणाधीन राममंदिर का

निर्माण भी पूरा हो जाने की पूरी संभावना है। और 23-24 में बहुचर्चित और बहुप्रतीक्षित राम मंदिर में दर्शन के लिए रामभक्तों का प्रवेश भी प्रारंभ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त संभावना है कि समान नागरिक कानून पास करवाकर भाजपा चुनावों में लाभ लेने का प्रयास करे। हिंदुत्व, विकास, राष्ट्रवाद के मुद्दों और ध्रुवीकरण की बिसात की काट के बीच पिछड़ा वर्ग, आरक्षण, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों का शोर भी 2023 में सुनाई देगा।

उप्र में कांग्रेस भारत में यात्रा के माध्यम से अपने संगठन को मजबूत करने के साथ-साथ इस साल होने वाले छह अलग-अलग राज्यों के चुनावों में मजबूती की आधारशिला भी इसी राज्य से रखेगी। कांग्रेस पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि पार्टी की ओर से उनको निर्देश मिल चुके हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ-साथ किस तरह से उन्हें संगठनात्मक स्तर पर अपने सिस्टम को मजबूत करना है। सूत्रों के मुताबिक उप्र के कांग्रेस नेताओं का एक बड़ा दल छत्तीसगढ़ में होने वाले कांग्रेस के बड़े आयोजन में शिरकत करेगा। छत्तीसगढ़ के बाद पार्टी उत्तर भारत के नेताओं को दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर में भी चुनावी अभियान में हिस्सा लेने के लिए भेजेगी। कांग्रेस पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता बताते हैं कि क्योंकि इस साल कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसलिए पार्टी ने संगठन को मजबूत करने के लिए बीस-बीस नेताओं के चार ग्रुप बनाने के निर्देश दिए हैं।

● इन्द्र कुमार

उप्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होता दिख रहा है। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस एक धुरी पर आती हुई दिख रही हैं। इस मुद्दे पर चर्चा की बड़ी वजह जौनपुर से बसपा सांसद श्याम सिंह यादव का कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना है। श्याम सिंह यादव भले ही कह रहे

हैं कि उनका राहुल गांधी की ओर से निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना व्यक्तिगत निर्णय था। वे राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की नीति और नीयत से प्रभावित होकर इसमें शामिल हुए। लेकिन, राजनीतिक जानकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़े राजनीतिक बदलाव के रूप में इसे देख रहे हैं। श्याम सिंह यादव पहले से बसपा और कांग्रेस गठबंधन की बात करते रहे हैं। संकेत दिया गया है कि वर्ष 2024

के लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों का गठबंधन हो सकता है। हालांकि, बसपा प्रमुख मायावती की ओर से कोई संकेत अभी तक नहीं आया है। नया साल उप्र में नए गठबंधन की उम्मीद और विपक्षी दलों के लिए कुछ नए सपनों के साथ आ रहा है। ताजा संकेत निश्चित तौर पर प्रदेश के राजनीतिक माहौल को गरमाने वाले हैं। बसपा अध्यक्ष मायावती पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों पर समान रूप से आक्रामक रही हैं। लेकिन, तमाम गिले-शिकवों को भुलाकर आगे बढ़ती दिख सकती हैं। मायावती की कोशिश अखिलेश यादव को विपक्ष के चेहरे से हटाकर प्रदेश स्तर पर भाजपा के मुकाबले में खुद को खड़ा दिखाने की है। ऐसे में इस प्रकार की चर्चाओं को एक बड़े वोट बैंक को एकजुट करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। अगर निकाय चुनाव में बसपा की रणनीति काम कर गई तो 2024 के लिए राह खुल जाएगी।

बसपा के रुख में बदलाव का बड़ा कारण पिछले विधानसभा चुनाव रहे हैं। वर्ष 2007 में बहुजन से सर्वजन तक का सफर तय करने वाली मायावती ने बसपा को प्रदेश की सत्ता में पूर्ण बहुमत दिला दी। तब बसपा के दलित, ओबीसी, मुस्लिम समीकरण के साथ ब्राह्मण वोट बैंक साथ आया। लेकिन, सरकार बनने के बाद ब्राह्मणों की उपेक्षा शुरू हुई। परिणाम 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा को घाटे के रूप में झेलना पड़ा। 2009 के लोकसभा चुनाव में उप्र की राजनीति में कांग्रेस करीब दो दशक बाद उभरी थी। केंद्र में मनमोहन सरकार की वापसी की राह उप्र से निकली। उस समय कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन की बातचीत चल रही थी। लेकिन, सपा ने कांग्रेस को 13 सीटों का ऑफर दिया। पार्टी ने अकेले लड़ने का फैसला किया। 18.2 फीसदी

कांग्रेस-बसपा में बड़ी नजदीकी



बसपा गठबंधन के सहारे हो सकती है मजबूत

बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में पांच साल पहले के रिजल्ट को सुधारने की कोशिश करती दिख रही है। इसके लिए मायावती लगातार जिला स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही हैं। एक बार फिर दलित, ओबीसी, मुस्लिम समीकरण को साधने की कोशिश है। बसपा का मास्टरप्लान रेडी है। मायावती की हरी झंडी मिल चुकी है। इमरान मसूद जैसे पश्चिमी उप्र के कद्दावर नेताओं को पार्टी ने जोड़कर अपनी रणनीति साफ कर दी है। हालांकि, मायावती को एक ऐसे साथी की जरूरत है, जो वोट बैंक को उनकी तरफ ट्रांसफर कराए। कांग्रेस उप्र में ब्राह्मण, ओबीसी और मुस्लिम वोट बैंक पर अपनी पकड़ रखती थी। इनके सहारे सत्ता की सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करती थी। मायावती ने बहुजन वोट बैंक पर फोकस किया है। ऐसे में वह कांग्रेस के सहारे सर्वार्थ वोट बैंक को साधने की कोशिश कर सकती है।

वोट शेयर के साथ कांग्रेस पार्टी ने 21 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उप्र चुनाव 2007 में कांग्रेस को 19 फीसदी ब्राह्मण वोट बैंक गए थे। महज दो साल बाद हुए चुनाव में पार्टी ने 31 फीसदी ब्राह्मण वोट हासिल किया। इस चुनाव में सपा को 23 और भाजपा को 10 सीटों पर जीत मिली थी। सत्ताधारी मायावती की पार्टी बसपा 20 सीटों पर जीत दर्ज कर तीसरे स्थान पर रही थी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बसपा 2009 के परिणाम और तत्कालीन सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश करती दिख सकती है।

5 साल बाद यानी 2014 के चुनाव में बसपा का वोट बैंक सिकुड़ा और पार्टी राज्य की सत्ता वर्ष

2012 में गंवाने के बाद लोकसभा से साफ हो गई। मायावती ने इस चुनाव में पूरा जोर लगाया। लेकिन, भाजपा के ब्रांड मोदी के आगे न मायावती टिकीं और न ही सत्ताधारी समाजवादी पार्टी। इस चुनाव में भाजपा गठबंधन यानी एनडीए ने 73 सीटों पर जीत दर्ज की। 5 सीटें सपा और 2 सीटें बसपा के पाले में गईं। पार्टी चुनाव में 19.60

फीसदी वोट ही मिले। 22 से 25 फीसदी वोट बैंक की राजनीति करने वाली मायावती का आधार वोट खिसका। इसके बाद से बसपा संभल नहीं पाई है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं ने भाजपा का दामन थामा तो ओबीसी वोट बैंक मजबूती के साथ भाजपा से जुड़ गया। भाजपा में गए तो दलित और अति पिछड़े वर्ग के वोटों को एक नया ठिकाना दिखा। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में इसका असर दिखा। बसपा को 22.24 फीसदी

वोट तो मिले, लेकिन पार्टी सिर्फ 19 सीटों पर सिमट गई। इसके बाद एक बार फिर 26 साल बाद सपा और बसपा का गठबंधन हुआ। उप्र की राजनीति में कल्याण सिंह और राम मंदिर मुद्दे की हवा निकालने वाली मुलायम सिंह यादव और काशीराम की जोड़ी की दोनों पार्टियां एक धुरी पर आईं।

2019 के चुनाव में इसका असर दिखा। 2014 के लोकसभा चुनाव में 71 सीट जीतने वाली भाजपा 62 सीटों पर आई। एनडीए ने कुल 64 सीटें जीतीं। यानी, 5 साल में 9 सीटों का नुकसान। फायदे में मायावती की बसपा रही। पार्टी ने सपा से गठबंधन का फायदा उठाते हुए 10 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं, सपा 5 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। कांग्रेस घटकर एक सीट पर पहुंच गई। वर्ष 2019 के चुनाव में बसपा का वोट शेयर सपा से गठबंधन के बाद भी 19.3 फीसदी रहा। सपा 18 फीसदी वोट शेयर के साथ तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस 6.31 फीसदी वोट शेयर ही हासिल कर पाई। भाजपा ने 49.6 फीसदी वोट शेयर के साथ प्रदेश की राजनीति पर अपना दबदबा दिखाया। उप्र चुनाव 2022 भी कांग्रेस और बसपा के लिए मुश्किलों भरा रहा है। उप्र में चार बार सरकार बनाने वाली बसपा केवल 12.88 फीसदी वोट ही हासिल कर पाई। पार्टी को केवल एक सीट पर जीत मिली। विधानसभा में विलुप्त होने से तो पार्टी बच गई, लेकिन आधार वोट ही खो दिया। भाजपा ने एक बार फिर सभी दलों को पछाड़ा। पार्टी ने 41.76 फीसदी वोट शेयर हासिल किया। वहीं, सपा 32.02 फीसदी वोट शेयर के साथ दूसरे स्थान पर रही। वहीं, कांग्रेस 2.4 फीसदी वोट शेयर हासिल कर पाई। कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर जीत मिली।

● लखनऊ से मधु आलोक निगम

महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच रार ठनी हुई है। दोनों सरकारों के मुखिया, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई और महाराष्ट्र के असली मुख्यमंत्री, वैसे उपमुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस सार्वजनिक रूप से एक दूजे को ललकार रहे हैं। बात पुलिस तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र भाजपा की पहल पर कर्नाटक में स्थित बेलगाम (इसे कर्नाटक बेलगावी और बेलगाव कहके पुकारता है) में उकसावे के लिए रखी गई एक कॉन्फ्रेंस में जाने वाले महाराष्ट्र के नेताओं को कर्नाटक की पुलिस ने रोककर वापस रवाना कर दिया। गर्मागर्मी और बढ़ी। इधर महाराष्ट्र की विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर कर्नाटक की निंदा की गई, उधर कर्नाटक इसी भाषा में इसका जवाब देने की तैयारी में जुट गया। ध्यान रहे कि दोनों ही राज्यों की सरकारें भाजपा सरकारें हैं। बोम्मई और फडणवीस दोनों ही भाजपा के बड़े नेता हैं।

झगड़ा राज्यों के पुनर्गठन के समय कुछ गांवों के इस या उस राज्य में शामिल होने या न होने को लेकर है, आज से नहीं है, तभी से है। एक आयोग बन चुका। कुछ गांवों के बारे में उसका निराकरण आ चुका, मगर मतभिन्नता बनी रही। अभी भी गांवों के इधर-उधर लिए-दिए जाने के दोनों राज्यों के दावों पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है। सभ्य समाज में कायदे की बात तो यह होती कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार किया जाता। जो भी आता उसे लागू किया जाता। मगर यहां न कायदे से कोई मतलब है न सभ्यता से ही कोई ताल्लुक है। इसलिए फैसले का इंतजार करने की बजाय दोनों भाजपाई सरकारें अपनी सीमाओं को कुरुक्षेत्र बनाने पर आमादा हैं। खबर यह है कि भाजपा सत्ता में नेतृत्व क्रम जहां पूरा हो जाता है उस दो नंबर पर विराजे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दोनों मुख्यमंत्रियों को बुलाकर उन्हें समझाते हैं। परिणाम यह है कि बजाय इसके कि माहौल में नरमी आती, दोनों अपने-अपने प्रदेशों की राजधानियों में पहुंचकर पहले से भी ज्यादा ऊंचे स्वर पर बोलना शुरू कर देते हैं।

ताज्जुब की बात नहीं होगी यदि कुछ महीनों में महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा पर दोनों तरफ की पुलिस एक-दूसरे के सामने अटेंशन की मुद्रा में राइफल ताने खड़ी नजर आए। पिछली साल ही यह अशुभ भी हो चुका है जब असम और मिजोरम पुलिस की आमने-सामने की भिड़ंत में 6 पुलिस सिपाही



महाराष्ट्र और कर्नाटक में रार

मारे गए थे। आज भी इन दोनों प्रदेशों की सीमाओं पर उनके प्रदेशों की पुलिस अलर्ट है। असम में भाजपाई मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर के अपने से छोटे और नन्हें राज्यों के खिलाफ जैसे कमान ही संभाली हुई है। सीमा को लेकर उनका पंगा सिर्फ मिजोरम के साथ ही नहीं था, उनका विवाद मेघालय से भी है, नागालैंड से भी है, अरुणाचल प्रदेश से भी है। होने को तो यह मसले पहले से चले आ रहे हैं मगर भाजपा के आने के बाद इनकी तीव्रता और तीक्ष्णता दोनों बढ़ी हैं। यह अतिरिक्त चिंता का विषय है क्योंकि समूचे पूर्वोत्तरी राज्यों की संवेदनशील पृष्ठभूमि रही है। इनके संघीय गणराज्य भारत का अंग बनने की लंबी प्रक्रिया चली है। उसे देखते हुए इस तरह के टकराव मुश्किल में डालने वाले हो सकते हैं। मगर भाजपा को इसकी परवाह नहीं है।

अचानक ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि एक ही पार्टी (वह भी खुद को भूतो न भविष्यतः टाइप की राष्ट्रवादी मानने वाली पार्टी) की दो सरकारें, एक ही पार्टी के दो नेता एक-दूसरे के सामने तलवारें भांज रहे हैं, पड़ोसी और शत्रु देशों की तरह एक-दूजे को द्वंद युद्ध के लिए ललकार रहे हैं? यह रोग, लक्षण दोनों के साथ उसका योजनाबद्ध तरीके से फैलाया जा रहा संक्रमण भी है। यह डिवाइडर इन चीफ के वायरसों के नए रूपों, संस्करणों की बढ़ती मारकता का भी एक नया आयाम है। विभाजन की प्रक्रिया विग्रह से शुरू होती है, विद्वेष से होती हुई अपने तार्किक अंत विखंडन तक पहुंचती है। इसका अपना डायनामिक्स (गत्यात्मकता) होती

है। यह जब शुरू होती है तो सिर्फ जिसके खिलाफ शुरू हुई या की गई होती है सिर्फ उस तक ही नहीं टिकती। अंधड़ के उभरते हुए बगुले की तरह अपनी तेज से निरंतर तेजतर होती गति में हरेक को समेट लेती है, अपनी परिधि में सबकुछ चपेट लेती है।

हाल के कुछ दशक इसका उदाहरण हैं, जहां हम और वे की शिनाख्त की शुरुआत धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाने पर लेने से हुई और फिर हिंदी-उर्दू, बामन-ठाकुर, अवर्ण-सवर्ण, सवर्णों और अवर्णों के भीतर भी वो और हम की खाइयां चौड़ी करते हुए अब देश के भीतर प्रदेशों के बीच सीमाएं बनाने और उन पर इन राज्यों के अर्धसैनिक बलों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करने तक आ पहुंची है। यह अनायास नहीं है। महाराष्ट्र कर्नाटक और असम के भाजपाई मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री राजनीतिक नौसिखिए नहीं हैं। ऐसा नहीं कि वे नहीं जानते कि इस तरह के मुद्दे हल करने के तरीके क्या हैं। मगर जब फूट, विग्रह और विभाजन राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बन जाए, चुनाव जीतने का जरिया बन जाए, जैसे भी हो वैसे चुनाव जीतना ही एकमात्र लक्ष्य रह जाए और इस जीत की हांडी पकाने के लिए इस तरह के उन्माद की आग सुलगाना चतुराई और कथित चाणक्य नीति मानी जाने लगे तो आधी सदी पुरानी कब्रें खोदने के इस तरह के कारनामे होना तय है। इसकी निचाई की कोई सीमा नहीं होती। त्रिपुरा में चुनाव जीतने के लिए किन-किन से गठबंधन करके चुनाव लड़ा गया यह सारा देश जानता है।

● बिन्दु माथुर

विपक्ष का आरोप है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों प्रदेशों की भाजपा अपने-

अपने राज्यों में क्षेत्रीयतावादी उन्माद भड़काकर वही करना चाह रही है जो वह देशभर में कर रही है। भावनात्मक मुद्दे उठाकर वास्तविक समस्याओं से ध्यान हटाना और अपनी सरकारों की असफलताओं और असंवैधानिकताओं को संकुचित, संकीर्ण क्षेत्रीयतावाद के झीने आवरण में छुपाना। कुछ लोगों, खासकर उन लोगों के लिए जो भाजपा के एक राष्ट्रवादी पार्टी होने के मार्केटिंग वाले जुमले में थोड़ा बहुत यकीन

क्षेत्रीयतावादी उन्माद भड़काने का आरोप

करते हैं, यह अजीब लग सकता है। किंतु इसमें न कुछ नया है न अप्रत्याशित।

भारत के बारे में उनकी समझदारी ही औंधी है। संविधान के फेडरल (संघीय) ढांचे में उनका विश्वास नहीं है। विविधताओं के समन्वय और मेल में उनका यकीन नहीं है। जिस ऊंच-नीच की धारणा वह समाज पर लागू करते हैं वही विषमता और दुराव की समझ उनकी प्रदेशों यहां तक कि प्रदेश के अलग-अलग अंचलों के बारे में है। राष्ट्र की संघी अवधारणा भी मनुस्मृति की भौड़ी व्याख्या पर टिकी हुई है।

गुजरात की जीत से अत्यंत प्रसन्न भाजपा ने संभवतः राजस्थान के लिए अधोषित रूप से निर्णय ले लिया है कि विधानसभा का अगला चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। तर्क यह है कि विधानसभा चुनाव के तत्काल बाद ही लोकसभा चुनाव होंगे, जिसके लिए जरूरी है कि चेहरा तो मोदी का ही हो। माना कि मोदी के चेहरे पर चुनाव हो भी जाएगा, तो क्या वसुंधरा राजे को दरकिनार करने में भाजपा सफल हो जाएगी? फिलहाल यह कहना मुश्किल है। राजस्थान की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जैसे अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाकर सचिन पायलट को बनाने की कांग्रेस आलाकमान की कोशिश गहलोत की ताकत के सामने असफल रही, भाजपा में भी राजे को दरकिनार करना वैसे ही फेल हो सकता है। राजस्थान की राजनीति में भाजपा के अगले मुख्यमंत्री की तस्वीर जितनी साफ, सरल और आसान तरीकों से देखने की कोशिश हो रही है, उतनी आसान असल में है नहीं। राजस्थान भाजपा की ताजा तस्वीर बहुत उलझन, असमंजस और अनिर्णयों से भरी है। मोदी के चेहरे की चमक के बहाने जिन वसुंधरा राजे को मुख्य किरदार से दरकिनार करने की कोशिश हो रही है, उनको राजस्थान में नजरअंदाज करना भाजपा के लिए इतना आसान खेल भी नहीं है।

वसुंधरा राजे भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष, दो बार मुख्यमंत्री रही हैं और भाजपा के वर्तमान 71 विधायकों में से 40 पर उनकी गजब पकड़ होने के साथ-साथ प्रदेश की जनता, खासकर महिलाओं और युवा वर्ग में तो उनकी वो जबरदस्त अपील है, जो किसी और की है नहीं। फिर हर जिले में उनके अपने लोग हैं और जिलों में मजबूत नेता सबसे ज्यादा उन्हीं के साथ हैं। लोकप्रियता के मामले में भी प्रदेश का कोई और नेता राजे के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता। भाजपा और उसके नेता वसुंधरा राजे की ताकत के तेवर तब से जानते हैं, जब वह पहली बार राजस्थान की मुख्यमंत्री थीं। उन्होंने साफ शब्दों में संदेश दे दिया था कि होंगे राजनाथ सिंह पार्टी के अध्यक्ष, लेकिन वे किसी और के कहने पर अपनी राजनीति नहीं चलाती। खासकर राजस्थान के मामलों में तो निर्णय उनकी इच्छा से ही होंगे। बात तब की है, जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर राजनाथ सिंह ने राजस्थान भाजपा में राजे की सहमति के बगैर अकारण और अप्रत्याशित हस्तक्षेप करके वसुंधरा समर्थक नेता महेश चंद्र शर्मा को हटाकर ओमप्रकाश माथुर को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था। वसुंधरा ने इसे लगभग व्यक्तिगत राजनीतिक हमला माना था और इतनी नाराज हुई थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ का फोन आया तो उनको कहलवा दिया था कि वे उनसे बात नहीं करना चाहती।

सन् 2018 में भी राजस्थान में विधानसभा



किसके चेहरे पर चुनाव ?

उपलब्धियां गिनाकर नहीं जीता जा सकता चुनाव

भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व मानता है और यह जानता भी है कि राजस्थान कोई ऐसा प्रदेश नहीं है, जहां उप्र, बिहार, झारखंड या उड़ीसा की तरह गरीबी व भुखमरी को आसानी से वोटों में भुनाया जा सके। मोदी जानते हैं कि यहां की प्रजा को उज्वला योजना, जनधन खातों और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी सरकारी योजनाओं के लाभार्थी के रूप में फायदे गिनाकर चुनाव नहीं जीता जा सकता है। फिर, वसुंधरा की मोदी और शाह से कितनी जमती है या बनती है, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तीनों की अपनी-अपनी टस्क है। लेकिन राजस्थान में भाजपा की असली परीक्षा कुछ वक्त बाद होगी, जब विधानसभा चुनाव सिर पर होंगे और वर्तमान गहलोत सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी भुनाने के लिए कोई सर्वमान्य चेहरा चाहिए होगा। वैसे, तो वसुंधरा राजे को आगे रखे बिना यह इतना आसान नहीं होगा और आगे किया तो मुश्किलें क्या-क्या होंगी, इसका आंकलन भी किया जा रहा है। फिर भी राजे को दरकिनार करके मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ना होगा, तो बाकी राज्यों के चुनाव की चिंता छोड़कर अमित शाह को यहां 6 महीने पहले से आकर डेरा डालना होगा और मोदी को हफ्ते के हिसाब से हर सात दिन में दौरे करने होंगे। फिर भी गहलोत सरकार से पार पा ही लेंगे, कहना मुश्किल है।

चुनाव से ऐन पहले भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह चाहते थे कि केंद्र में राज्यमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जयपुर भेजा जाए, लेकिन वसुंधरा सरकार के 20 से ज्यादा मंत्रियों और 20 विधायकों ने केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली के दरवाजे खटखटाए और शेखावत को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से राजस्थान में जाटों की नाराजगी बढ़ने का हवाला देकर निर्णय रुकवा दिया। मगर, उन दिनों न तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर भाजपा व संघ परिवार की आभा पर सवार थे, और न ही अमित शाह आज जितने ताकतवर। अब भाजपा बहुत बदल गई है और फिर वसुंधरा राजे भी पहले जितनी ताकतवर नहीं रहीं। फिर भी, जून 2020 में सचिन पायलट द्वारा अपनी ही कांग्रेस पार्टी की सरकार व अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तख्तापलट की कोशिश हुई, तो उसे गहलोत के हक में असफल करने में वसुंधरा ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर अपनी बची-खुची ताकत का अहसास कराया, भाजपा उसी को लेकर चिंतित है। वसुंधरा के मामले में पार्टी इसीलिए बेहद सावधानी बरत रही है।

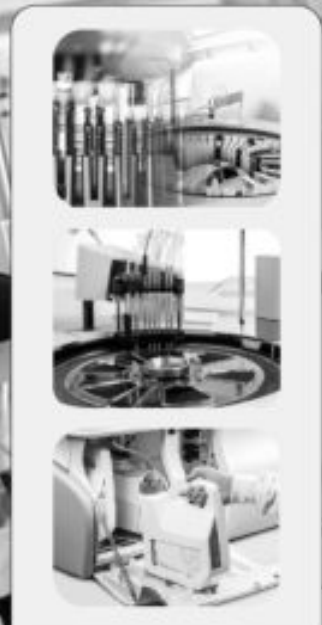
दिग्गज नेता भैरोसिंह शेखावत अब इस लोक में नहीं है, फिर भी राजस्थान की राजनीति में उनके

नाम और सम्मान की हैसियत किसी भी जीवित नेता के मुकाबले बहुत ज्यादा मानी जाती है। लेकिन शेखावत के निधन के बाद सतीश पूनिया, ओम बिड़ला, राजेंद्र राठोड़, गुलाबचंद कटारिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, राज्यवर्द्धन राठोड़, ओम माथुर व ऐसे ही कुछ और दिग्गज नेताओं की लंबी-चौड़ी फौज होने के बावजूद भाजपा के नेता के रूप में पूरे प्रदेश में समान रूप से स्वीकारोक्ति वसुंधरा राजे की ही सबसे ज्यादा है। राजस्थान की खास बात यह है कि यहां की राजनीतिक तासीर जातियों की जकड़न में कैद है, और जिनमें जाट, राजपूत, ब्राह्मण, गुर्जर और मीणा सबसे ताकतवर जातियां हैं। प्रदेश की राजनीति इन्हीं जातियों के इर्द-गिर्द चक्कर काटने को मजबूर है। राजस्थान की जनता जानती और मानती है कि जातियों की इस जकड़न में सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर, भाजपा में वसुंधरा राजे का कोई तोड़ नहीं है। प्रदेश में समान रूप से सभी इलाकों व मजबूत जातियों में जनाधार राजे की सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी है। लेकिन यह अलग मुसीबत है कि भाजपा की अगली पीढ़ी के नेता वसुंधरा के बजाय खुद को बड़ा नेता मानने लग गए हैं।

● जयपुर से आर.के. बिन्नानी

ANU SALES CORPORATION

We Deal in
Pathology & Medical
Equipment



Address : M-179, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

☎ 9329556524, 9329556530 ✉ Email : ascbhopal@gmail.com

क्या गुल खिलाएंगे पीके ?



प्रशांत किशोर अपने सामने किसी की नहीं चलने देते

प्रशांत को जानने वाले ही बताते हैं कि वह सुनते सबकी हैं लेकिन अपने सामने चलने किसी की नहीं देते। अपने इसी स्वभाव के कारण वे कांग्रेस के साथ काम नहीं कर पाए और इसी स्वभाव की वजह से भाजपा और जदयू से उनके रिश्ते खराब हुए। प्रशांत किशोर के आधा दर्जन साक्षात्कारों को सुनते हुए यह कई बार लगा कि अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर की राजनीतिक यात्रा की पटकथा किसी एक ही व्यक्ति ने लिखी है। फिर भी प्रशांत किशोर की राजनीतिक यात्रा पर किसी तरह की भविष्यवाणी करना इस समय जल्दबाजी होगी हालांकि इस यात्रा को प्रारंभ करने के लिए उनके पास समय बहुत कम है। शेष बिहार वालों के लिए यह देखना दिलचस्प होगा कि वे अपने सारे पते 2024 में खोलते हैं या फिर 2025 में, वे बिहार में कोई बड़ा परिवर्तन लेकर आते हैं।

प्रशांत किशोर अब तक पूरे देश में एक जाना पहचाना नाम बन चुके हैं। एक अंग्रेजी अखबार के ऑनलाइन साक्षात्कार में पत्रकार ने उन्हें बताया कि उनको सुनने और पढ़ने वालों में सिर्फ हिंदी पट्टी के लोग ही नहीं हैं। उनके साक्षात्कारों को दक्षिण भारत में भी खूब पसंद किया जा रहा है। प्रशांत को लोग सुनना चाहते हैं। ऐसे में जब वे लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि बिहार का विकास कोई सपना नहीं है। वह सच हो सकता है तो बिहार के लोग इस बात पर विश्वास करना चाहते हैं। उन पर लोग विश्वास करें इसके लिए आवश्यक है कि उनके कहे में स्पष्टता हो। जब उनसे पूछा जाता है कि वे खुद को सामाजिक कार्यकर्ता मानते हैं, राजनेता, या फिर चुनावी विश्लेषक तो इस सवाल के जवाब में वे अक्सर उलझ जाते हैं। जवाब देते हुए ऐसा लगता है कि वे खुद भी अपने जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। पिछले दिनों जब एक पत्रकार ने प्रशांत से पूछा कि क्या है प्रशांत किशोर? बिहार में सत्ता की आहट टटोलने वाली महत्वाकांक्षी राजनीति के लिहाज से अभी युवा नेता? इस प्रश्न के जवाब में प्रशांत ने कहा- आप मुझे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कहें। नेता तो जनता बनाएगी। यदि बनाएगी तो।

वे बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था लाने के सपने के साथ कुछ साल लगाने के लिए आए हैं। उनकी नई राजनीतिक व्यवस्था तीन मूलभूत बातों पर आधारित होगी। सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। जब विकास की प्रतिस्पर्धा में पूरा देश आगे की तरफ भाग रहा था। नीतीश जी के सुशासन के बावजूद बिहार सबसे पीछे क्यों रह गया? आज के दौर में जब यह सवाल नीतीश कुमार से किया जाए तो वे इसकी जिम्मेवारी राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद पर नहीं डाल सकते। बिहार के इस अंधकारमय वातावरण में यही सवाल है जो प्रशांत किशोर के लिए जगह बना रहा है। इस समय बिहार में जितने भी सक्रिय राजनीतिक दल हैं, सभी कभी ना कभी सत्ता में रहे हैं। अब उनके द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर बिहार के लोग बहुत विश्वास नहीं करेंगे। पलट कर सवाल जरूर कर सकते हैं कि जब तुम सत्ता में थे तो क्या किया? प्रशांत जानते हैं कि महात्मा गांधी, राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, नानाजी देशमुख से लेकर अन्ना हजारे तक की परंपरा में एक बात समान थी। इन सबने सत्ता से खुद को दूर रखा। भारतीय समाज में त्याग करने वालों का मान बहुत है। इसका लाभ दिल्ली की राजनीति में केजरीवाल ने उठाया, जो भारतीय समाज के बीच झोला लेकर आंदोलनकर्मी बनकर आए।

गांधीवादी अन्ना हजारे के साथ केजरीवाल ने संकल्प लिया था कि सक्रिय राजनीति में कभी हिस्सा नहीं लेंगे। जब समाज का विश्वास हासिल कर लिया, उसके बाद अन्ना को हाशिए पर

डालकर सक्रिय राजनीति में उतर गए। प्रशांत इस बात को समझते हैं लेकिन जब वे मंच से इस बात को स्वीकार नहीं पाते तो उनके अपने कार्यकर्ता भ्रमित होते हैं। इसलिए वे कई बार प्रशांत किशोर और उनके अभियान से जुड़े सवालों का जवाब नहीं दे पाते और एक-एक व्यक्ति तक प्रशांत का पहुंचना संभव नहीं है। इसलिए वे जिस भी उद्देश्य के साथ बिहार के मैदान में उतरे हैं और सड़कों की खाक छान रहे हैं। वह स्पष्ट होना चाहिए और उसमें किंतु-परंतु कम से कम होना चाहिए। नब्बे के दशक में जब बिहार में लालूजी का शासन आया। वह बूथ लुटेरों का दौर था, जो नेताओं के लिए बूथ लूटते थे। बाद में इन बूथ लूटने वाले डकैतों को लगा कि जब हम बूथ लूटकर नेता को विधायक, सांसद, मंत्री बना सकते हैं तो खुद अपने लिए बूथ क्यों ना लूटे? यह भारतीय राजनीति के अपराधीकरण और बिहार की राजनीति के लालूकरण का दौर था। तब राजनीति में आने के लिए साफ सुथरी छवि की अनिवार्यता खत्म होने लगी। जिस पर जितने अधिक मुकदमे। वह उतना ही योग्य उम्मीदवार। बहरहाल, बूथ लुटेरों के बाद अब चुनावी रणनीतिकारों और विश्लेषकों के राजनीति में उतरने का समय है। उन्हें भी लगता है कि वे चुनाव जिता सकते हैं तो जीत क्यों नहीं सकते? मैदान में उतरने वालों के सामने योगेंद्र यादव जैसा उदाहरण भी है, जो अपनी पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में उतरे और एक-एक सीट पर अपनी जमानत जब कराई। तब

शिगूफा खूब चला कि दूसरों की चुनावी जीत हार का खूब विश्लेषण करते थे और अपनी पार्टी का भविष्य नहीं देख पाए।

प्रशांत किशोर सावधान हैं। वे राजनीति में उतरने से पहले बिहार के लोगों को बता रहे हैं कि बिहार का पिछड़ापन तब तक खत्म नहीं होगा, जब तक बिहार के सच्चे और अच्छे लोग सामूहिक प्रयास ना करें। उनके इस प्रयास से ही बिहार के आगे का रास्ता बेहतर हो सकता है। अगला एक साल वे ऐसे लोगों की तलाश करने, उनसे मिलने और उन्हें एकजुट करने में लगाने वाले हैं, जिनकी रूचि बिहार के विकास में है। यह राजनीति में उतरने का केजरीवाल मॉडल है, जिसमें उतरने वाला पहले सामाजिक अभियान लेकर समाज के बीच में जाता है। राजनीति में सीधे उतरने से पहले वह बहाव के तापमान और धार का सही-सही अनुमान लगा लेना चाहता है। वह चाहे एक तरफ कह रहे हैं कि उन्हें राजनीति में नहीं उतरना। वे सिर्फ लोगों को एकत्रित कर रहे हैं। नेतृत्व लोग तय करेंगे लेकिन साथ ही साथ वे ये भी कह जाते हैं कि वे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और नेता उन्हें जनता बनाएगी। प्रशांत कहते हैं कि एक बार उनकी सोच से सहमत होने वालों का एक बड़ा समूह इकट्ठा हो गया फिर वे सभी तय करेंगे कि कोई राजनीतिक दल खड़ा करना है तो वह दल बनेगा। जिसका वे सिर्फ एक हिस्सा होंगे।

● विनोद बक्सरी

नेपाल में नई सरकार का गठन हो चुका है। 20 नवंबर को हुए संसदीय चुनाव के करीब 35 दिन बाद नई सरकार गठन के साथ पूर्वानुमानों पर अब विराम लग चुका है। एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में तय समय सीमा समाप्ती के अंतिम घंटे में पूर्व माओवादी नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इन्हें अन्य पांच दलों को मिलाकर कुल 165 सांसदों का समर्थन प्राप्त है।

नेपाल के 275 सदस्यीय सदन में इस चुनाव के दौरान किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिला है। वहीं चुनाव पूर्व के गठबंधन भी इन आंकड़ों से दूर थे। ऐसे में चुनाव बाद सरकार गठन को लेकर शतरंजी बिसातें बिछनी तय थीं। जिसमें बाजी महज 32 सीटों को जीतकर आने वाले प्रचंड ने मारी है। चुनाव पूर्व नेपाली कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा रहे प्रचंड अब पुनः एमाले के साथ हैं। इस नए गठबंधन में सरकार का नेतृत्व ढाई साल के लिए प्रचंड तो अगले ढाई वर्ष ओली के पास रहेगा। वामपंथी धड़े की पिछली सरकार में एमाले मुखिया ओली द्वारा समझौते के अनुसार प्रधानमंत्री पद नहीं छोड़ने के नाते प्रचंड अलग हुए थे। फिलहाल इस शह-मात के असली विजेता केपी ओली हैं। दरअसल इस बहाने उन्होंने न केवल सबसे बड़े संसदीय दल नेपाली कांग्रेस के सरकार बनाने की पहल को रोक दिया, बल्कि इस बहाने पुनः एक बार वामपंथी धड़ों को भी एकजुट किया है। वहीं इस सरकार की असली शक्ति इन्हीं के हाथ में रहनी है, क्योंकि इस सरकार के गठन के साथ ही राष्ट्रपति और स्पीकर का अहम पद ओली की पार्टी के पास रहना है। पिछली सरकार में इन पदों पर बैठे अपने प्रतिनिधियों द्वारा इन्होंने अपने मन की भरपूर चलाई थी।

वैसे इस सरकार की ओर से नियुक्त होने वाले राजदूतों में भी ओली के पसंद की चर्चा है। ऐसे में कुल मिलाकर नई सरकार के देश से विदेश नीति तक ओली प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। दरअसल इसका एक और कारण है। नेपाल के संसदीय चुनावों संग प्रांतीय सदन के चुनाव भी हुए हैं। यहां के सात प्रदेशों का दृश्य बिल्कुल केंद्रीय सदन सा है। कहीं किसी दल को बहुमत नहीं है। एमाले तीन प्रदेशों में आगे तो एक में कांग्रेस से महज एक सीट कम है। ऐसे में नेपाल के गैर कांग्रेस दलों द्वारा प्रदेशों में सत्ता सुख के एकमात्र पूर्तिकर्ता ओली ही हैं। जहां तक प्रधानमंत्री के तौर पर माओवादी नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड की सोचें तो यह उनकी तीसरी ताजपोशी है। इससे पूर्व 2008 से 2009 और फिर 2016 से 2017 तक वो इस पद पर सत्तासीन रहे हैं। भारत के इस पड़ोसी हिमालई राज्य में राजशाही के पतन और नवीन शासन व्यवस्था का कारण इनका माओवादी आंदोलन माना जाता है। वैसे एक माओवादी नेता के तौर पर इनके चीन से

नेपाल में नई सरकार



भारत की अपेक्षा चीन कहीं अधिक सफल

वैसे नेपाल की नई सरकार के गठन की घटनाक्रम को चीन भारत के हवाले से देखें तो फिलहाल चीन कहीं अधिक सफल है। उसने पिछले अनुभवों से सीखते हुए बिना किसी शोर अपने लिए कहीं अधिक अनुकूलता प्राप्त की है। इसके उलट भारतीय राजनयिक बेवजह सक्रिय दिख रहे थे। इस नाते चुनाव से लेकर चुनाव बाद तक की परिस्थितियों तक में यहां भारत को लेकर नकारात्मक खबरें चलती रहीं। वैसे चुनाव से सरकार गठन तक में पैन हान संग पैन इस्लाम की महती भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। बिना शोर इनका पूरा जोर रहा है। जिस नाते संख्या बल में नेपाल कांग्रेस प्रथम होकर भी सरकार से बाहर है, इसके मत प्रतिशत में भी गिरावट आई है जबकि वामपंथी दलों का मत प्रतिशत ज्यों का त्यों है। बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी का एकमुश्त वोट वाम दलों को गया है या फिर छद्म प्रगतिशील पहचान के साथ बनी रास्वपा जैसी नई पार्टी को मिला है। नेपाली मूल के अप्रवासी अमेरिकी पत्रकार रवि लामे छाने की इस पार्टी को नेपाल में तेजी से बढ़ रहे मुस्लिम ईसाई समुदाय का भी भरपूर मत मिला है। अब वे नई सरकार के गृहमंत्री हैं। इस सब के बीच उनकी नागरिकता पर सवाल है जिसकी सुनवाई अगले हफ्ते सर्वोच्च न्यायालय में होनी है।

जुड़ाव-लगाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के तौर पर इनके पूर्व कार्यकाल की पहली आधिकारिक यात्रा भी चीन की रही है। जबकि परंपराानुसार नेपाल के हर नए हुक्मरान पहली यात्रा भारत भूमि की ही करते रहे हैं। वैसे पिछली वामपंथी गठबंधन सरकार में ओली के प्रबल भारत विरोधी तेवर से दूरी और चीनी पहल बावजूद गठबंधन सरकार से समर्थन वापसी शायद बदलाव के संकेत हों। वैसे प्रचंड द्वारा लोकतांत्रिक कांग्रेस संग सरकार पिछली सरकार में होना और इस बीच दिल्ली की यात्राओं से भी उनके सोच में कहीं अधिक लचीलापन दिखता है।

अपनी दिल्ली यात्रा में इस हार्डकोर माओवादी नेता ने भाजपा जैसे भगवा पार्टी के दफ्तर जाकर चौंका दिया था। अब चूंकी वो सरकार के मुखिया हैं ऐसे में उनके द्वारा नेपाल में लोकतांत्रिक संस्थानों की मजबूती और भारत को लेकर उदार सोच ही बदलाव के वास्तविक वाहक होंगे। वैसे नेपाल में जन आकांक्षाओं की पूर्ति और पड़ोसी भारत-चीन संग एक संतुलित रिश्ते का तालमेल उनके लिए सफलता का पैमाना होगा, किंतु ये

इतना भी आसान नहीं है क्योंकि यहां हर बात भारत विरोध भड़कता और सीनों में पलता रहता है। ओली के प्रभाव के नाते भारत संग सीमा विवाद को हवा भी दी जा सकती है। वहीं चीन समर्थक वामपंथी धड़ों के सत्ता साझीदार होने के नाते पूर्व में बने एमिनेंट पर्सन गुप प्रस्तावों पर भारत को सहमति हेतु पुनः दबाव दिया जा सकता है। इसके अंतर्गत भारत नेपाल रिश्तों की डोर सन् 1950 की द्विपक्षीय संधि के समापन तथा सीमा पर बाड़ लगाने की योजना है। जहां लाखों नेपाली नागरिक भारत में सरकारी, निजी-नौकरी और व्यापार में हैं। वही यहां नेपाली भाषी नागरिकों की भी एक बड़ी आबादी है। अब तक दोनों देशों के नागरिक एक-दूसरे के यहां बे-रोक-टोक धार्मिक यात्राएं और विवाह करते रहे हैं। ऐसा होने से सीमा के दोनों ओर होने वाली सहज यात्राएं, विवाह और व्यापार सभी कुछ प्रभावित होगा। किंतु ओली समर्थन पर टिकी सरकार में प्रचंड कितना कुछ बदलाव ला पाएंगे और कितना कुछ इन व्यर्थ के विवादों को दूर रख पाएंगे फिलहाल कहना अधिक कठिन है।

● ऋतेन्द्र माथुर

HEIDELBERGCEMENT

149 वर्षों का अतुलनीय अनुभव



माईसेम सीमेन्ट की सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता, मज़बूती और टिकाऊपन के पीछे उसके विश्व प्रख्यात उत्पादनकर्ता जर्मन कंपनी हाइडलबर्ग सीमेन्ट का 149 वर्षों का अतुलनीय अनुभव है जो 50 देशों में लगातार सुनिश्चित करता आया है कि उसके द्वारा उत्पादित सीमेन्ट का हर कण गुणवत्ता के मापदंड पर खरा उतरे ताकि उनका नारा “सर्वोत्तम निर्माण के लिए” उसके ग्राहकों का विश्वास पात्र बना रहे।

क्योंकि जब सीमेन्ट की गुणवत्ता का सवाल हो,
तो सीमेन्ट का हर कण मायने रखता है..

माईसेम सीमेन्ट | सर्वोत्तम निर्माण के लिए

सस्ता सीमेन्ट या बढ़िया सीमेन्ट - फैसला आपका

For all licenses and BIS standards please refer to www.bis.gov.in
HeidelbergCement India Limited CIN: L20942HR1958FLC042301 Phone +91-124-4503700 e-mail - assistance@mycem.in

आज से कुछ साल पहले हम अक्सर मेड इन इंडिया शब्द सुनते थे लेकिन सन् 2014 के बाद से हमें मेड इन इंडिया की बनिस्बत मेक इन इंडिया के शब्द ज्यादा सुनाई देते हैं। मेड से मेक में हुए इस बदलाव के बीच भारत में क्या कुछ बदला है? मेड इन इंडिया के तहत यह अन्तर्निहित शर्त नहीं थी कि भारत में बेचना है तो भारत में बनाओ, जबकि वास्तविकता यह थी कि हम खुद ही अपने आप में एक बड़ा बाजार थे और हैं। अगर यह अन्तर्निहित शर्त पहले लगा देते तो भारत के पास क्रय शक्ति युक्त दुनिया का बड़ा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार होने के कारण जिसको भारत में सामान बेचना है वह यहां कारखाना लगाने को बाध्य होता। लेकिन 2014 से पहले मेक इन इंडिया की अन्तर्निहित शर्त नहीं होने के कारण कंपनियां विदेशों में माल बनाकर भारत में बेचा करती थीं। अब मेक इन इंडिया पॉलिसी और इसके तहत जो तमाम सुविधाएं और इंसेंटिव दिए गए तो कंपनियां भारत में बेचने के लिए भारत में ही अपना सामान बनाने लगीं।

इससे केवल उन्हें भारत का ही बाजार नहीं मिला बल्कि यहां का बना माल विदेशों में भी बेचने लगीं। भारत का जो आयात था वह कम होने लगा और उसी विदेशी तकनीकी से अब भारत में निर्मित होने लगा। धीरे-धीरे भारत वैश्विक निवेश का केंद्र बनना शुरू हुआ। सस्ता कच्चा माल, सस्ता श्रम, एक जीएसटी, कम दर वाला आयकर, डिजिटल और भौतिक इंफ्रा इन सबने मिलकर मेक इन इंडिया को सुगम बनाया। अब विदेशी कंपनियों के लिए भारत में माल बनाना सस्ता होने लगा। भारत सरकार को यह लगने लगा था कि भारत अगर बाहर से माल खरीदता रहेगा तो न भारत को प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता हासिल होगी और न भारत आत्मनिर्भर बन पाएगा। इसीलिए भारत सरकार ने मेक इन इंडिया के साथ-साथ आत्मनिर्भर भारत का अभियान भी शुरू किया। सबसे पहले टारगेट क्रिया डिफेंस को। भारत सरकार ने यह भी सोचा कि जब उनके सामान की बिक्री कन्फर्म है तो क्यों ना उन्हें बोलें कि भारत को बेचने वाला साजो सामान भारत में ही बनाओ। डिफेंस से हुई शुरुआत धीरे-धीरे कई क्षेत्रों तक जाने लगी, जिसमें मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक का बढ़ता हुआ बाजार प्रमुख है। इससे भारत में उत्पादन भी बढ़ा, रोजगार भी बढ़ा, और टैक्स के रूप में कमाई भी भारत सरकार को मिली। यह सब फीचर मेड इन इंडिया में सीमित रूप में थे। इसमें कोई अन्तर्निहित शर्त नहीं थी कि भारत में बेचना है तो भारत में बनाओ।

मेक इन इंडिया ने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने और चालू खाते का घाटा कम करने में भी मदद की, क्योंकि इस नीति से आयात की मात्रा कम हो गई। सरकार ने इसमें सहूलियत देने के लिए कुछ टैक्स और कानूनी सुधार भी किए ताकि मेक इन



मेक इन इंडिया के जरिए चीन को चुनौती

आर्थिक सुस्ती दूर होगी

कॉरपोरेट टैक्स की दर घटाने का अमेरिकी कारोबारियों ने भी स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे देश की और विश्व की भी आर्थिक सुस्ती दूर होगी और अमेरिकी कंपनियों को भारत में मैनुफैक्चरिंग गतिविधि बढ़ाने का एक नया अवसर मिलेगा। ज्ञातव्य हो कि अमेरिका भारत के सबसे बड़े एफडीआई निवेशकों में शामिल है। जहां तक वित्तीय घाटे का प्रश्न है इस टैक्स कटौती से राजस्व को होने वाले नुकसान से वित्तीय घाटा अधिक नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एक तरफ तो यह कटौती होगी दूसरी तरफ जीएसटी एवं आयकर दोनों कर चुकाने वालों का आधार बढ़ जाएगा। इससे राजस्व की वसूली बढ़ेगी। इस कदम से जो सबसे पहला फायदा है वह यह है कि इससे भारतीय कंपनियों में कैश फ्लो बढ़ेगा, जिसका इस्तेमाल कंपनियां अपने कर्ज को समायोजित करने और नौकरियां बढ़ाने या उसे स्थिर रखने में कर सकती हैं। वैश्विक स्तर पर अगर देखेंगे तो जो शीर्ष के 10 मैनुफैक्चरिंग देश हैं उनके यहां भी जो कर की प्रभावी दर है निर्माण कारखानों पर, वह अब हमसे ज्यादा हो गई है। मतलब चीन, यूनाइटेड किंगडम, कोरिया, इटली, जापान, फ्रांस आदि देशों के कॉरपोरेट इनकम टैक्स अब भारत के नए प्रभावी कॉरपोरेट इनकम टैक्स 17 फीसदी से ज्यादा हो गए हैं। ऐसी दशा में जो वैश्विक निवेशक हैं उनके लिए भारत निवेश के लिए अब नए विकल्प के रूप में सामने आया है। इसलिए मेड इन इंडिया से मेक इन इंडिया के नीतिगत बदलाव से भारत को दीर्घकालिक लाभ होगा।

इंडिया सफल हो। जैसे सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स रेट घटाकर देश ही नहीं पूरी दुनिया को चौंका दिया। कुछ चुनिंदा टैक्स को लेकर जो भारत की छवि दुनिया में बनी हुई थी वो अब बीते कुछ समय से खत्म हो रही है। कॉरपोरेट घरानों के लिए अब

भारत टैक्स टेररिज्म वाला देश नहीं रहा। निवेशकों को भी लगने लगा है कि अब वह दौर गया जब पिछली तारीख से टैक्स के कानून बदल जाया करते थे या गैर जरूरी टैक्स लाद दिए जाते थे। अब सब डिजिटल हो गया है। पूरे देश में एक जीएसटी लगाने से भी टैक्स की परिभाषाओं को समझने की जो सहूलियतें मिली उसका सबने स्वागत किया। भारत में घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की प्रभावी दर भी काफी कम हो गई। यदि कोई घरेलू कंपनी किसी प्रकार का प्रोत्साहन या छूट नहीं ले रही है, तो उनके लिए कॉरपोरेट टैक्स दर 22 फीसदी और यदि ले रही है तो लगभग 25 फीसदी के आसपास होगा। 22 फीसदी टैक्स का विकल्प चुनने वाली कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) नहीं देना होगा। नई घरेलू मैनुफैक्चरिंग कंपनी यदि कोई प्रोत्साहन या छूट नहीं ले रही है तो वह 15 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स दे सकती है। ऐसी नई कंपनियों के लिए सभी सरचार्ज और सेस लगाने के बाद नई मैनुफैक्चरिंग कंपनी के लिए टैक्स की प्रभावी दर 17.01 फीसदी ही होगा।

भारत के इस कदम से विश्व में भारत की टैक्स साख खूब बढ़ी है और वैश्विक मैनुफैक्चरिंग ट्रेंड भारत की तरफ मुड़ने की संभावना है जो मेक इन इंडिया के लिए अच्छा होगा। अभी चीन में कॉरपोरेट टैक्स की मानक दर 25 फीसदी है। यदि कोई कॉरपोरेट कंपनी चीन की सरकार द्वारा प्रोत्साहन के लिए चिन्हित क्षेत्रों में कारोबार करता है तो उसके लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर घटाकर 15 फीसदी की जा सकती है। हालांकि भारत में सभी नई मैनुफैक्चरिंग यूनिट को 15 फीसदी की दर दी गई है। चाइना की 15 फीसदी की दर काफी प्रतिबंधित है और वह चुनिंदा कंपनियों के लिए ही उपलब्ध होता है। चीन में इस प्रोत्साहन वाले क्षेत्रों में नई व अत्याधुनिक तकनीकी और कुछ खास एकीकृत सर्किट का उत्पादन ही शामिल है।

● कुमार विनोद

देश में खासतौर पर महिलाओं की तस्करी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। साल 2017 से 2021 के बीच देश में 16,51,809 महिलाएं गायब हुई थीं। इनमें से 8,66,571 महिलाओं का पता लगाया जा सका है। मतलब, केंद्र एवं राज्यों की विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियां 50 फीसदी लापता महिलाओं का सुराग नहीं लगा पा रही हैं। महिलाओं के गायब होने के मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, जबकि पश्चिम बंगाल का दूसरा नंबर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मौजूदा मानव तस्करी रोधी इकाइयों (एचटीयू) को सुदृढ़ करने के लिए निर्भया फंड के अंतर्गत 98.96 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसके बावजूद मानव तस्करी के मामलों की रफतार थम नहीं पा रही है। हाल ही में यह खबर सामने आई थी कि महाराष्ट्र में निर्भया फंड के तहत मिले 30 करोड़ रुपए से विधायकों के लिए वाहन खरीदे गए हैं।

साल 2017 के दौरान 18 वर्ष से अधिक आयु की 2,83,428 महिलाएं गायब हो गई थीं। इनमें से 15,359 महिलाओं का पता लगा लिया गया। 2018 में 3,06,733 महिलाएं गायब हुई थीं, जिनमें से 1,61,110 महिलाओं को ढूंढने में सफलता हाथ लगी। 2019 में विभिन्न राज्यों से 3,42,168 महिलाएं लापता हो गई थीं। इनमें से कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने 1,74,278 महिलाओं को खोज निकाला। 2020 में 3,44,422 महिलाएं लापता हुईं, जिनमें से 1,75,326 महिलाओं का पता लगा लिया गया। 2021 में 3,75,058 महिलाओं के गायब होने की सूचना मिली थी। इनमें से 2,02,298 महिलाओं को ढूंढने में सफलता मिली। केंद्रीय गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा ने संसद सत्र के दौरान पृष्ठे गए एक सवाल के जवाब में बताया, चूंकि संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य सूची के विषय हैं। ऐसे में मानव तस्करी के अपराध को रोकने और उससे निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है।

गृह मंत्रालय ने मौजूदा मानव तस्करी रोधी इकाइयों (एचटीयू) को सुदृढ़ करने तथा

	2017 2,83,428 महिलाएं गायब हुई, मिलीं मात्र 15,359	2018 3,06,733 महिलाएं गायब, केवल 1,61,110 मिलीं
	2019 3,42,168 महिलाएं हुई लापता, 1,74,278 को खोजा गया	
	2020 3,44,422 महिलाएं लापता हुई, 1,75,326 मिलीं	2021 3,75,058 महिलाएं गायब हुई, 2,02,298 मिलीं

8 साल पहले दिल्ली में घटित निर्भया कांड के बाद सरकार ने सबक लीते हुए लड़कियों और महिलाओं की रक्षा के लिए निर्भया फंड शुरू किया था। इस फंड से इनकी देखरेख करने के इंतजाम किए जा रहे थे। लेकिन इस फंड के बाद भी लड़कियों की तस्करी रुक नहीं रही है।

राज्यों व संघ क्षेत्रों के सभी जिलों को कवर करते हुए नए एचटीयू की स्थापना करने के लिए 2019-20 और 2020-21 के दौरान सभी राज्यों को निर्भया निधि के तहत 98.96 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की है। एचटीयू एकीकृत कार्यबल इकाइयां हैं, जिन्हें व्यक्तियों की तस्करी को रोकने और उससे निपटने तथा तस्करी के अपराध की जांच करने व अभियोजन चलाने का अधिदेश प्राप्त है। राज्यों और संघ राज्य प्रदेशों में कुल 768 एचटीयू स्थापित किए गए हैं। मानव तस्करी के पीड़ितों को बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों में एचटीयू की स्थापना के लिए सीमा रक्षक बलों, जैसे बीएसएफ और एसएसबी को अनुदान सहायता भी प्रदान की गई है। बीएसएफ और एसएसबी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में क्रमशः 15 और 5 एचटीयू स्थापित किए हैं।

इसके अलावा गृह मंत्रालय ने क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर (क्राई-मैक), राष्ट्रीय स्तर का संचार प्लेटफार्म लांच किया है। इसके अंतर्गत देश में मानव तस्करी के मामलों सहित बड़े अपराधों संबंधी सूचना का सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस अधिकारियों के बीच त्वरित (रियल टाइम) आधार पर प्रसार करने और उसे साझा करने की सुविधा भी प्रदान करता है। क्राई-मैक, विभिन्न अपराध से संबंधित कार्य को देख रहे पुलिस अधिकारियों के बीच अंतरराज्यीय समन्वय में सक्षम बनाता है। गृह मंत्रालय, मानव तस्करी से संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के नोडल अधिकारियों के साथ मिलकर काम करता है।

● ज्योत्सना अनूप यादव

थम नहीं रही मानव तस्करी

राज्य	महिलाएं गायब	पता लगाया
महाराष्ट्र	2,87,200	1,65,261
पश्चिम बंगाल	2,61,593	1,15,730
मध्यप्रदेश	2,40,506	1,02,256
दिल्ली	1,05,064	40,783
ओडिशा	97,834	37,104
राजस्थान	92,892	55,371
छत्तीसगढ़	73,467	32,810
तमिलनाडु	63,966	41,670
कर्नाटक	61,620	45,811
गुजरात	59,037	38,455

पूर्वोत्तर राज्यों में मौजूद 42 आश्रय गृह

गृह मंत्रालय समय-समय पर न्यायिक वार्तालाप और राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए राज्यों को वित्तीय मदद प्रदान करता है। इसका मकसद, न्यायिक और पुलिस अधिकारियों को मानव तस्करी से संबंधित कानूनों के नवीनतम प्रावधानों के बारे में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराना है। गृह राज्यमंत्री के मुताबिक, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि नए अनुमोदित मिशन शक्ति के तहत, तस्करी की रोकथाम के लिए कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लिए स्वाधारगृह और उज्ज्वला गृह का आपस में विलय कर दिया गया है। इनका नाम बदलकर अब शक्ति सदन हो गया है। यह एक एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह है। पूर्वोत्तर राज्यों में 42 आश्रय गृह हैं। इनमें से असम में 19, मणिपुर में 22 और मिजोरम में 1 आश्रय गृह शामिल है।

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.



D-10™ Hemoglobin Testing System For HbA_{1c}, HbA₂ and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and
diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; it's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or HbA₂/F/A₂ testing using primary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps. With the D-10™ System, it's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

Add:- C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 ✉ Email : shbple@rediffmail.com
☎ Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

पेले जैसा कोई नहीं!



पेले के निधन से सारी दुनिया उदास है! उन्होंने अपने चाहने वालों को आनंद के अनगिनत अवसर दिए! पेले के चाहने वाले कहते हैं कि वे महानतम थे। वे तीन बार जीती फीफा वर्ल्ड कप विजेता ब्राजील टीम के सदस्य रहे। वे दो बार उन ब्राजील की टीमों में रहे। उन्हें साल 2000 में फीफा फ्लेयर आफ द सेंचुरी का भी सम्मान मिला। पर क्या पेले को मुख्य रूप से इसी आधार पर सर्वकालिक महानतम खिलाड़ी माना जाए क्योंकि वे तीन बार जीती ब्राजील टीम में सदस्य थे? वे 1958 में ब्राजील की टीम में थे। वे तब मात्र 17 साल के थे। वैसे वे 1962 और 1966 के वर्ल्ड कपों में चोटिल होने के कारण कोई खास जौहर नहीं दिखा सके थे। हां, 1970 के वर्ल्ड कप में वे अपने पीक पर थे। पर उस टीम के बारे में कहा जाता है कि वो वर्ल्ड कप में अब तक खेलेली महानतम टीम थी। वो टीम वैसे कहा जाए तो पेले के बिना भी वर्ल्ड कप जीतने की कुव्वत रखती थी। उस टीम में गर्सन, टोस्टओ, रेविलिनिओ और जेरजिन्हो जैसे महान फारवर्ड खिलाड़ी थे। ये किसी भी टीम की रक्षा पंक्ति को भेद सकने वाले महान खिलाड़ी थे।

एक बात समझी जाए कि फुटबॉल का मतलब बड़ी शॉट खेलना कतई नहीं है। बड़ा खिलाड़ी तो वो ही होता है, जो डिबलिंग करने में माहिर होता है। उसे ही दर्शक देखने जाते हैं। इस लिहाज से पेले बेजोड़ रहे हैं। खेल के मैदान में पेले के दोनों पैर चलते थे। उनका हेड शॉट भी बेहतरीन होता था। पेले के 1970 में इटली के खिलाफ फाइनल में हेडर से किए गोल को जरा याद करें। उस गोल के चित्र अब भी यदा-कदा देखने को मिल जाते हैं। वैसे, उस फाइनल में एक गोल कार्लोस एलबर्टो ने पेले की ही पास पर किया था। अगर गेंद उनके बाएं पैर पर आ गई उनका गेंद पर नियंत्रण और विरोधी खिलाड़ी को छकाने की कला दुबारा देखने को नहीं मिलेगी। पेले के बारे में विरोधी टीम को पता ही नहीं चलता था कि वे कब अपनी पोजिशन चेंज कर लेंगे। वे मैदान में हर जगह मौजूद रहते थे। पेले की लाजवाब डिबलिंग कला थी। उनका अपनी टीम पर गजब का प्रभाव था। हां, पार्सिंग और रफ्तार में दोनों का कोई सानी नहीं हुआ।

पेले ने अपने कैरियर में 760 गोल किए जिनमें से 541 लीग चैम्पियनशिपों में किए गए थे, जिसके कारण वे सर्वकालीन सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी माने जाते हैं। कुल मिलाकर पेले ने 1363 खेलों में 1281 गोल किए। हालांकि इनके आंकड़ों को चुनौती भी मिलती है। पेले खुद ही गोल करने के लालच में नहीं रहते थे। वे साथी खिलाड़ियों को गोल करने के बेहतरीन अवसर भी देते थे। वे बड़े और अहम मैचों में छा जाते थे। वे छोटी-कमजोर टीमों के खिलाफ अपने जौहर नहीं दिखा पाते थे। अगर बात मैदान

से हटकर करें तो पेले फुटबॉल के मैदान को छोड़ने के बाद सामाजिक कार्यों से जुड़ गए। ब्राजील में करप्शन से लेकर गरीबी के खिलाफ लड़ते रहे। पेले को 1992 में पर्यावरण के लिए संयुक्त राष्ट्र का राजदूत नियुक्त किया गया। उन्हें 1995 में खेलों की दुनिया में विशेष योगदान के लिए युनेस्को सद्भावना राजदूत बनाया। पेले ने ब्राजीली फुटबॉल में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए एक कानून प्रस्तावित किया, जिसे पेले कानून के नाम से जाना जाता है। माराडोना ने पेले की तरह का कोई सामाजिक आंदोलन से अपने को नहीं जोड़ा।

पेले का कद इतना ऊंचा था कि उनसे अमेरिका के राष्ट्रपति भी आदर से मिलते थे। उनका बचपन अभावों में गुजरा। पेले बेहद शांत और विनम्र थे। पेले के भारत में भी करोड़ों फैंस हैं। वे दो बार भारत आए। वे भारत को प्रेम करते रहे। वे पहली बार जब कोलकाता आए थे तो देर रात को एयरपोर्ट पहुंचने पर भी हजारों फैंस ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया था। वे जब भी यहां आए तो भारत के फुटबॉल फैंस ने उन्हें भरपूर स्नेह और सम्मान दिया। पेले 1977 में भारत आए थे। पेले कोलकाता (तब कलकता) में एक प्रदर्शनी मैच खेलने आए थे। वे तब काज्मोस क्लब से जुड़े हुए थे। काज्मोस का एक मैच ईस्ट बंगाल के साथ रखा गया था। मुकाबला बराबर रहा था। बंगाली भद्रलोक पेले को खेलता देखकर अभिभूत थे। धन्य महसूस कर रहे थे। पेले का पीक तब तक नहीं रहा था।

पेले ने कभी अपने चमत्कारी खेल का प्रदर्शन दिल्ली में नहीं किया! पर वे साल 2015 में दिल्ली आए थे। वे सुब्रत कप के फाइनल मैच के मुख्य अतिथि थे। पेले ने फाइनल मैच को देखा था। उन्हें देखने के लिए अंबेडकर स्टेडियम

खचाखच भरा हुआ था। उन्होंने फाइनल मैच के बाद एक खुली जीप पर सारे स्टेडियम का चक्कर लगाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया था। पेले ने वहां पर मौजूद दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा था, मैं सुब्रतो कप में हिस्सा बनकर बहुत खुश हूँ। मुझे भारत के युवा फुटबॉल खिलाड़ियों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। वे उम्र दराज होने पर भी बिल्कुल फिट लग रहे थे। भारत महिला फुटबॉल टीम के कोच रहे अनादि बरूआ को याद है वह दिन जब पेले को देखने अंबेडकर स्टेडियम में सभी उम्र के हजारों फुटबॉल प्रेमी पहुंचे थे। हालांकि सुरक्षा कारणों के चलते वे किसी को ऑटोग्राफ नहीं दे सके थे!

पेले को 2015 में दिल्ली में लाने का श्रेय भारतीय वायुसेना को ही जाता है! पेले ने फाइनल को देखने आए दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा था, मैं भारतीय वायुसेना की कड़ी मेहनत से प्रभावित हूँ। सुब्रतो कप का सफल आयोजन भारतीय वायुसेना ही करती है। चूँकि एयर चीफ मार्शल सुब्रत मुखर्जी फुटबॉल में गहरी दिलचस्पी लेते थे, इसलिए उनके नाम पर यह चैंपियनशिप चालू हुई थी। सुब्रतो मुखर्जी भारतीय एयरफोर्स के पहले प्रमुख थे। वे 1 अप्रैल 1954 को भारतीय वायुसेना के पहले प्रमुख बनाए गए थे। उनको फादर ऑफ द इंडियन एयर फोर्स कहा जाता है। सुब्रतो मुखर्जी बंगाल के एक प्रमुख परिवार से थे। उनके पिता सतीश चंद्र मुखर्जी आईसीएस अफसर थे। सुब्रत मुखर्जी 1932 में वायुसेना में शामिल हुए। पेले को दुनिया सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में से एक रूप में याद रखेगी! उनका कद इतना ऊंचा हो गया था कि वे अपने जीवनकाल में ही किसी दंतकथा का पात्र बन गए थे!

● आशीष नेमा



करीना की एक ना से जागा अमिषा का भाग्य

झोली में गिरे थे 92 अवॉर्ड

करीना कपूर ने 2 दशकों तक बॉलीवुड में राज किया है। आज भी देशभर में करीना कपूर को लाखों लोग पसंद करते हैं। करीना अपने डेब्यू के समय से ही मीडिया की सुर्खियों में रहीं हैं। करीना ने साल 2000 में रेपयूजी फिल्म से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी थी। करीना के फिल्मी सफर की शुरुआत एक फ्लॉप फिल्म की जगह हिट फिल्म से हो सकती थी। लेकिन करीना के एक गलत फैसले ने उनके कैरियर की पहली सीढ़ी में दाग लगा दिया। करीना के पास मौका था ऋतिक रोशन के साथ कहो न प्यार से डेब्यू करने का। करीना ने ये फिल्म साइन भी कर ली थी। लेकिन मां की सलाह के चलते करीना को यह फिल्म छोड़नी पड़ी। बाद में ऋतिक रोशन के साथ करीना कपूर की जगह अमीषा पटेल को कास्ट किया गया। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इतना ही नहीं इस फिल्म ने कुल 92 अवॉर्ड अपने नाम कर एक रिकॉर्ड भी कायम किया है। करीना के मना करने के फैसले से अमिषा पटेल की किस्मत चमक गई।



शाहिद कपूर के प्यार में बदनाम हुई स्टारकिड, परिवार को मांगनी पड़ी थी एक्टर से माफी



फिल्मों में शाहिद कपूर लड़कियों के प्यार में पागल नजर आते हैं, पर असल जिंदगी में लड़कियां उन पर जान छिड़कती हैं। बॉलीवुड स्टार्स का क्रेजी फैंस से सामना होना आम बात है, पर शाहिद कपूर की एक फैन उन्हें जुनून की हद तक प्यार करती थीं। वे कभी अचानक उनकी कार के आगे आ जातीं, उनका रास्ता रोक लेतीं और अक्सर उनका पीछा करते हुए शूट तक पहुंच जातीं। जब उस फैन ने दीवार फांदकर शाहिद कपूर के घर तक पहुंचने की कोशिश की, तब यह एक तरफा प्यार शाहिद कपूर को जी का जंजाल लगा और उन्होंने मुंबई के वर्सोवा पुलिस थाने में उनकी शिकायत कर दी। यह फैन कोई मामूली लड़की नहीं थी, बल्कि अपने दौर के दिग्गज एक्टर राज कुमार की बेटी वास्तविकता पंडित थीं, जिन्होंने सुपरनैचुरल थ्रिलर 'एट' से बॉलीवुड डेब्यू किया था। शाहिद कपूर की परेशानी तब शुरू हुई, जब वास्तविकता उनकी बीलिंग के बगल में रहने चली आईं। वास्तविकता दावा करतीं कि वे शाहिद कपूर की बीवी हैं। वे अक्सर शूट तक उनका पीछा करतीं और उनकी बीलिंग के गेट पर उनके आने का इंतजार करतीं। खबरों की मानें, तो राजकुमार की बेटी शाहिद कपूर से पहली बार शामक डावर की डॉस क्लास में मिली थीं। उन्हें देखते ही वास्तविकता को उनसे प्यार हो गया था। तब मीडिया में खबर आई थी कि वास्तविकता की मां ने बेटी की हरकतों की वजह से शाहिद कपूर से माफी मांगी थी।

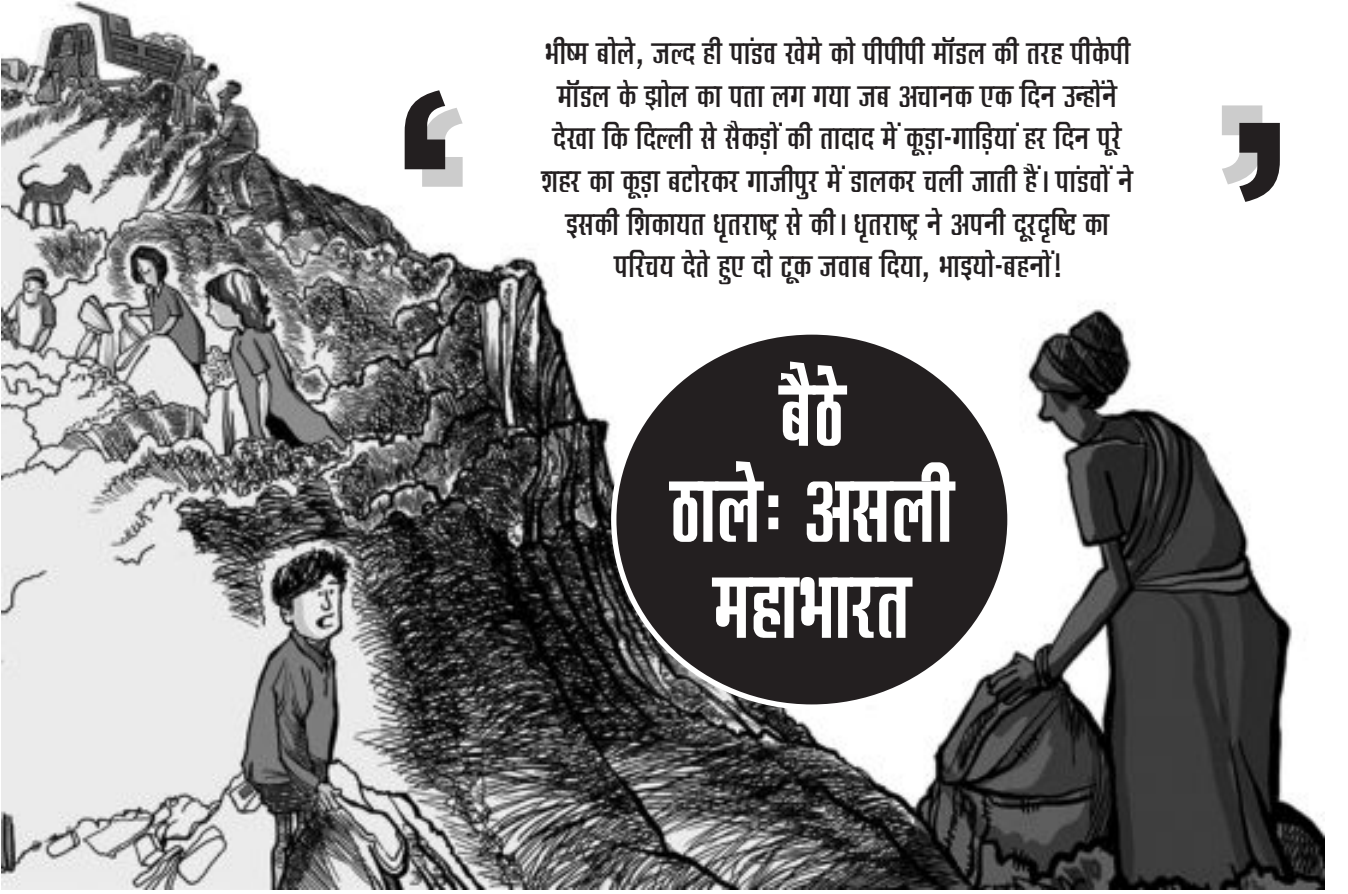
जब ममता कुलकर्णी ने शाहरुख और सलमान को हड़काया

राकेश रोशन के निर्देशन में बनी 'करण अर्जुन' की कहानी और स्टारकास्ट ने कुछ ऐसा रंग जमाया था कि साल 1995 में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बार सलमान खान और शाहरुख खान पर ममता कुलकर्णी बुरी तरह भड़क गई थीं। दरअसल 'करण अर्जुन' फिल्म में एक गाना है 'आजा-आजा भंगड़ा पा ले', इस गाने की शूटिंग का एक हिस्सा खत्म होने के बाद सब ब्रेक पर थे। शाहरुख खान और सलमान खान भी रेस्ट कर रहे थे तभी ममता कुलकर्णी ने सीटी मारकर दोनों को अपने पास आने का इशारा किया। पहले



तो इन्हें अंदाजा नहीं हुआ कि उन्हें इस तरह बुलाया जा रहा लेकिन इनके अलावा वहां कोई दूसरा था नहीं। जैसे ही दोनों ममता के पास पहुंचे ममता ने हड़काना शुरू कर दिया। ममता ने कहा कि इस गाने में मेरे स्टेप्स परफेक्ट जा रहे थे लेकिन तुम

दोनों की वजह से गाना खराब हो रहा है। कल आना तो पूरे रिहर्सल के साथ आना। सलमान और शाहरुख पर ममता की डांट का ऐसा असर हुआ कि रोज सुबह 5 बजे उठकर दोनों प्रैक्टिस करते और फिर सेट पर आते। फिर कुछ ऐसा हुआ कि पासा ही पलट गया। जब 'आजा-आजा भंगड़ा पा ले' गाने के आखिरी हिस्से की शूटिंग चल रही थी तो गाने की कोरियोग्राफर चिन्नी प्रकाश ने ममता कुलकर्णी से कहा कि 'ये दोनों लड़के बिल्कुल सही स्टेप्स कर रहे हैं, लेकिन आपके स्टेप्स गड़बड़ हैं।' इस पर सलमान-शाहरुख फख से एक-दूसरे को देखने लगे।



बैठे ठाले: असली महाभारत

शुक्रवार की शाम थी। छह बजते ही कौरव और पांडव दोनों पक्षों के सैनिकों ने अपना-अपना अस्त्र समेटा, बायोमेट्रिक में पंच-आउट किया और फिर कुरुक्षेत्र-मैदान मेट्रो स्टेशन की ओर दौड़ पड़े। मैदान में अब केवल घायल सैनिकों की हाय-हाय सुनाई पड़ रही थी। उन हाय-हाय में कोई एक था जो अपनी भरपूर आवाज में किसी को कोसता हुआ गालियां दे रहा था। यह भीष्म पितामह थे जो अर्जुन के तीरों से बिंध गए थे और कौरवों ने उन्हें 'मार्गदर्शक' मंडल में भेज दिया था। एक नन्ही सी परछाई घायल सैनिकों के बीच से रास्ता बनाते हुए उस आवाज की ओर बढ़ती जा रही थी। परछाई को देखकर भीष्म ने शिष्टता से पूछा, कौन है बे?

परछाई बोली, बाबा! मैं अभिमन्यु का बेटा परीक्षित हूँ। बाबा महाभारत का सीजन-वन मिस हो गया और अपने आपको बड़ा 'फोमो' महसूस कर रहा हूँ।

भीष्म ने बड़बड़ाते हुए कहा, सीजन वन में सब कुछ गलत दिखाया गया है। असली कहानी कुछ और ही थी। इतना कहते हुए भीष्म ने अपने स्मार्टफोन पर महाभारत चला दिया।

...धृतराष्ट्र का दरबार लगा है। कौरव और पांडव में जमीन का स्थापा चल रहा है।

धृतराष्ट्र कहते हैं, मितरों! पीपीपी यानी

भीष्म बोले, जल्द ही पांडव खेमे को पीपीपी मॉडल की तरह पीकेपी मॉडल के झोल का पता लग गया जब अचानक एक दिन उन्होंने देखा कि दिल्ली से सैकड़ों की तादाद में कूड़ा-गाड़ियां हर दिन पूरे शहर का कूड़ा बटोरकर गाजीपुर में डालकर चली जाती हैं। पांडवों ने इसकी शिकायत धृतराष्ट्र से की। धृतराष्ट्र ने अपनी दूरदृष्टि का परिचय देते हुए दो टूक जवाब दिया, भाइयो-बहनों!

पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप मॉडल की तर्ज पर मैंने पीकेपी या पांडव-कौरव-पार्टनरशिप का मॉडल ईजाद किया है जिसमें कौरव लोग हस्तिनापुर की सीमा पर बसे गाजीपुर नामक मनोरम गांव का इलाका पांडवों को दे दूँगे।

इतना सुनकर युधिष्ठिर समेत सभी पांडवों के आंखों के सामने रियल एस्टेट और मकानों के कतारों के चित्र घूम गए और पांडव खेमा खुशी से उछलने लगा। कौरव सेना धृतराष्ट्र के इस फैसले से बहुत नाराज हुई पर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को आंख मारकर खामोश रहने का इशारा किया।

भीष्म बोले, जल्द ही पांडव खेमे को पीपीपी मॉडल की तरह पीकेपी मॉडल के झोल का पता लग गया जब अचानक एक दिन उन्होंने देखा कि दिल्ली से सैकड़ों की तादाद में कूड़ा-गाड़ियां हर दिन पूरे शहर का कूड़ा बटोरकर गाजीपुर में डालकर चली जाती हैं। पांडवों ने इसकी शिकायत धृतराष्ट्र से की। धृतराष्ट्र ने अपनी दूरदृष्टि का परिचय देते हुए दो टूक जवाब दिया, भाइयो-बहनों! जिस प्रकार पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप मॉडल जनता का पैसा/लाला का मुनाफा के सिद्धांत पर टिका है, उसी प्रकार पांडव-कौरव-पार्टनरशिप मॉडल का मतलब है कि गांव अपनी जमीनें देंगे और शहर उस जमीन पर अपना कूड़ा डालेंगे।

देखते ही देखते गाजीपुर गांव में हस्तिनापुर का कूड़ा इकट्ठा होने लगा और जल्द ही वहां पर एक भरा-पूरा कूड़े का पहाड़ बन गया जहां रोज सैकड़ों की तादाद में गरीब परिवार कूड़ा बीनने लगे। वहां आवारा कुत्तों ने भी पैठ बना ली, यानी देखा जाए तो अपने आप में एक लहलहाता ईकोसिस्टम ही बन गया। पर जाने क्यों पांडव नाराज थे। उन्होंने एक बार फिर धृतराष्ट्र से अपील की पर धृतराष्ट्र अपनी बात पर अड़े रहे। अब ऐसे में जुआ खेलने के अलावा पांडवों के पास कोई चारा नहीं था। महाभारत की लड़ाई इसी वजह से शुरू हुई। यह इतिहास तुम्हें सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता।

इतना कहकर भीष्म चुप हो गए।

नन्हे परीक्षित ने पूछा, पर महाभारत का युद्ध तो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था और आप किसी गाजीपुर के कूड़े पहाड़ की बात कर रहे हैं?

भीष्म बोले, तुमने हस्तिनापुर के ट्रैफिक का हाल देखा है? पहले तो तय यही हुआ था कि महाभारत का युद्ध गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ पर लड़ा जाएगा पर ट्रैफिक जाम के चलते सैनिक लोग युद्ध क्षेत्र में समय से पहुंच नहीं पाते, इसलिए युद्ध का वेन्यू चेंज कर दिया। अब गाजीपुर के कूड़े पहाड़ पर युद्ध नहीं बल्कि एमसीडी के चुनाव लड़े जाते हैं।

● प्रमोद दीक्षित 'मलय'



नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री



सिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

माफिया के
कब्जे से छुड़ाई

23 हजार

एकड़ जमीन

बनेंगे गरीबों के लिये घर

भोपाल के नीलबड़ से हुई शुरुआत



SMILES TO A MILLION ENERGY SECURITY TO A BILLION



MCL

MAHANADI COALFIELDS LIMITED

(A Govt. of India Undertaking & Subsidiary of Coal India Limited)

Corporate Office: At/Po.- Jagruti Vihar, Burla, Sambalpur, Odisha-768 020

www.mahanadicoal.in



mahanadicoal



mahanadicoal